R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 06
16 से 31 दिसम्बर 2021
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

पुलिस कमिश्नर प्रणाली
पावर के साथ चुनौतियां भी

अपराधों पर नियंत्रण की कमान, अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी...

सबकुछ इन दोनों अफसरों पर

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

6 वर्ष शहरी परिवर्तन के...

अमृत योजना से हो रहा है शहरों का कायाकल्प

अमृत योजना के बेहतर क्रियान्वयन में अव्वल रहा मध्यप्रदेश

इस अंक में

पहल

8 | 2024 तक हर घर में नल से मिलेगा जल

आत्मनिर्भर मप्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हर घर नल जल योजना का कार्य तेजी से हो रहा है। प्रदेश के 54,903 गांव हैं, जिनमें से 40 हजार गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी...

राजपथ

10-11 | अब पंचायत चुनाव का घमासान

प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर होते हैं लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियों की हिस्सेदारी पूरी रहती है। इसलिए करीब 7 साल बाद होने वाले पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट...

विकास

12 | मप्र को 23 सड़कों की सौगात

विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहे मप्र में उच्च तकनीक की सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से मप्र को बड़ी सौगात मिली है। सीआरआईएफ (सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) योजना से मप्र...

अवैध खनन

15 | माफिया ने रोकी नर्मदा की धार

मप्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन का काला करोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज पर प्रदेश में रेत का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं लाइसेंस लेकर तो कहीं बिना लाइसेंस के अवैध खनन जारी है। रेत का यह अवैध...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

आखिरकार 40 साल बाद मप्र के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। इस प्रणाली के लागू होने से जहां पुलिस अधिक पावरफुल हुई है, वहीं उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। अब भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर पर जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधिकारों का तेजी और ताकत के साथ उपयोग करें और प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों की जनता के मन में विश्वास पैदा करें। राजधानी भोपाल व प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नरों...

राजनीति

30-31 | कांग्रेस मुक्त विपक्ष!

राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन ही ऐसा मुद्दा बचा है जिस पर विपक्ष साथ खड़ा है। अगर तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों के खिलाफ राज्यसभा सभापति की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया होता तो कांग्रेस के साथ ये दोनों पार्टियां तो नहीं ही नजर आतीं।

महाराष्ट्र

35 | शरद पवार की ख्वाहिशें...

शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे बिना फायदे के कोई कदम नहीं उठाते हैं। शरद पवार पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी कुछ ख्वाहिशें भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन ममता बनर्जी की सक्रियता उनकी राह में रोड़ा बनता...

राजस्थान

37 | गुटबाजी से त्रस्त है भाजपा...

राजस्थान भाजपा में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरह जहां राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं...

6-7 अंदर की बात
40 उप्र
41 विदेश
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

कोई तो पूछे क्या हाल है...उस गरीब के घर में

किसी शायर ने कहा है...

कोई तो पूछे क्या हाल है... उस गरीब के घर में
खाली पेट ही बदल रहे, महंगाई से करवटें बिस्तर में

भारत में बहुसंख्यक आबादी का हाल उपरोक्त पंक्तियों की तरह है। वजह है दिन पर दिन बढ़ती महंगाई। बेरोजगारी की वजह से कमाई का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, ऊपर से महंगाई ऐसी है कि लोग खाली पेट ही करवट बदल रहे हैं। आम लोगों के सामने पिछले करीब दो साल से कई तरह की मुश्किलें लगातार पेश आ रही हैं और उनके लिए अपने जीवन को सहज रख पाना एक चुनौती बनी हुई है। महामारी की मार के अलग-अलग रूपों ने रोजमर्रा की जरूरतों से भी समझौता करने के हालात पैदा कर दिए हैं। आय और खर्च का संतुलन इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि कई बार लोग लाचार भाव से बाजार की ओर देखते हैं। मसलन, आय में तेजी से गिरावट के साथ घटती क्रय-शक्ति या फिर बेरोजगारी में इजाफे के दौर में महंगाई ने लोगों के जीवन को किस स्तर तक प्रभावित किया है, उससे सभी वाकिफ हैं। जनता का ख्याल रखने का भरोसा देने वाली सरकारों को इस समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन हालत यह है कि एक ओर लोगों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भारी पड़ रहा है, दूसरी ओर लगभग सभी जरूरत की चीजों की कीमतें बेलगाम बढ़ती जा रही हैं। खासकर खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई ने लोगों को ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। पहले ही मुश्किल से जूझते लोगों को महंगाई के मोर्चे पर हाल ही में दो बड़े झटके और लगे हैं। खुदरा महंगाई दर में इजाफे के साथ ही थोक मूल्य सूचकांक ने भी चिंता बढ़ाई। अक्टूबर में जो खुदरा महंगाई दर 4.48 फीसदी थी, वहीं नवंबर में बढ़कर 4.91 फीसदी हो गई। यानी अमूमन हर महीने इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। खुदरा महंगाई ने औसत भारतीय परिवारों पर कैसा असर डाला है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब इसके बाद थोक मूल्य आधारित नवंबर में बढ़कर 14.23 फीसदी हो गई, जो अक्टूबर में 12.54 फीसदी थी। सरकार का कहना है कि मंहगाई की मौजूदा मुश्किल की वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो थोड़ी राहत का सबब बन सके। हालत यह है कि बहुत सारे साधारण परिवारों को अपनी थाली में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार में अनाज से लेकर सब्जियों और खाद्य तेल आदि खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें अब बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। सवाल है कि थोक और खुदरा महंगाई दर में इस हालत के बावजूद यह मसला सरकार की फिक्र में शामिल क्यों नहीं है! महामारी की मार का सामना करने के क्रम में टुकड़ों में लागू पूर्णबंदी के लंबा खिंचने के दौर में भारी ताादाद में लोगों को रोजी-रोटी से लाचार होना पड़ा। बाजार से लेकर उद्योग जगत में जैसी मंदी छाई, उसमें पूर्णबंदी के लगभग खत्म होने के बाद आज भी पहले जैसी सहजता नहीं आ पाई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि उस दौर में अपना छोटा-बड़ा कारोबार ठप होने से लेकर बेरोजगारी के आलम में आज भी कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। खाने-पीने जैसी अनिवार्य जरूरतों को छोड़ दें, तो लोग बहुत जरूरी होने पर ही कोई सामान खरीद पा रहे हैं। अब भी महामारी से मुक्त वक्त की संभावना काफी दूर दिख रही है, जिस वजह से लोग खर्च के मामले में कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं। ऐसे में अनिवार्य वस्तुओं की महंगाई ने लोगों की चुनौती दोहरी कर दी है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 6, पृष्ठ-48, 16 से 31 दिसंबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

aksnews.com

इंदौर फिर नंबर-1

स्वच्छता में इंदौर ने एक बार फिर झंडे गाढ़ दिए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार भी देशभर में अव्वल आया है। इसमें जितना योगदान नगर निगम के कर्मचारियों का है, उतना ही योजना इंदौर के रहवासियों का भी है। आगे भी हम इंदौर को स्वच्छता में नंबर-1 बनाते रहेंगे।

● **रानी सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

बिजली के लिए परेशान

सरकार के लाख दावों के बाद भी प्रदेश के कई किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। रबी फसलों की बुवाई के बाद से ही किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी समस्या का निदान करना चाहिए।

● **पंकज वर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

साफ-सफाई रखें

प्रदेश सहित देशभर में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार इतनी बढ़ती जा रही है कि सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों में बेड के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे समय में लोगों को अपने आसपास साफ-सफाई का ध्यान देना चाहिए।

● **हिमांशी साहू,** जबलपुर (म.प्र.)

चुनावी मोड में भाजपा

प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक वोट हासिल करने के बाद भी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, क्योंकि सीटों की संख्या कम थी। इसलिए पार्टी 2 साल पहले चुनावी मोड में आ गई है। अब भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए 2023 के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2023 में 200 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने के लिए भाजपा ने 51 फीसदी वोट पाने की कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के हर छोटे से छोटे क्षेत्र में जाकर प्रदेश सरकार की सफलताओं को बता रहे हैं।

● **पर्यन्त शर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

बाघों की मौत चिंताजनक

मप्र के जंगलों में आज भी खूंखार तस्करों का राज है, जो आदिवासियों को थोड़े से पैसे का लालच देकर बाघ या अन्य वन्य प्राणियों का शिकार करवाते हैं। वन विभाग-नेशनल पार्क के अफसरों, सफेदपोश लोगों, स्थानीय प्रशासन और तस्करों के गठजोड़ से मप्र में हर साल वन्य जीव तस्करी का अवैध कारोबार करीब 7500 करोड़ रुपए से अधिक का है। मप्र में इस साल अब तक 38 बाघों की मौत हो चुकी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।

● **सुनील सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

विपक्ष फिर कमजोर

कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों और समर्थकों, दोनों को चौंका दिया। विपक्षी दलों को लग रहा था कि किसान आंदोलन उनके लिए राजनीतिक एटीएम जैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस एटीएम को ही बंद कर दिया। अपने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिससे वे मोदी सरकार को घेर सके। एक बार फिर विपक्ष कमजोर स्थिति में है। कृषि कानूनों को वापस लेने के इस फैसले को किसी पक्ष की हार-जीत के रूप में देखा जाना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं परंपराओं के विरुद्ध होगा।

● **निशांत राजपूत,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

पंजाब में चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक तापमान खासा गर्मा गया है। इस बार मुकाबला कांग्रेस बनाम अकाली न होकर त्रिकोणीय हो चला है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बागी होकर अपनी अलग पार्टी बना डाली है जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का धुआंधार दौरा कर कांग्रेस की मुसीबतों में इजाफा कर रहे हैं। उनके निशाने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लेकिन केजरीवाल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सत्ता में बने रहने का पूरा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों केजरीवाल अपने साथ एक लाख बिजली के ऐसे बिल लेकर पंजाब आ धमके जिनमें दिल्ली के उपभोक्ताओं को कोई पैसा सरकार को नहीं देना है। यानी 'जीरो बिल।' केजरीवाल ने चन्नी को चुनौती देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ऐसे एक हजार बिल दिखा दे जिसमें पंजाब के उपभोक्ता को कुछ न देना हो। चन्नी ने इसके जवाब में केजरीवाल से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम जनता को बताने की बात कह डाली। गौरतलब है कि पंजाब में दिल्ली से 9 रुपया कम पेट्रोल-डीजल की कीमत है। चन्नी के इस वार से बिलबिलाए केजरीवाल ने तुरंत दिल्ली में दाम 8 रुपया घटा दिए। इसके बाद दिल्ली के स्कूलों का मुद्दा उठा।

राहुल के अजब-गजब फैसले

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर पार्टी के भीतर भारी असंतोष का माहौल है। राहुल स्पष्टवादी नेता हैं। उन्हें यदि कोई बात पसंद नहीं आती तो वे बगैर लाग-लपेट उसे कहने से नहीं चूकते। गत बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की करारी हार से नाराज राहुल ने खुलकर कह डाला था कि पार्टी के टिकट बेचे गए इसलिए नतीजा इतना खराब रहा। उनके इस बयान के बाद बिहार के प्रभारी रहे अविनाश पांडेय को हटा दिया गया था। लेकिन अब यकायक ही पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा सौंप दिया है। उनके साथ इस कमेटी की जिम्मेदारी विरेंद्र राठौड़ को दी गई है। हरियाणा के नेता राठौड़ स्वयं तीन बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले उन्हें गत दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली में कभी 15 बरस तक लगातार शासन करने वाली कांग्रेस का एक भी नेता चुनाव जीत विधानसभा नहीं पहुंच पाया। इस हार के बाद चर्चा गर्म रही थी कि टिकट वितरण में पैसा चला था। अब कुछ ऐसा ही उत्तराखंड के संदर्भ में कहा जाने लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता का मानना है कि गलत टिकट यदि दिए गए तो सत्ता के करीब पहुंच चुकी कांग्रेस का हश्र पिछले चुनाव जैसा होना तय है जब पार्टी को 70 में से मात्र 11 सीटें मिली थीं।

केसीआर की बढ़ती महत्वाकांक्षा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव इन दिनों अपने राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से खासे चिंतित बताए जा रहे हैं। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने राव का करिश्मा अब ढलान की तरफ जाता नजर आ रहा है। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में राव की पार्टी टीआरएस कांग्रेस को 119 सीटों में से 63 सीटें मिली थी। तब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मात्र 21 सीटें जीत दूसरे स्थान पर रही थी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सात सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। 2018 के चुनाव में टीआरएस कांग्रेस को 88 सीटें मिली, कांग्रेस की 19 सीटों पर जीत दर्ज हुई तो ओवैसी की पार्टी अपनी 7 सीटें बचा पाने में सफल रही। 2014 में भाजपा को तेलंगाना में पांच सीटें मिली थी। 2018 में उसे मात्र 2 सीटों की जीत पर संतोष करना पड़ा। अब लेकिन भाजपा का प्रभाव राज्य में बढ़ा है। गत नवंबर हुजुराबाद लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में गया। यहां से पार्टी प्रत्याशी की करारी हार ने मुख्यमंत्री राव की बेचैनी बढ़ा डाली है। अब तक के चंद्रशेखर राव केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने से कतराते आए हैं। संसद में भी टीआरएस कांग्रेस के सांसद विपक्षी दलों संग तालमेल करने से बचते रहते हैं।

ममतामय होंगे कई भाजपाई

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लक्ष्य अब 2024 के आम चुनावों में विपक्षी दलों का नेतृत्व करना साफ नजर आने लगा है। अपने इस अघोषित लक्ष्य को साधने के लिए दीदी बड़ा 'खेला' करने में जुट गई हैं। उनके निशाने पर न केवल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं, बल्कि भाजपा के कई बड़े नामों पर भी उनका फोकस बन चुका है। खबर गर्म है कि भाजपा आलाकमान की नजरों में गिर चुके भाजपा नेता इन दिनों ममता के संपर्क में हैं। ऐसे नेताओं में सबसे बड़ा नाम डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी का बताया जा रहा है। गत दिनों दिल्ली यात्रा पर आईं ममता ने स्वामी संग 'शिष्टाचार' भेंट कर इन खबरों को हवा देने का काम किया। खबर भाजपा सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर भी इन दिनों दिल्ली के सत्ता गलियारों में कही-सुनी जा रही है। तृणमूल सूत्रों की मानें तो भाजपा आलाकमान द्वारा इग्नोर किए जा रहे वरुण जल्द ही तृणमूल में शामिल होने जा रहे हैं।

बैकफुट पर फडणवीस

महाराष्ट्र की राजनीति में बतौर भाजपा नेता लंबे अर्से से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे देवेंद्र फडणवीस अब बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त फडणवीस का जलवा अब कम होने लगा है। प्रदेश की राजनीति में उनसे छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले भाजपा नेताओं की तरफ अब पार्टी आलाकमान का झुकाव बढ़ने लगा है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महामंत्री बनाए गए विनोद तावड़े से फडणवीस के रिश्ते बेहद खराब बताए जाते हैं। गत विधानसभा चुनावों में फडणवीस की मुखाल्फत के चलते तावड़े को टिकट तक नहीं मिल सका था। अब जेपी नड्डा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना डाला है। तावड़े का प्रमोशन सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर केंद्रीय नेतृत्व के कम हो रहे विश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, फडणवीस के एंट्री कैंप के अन्य बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले के दिन भी फिर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भी पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के कहने पर काट दिया था।

अहंकार की जंग

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों कमिश्नर प्रणाली के साथ ही दो महिला आईपीएस अधिकारियों के अहंकार की लड़ाई भी खासी चर्चा में है। भोपाल संभाग के करीबी संभाग में दो आईपीएस अफसरों के बीच हो रही लड़ाई को मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में चटखारे लेकर सुना और सुनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों महिला अफसरों में अहंकार की लड़ाई है। एक महिला अफसर के पास जोन की कमान है तो दूसरी आदिवासी बहुल जिले की पुलिस मुखिया हैं। दोनों के बीच लड़ाई की वजह क्या है, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आदेश-निर्देश को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई होगी। यहां यह बता दें कि जिले की कमान संभालने वाली आईपीएस अधिकारी काफी तेज तर्रार मानी जाती हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रशासनिक होने के कारण उनमें पहले से ही अकड़ रही है। सूत्र बताते हैं कि जबसे वे भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई हैं, तभी से उनका रुख और बदल गया है। आलम यह है कि वे अपने पूर्ववर्ती साथियों के साथ भी द्वेष का भाव रखती हैं। ऐसे में यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मैडम अपने वरिष्ठ अफसरों को कितना सम्मान देती होंगी। हालांकि भारतीय संस्कृति में यह प्रचलित है कि दो महिलाएं जहां भी रहेंगी उनमें अहंकार की लड़ाई तो छिड़ेगी ही। ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों पुलिस अधिकारियों के बीच कैसी रार मची होगी।

मंत्रीजी की चार बीवियां

प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में एक मंत्रीजी इन दिनों खासे चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि मंत्रीजी ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। मंत्रीजी ने यह रिकार्ड शादियों को लेकर बनाया है। अभी तक अधिकतम तीन बीवी वालों के बारे में सुना गया था, लेकिन इन मंत्रीजी की तो चार बीवियां हैं। इस खबर के सामने आने के बाद जब पड़ताल की गई तो यह उजागर हुआ कि मंत्रीजी की दो बीवियां राजधानी की शोभा बढ़ा रही हैं, वहीं एक बीवी उनके जिला मुख्यालय पर रहती हैं। जबकि एक बीवी उनके पैतृक गांव में रहती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मंत्रीजी ने चारों के साथ सामन्जस्य बनाए रखा है। इनमें से कौनसी बीवी वैधानिक है और कौन अवैधानिक यह तो मंत्रीजी ही जानते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी की नजर में चारों का सम्मान एक जैसा है। यहां यह बता दें कि मंत्रीजी मालवा-निमाड़ क्षेत्र से आते हैं। मंत्रीजी शुरू से ही शौकीन मिजाज के रहे हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि मंत्रीजी की शौकीन मिजाजी अभी भी कम नहीं हुई है। लोग कुछ भी कहें मंत्रीजी अपनी धुन के पक्के हैं। ऐसे में उनके करीबी चटखारे लेकर यह कहने से नहीं चूकते हैं कि भैया मंत्रीजी का मन डोला तो यह संख्या और बढ़ सकती है।

अधिकारों की लड़ाई

प्रदेश में जितने भी दुग्ध संघ हैं, वे भले ही घाटे में चल रहे हैं, लेकिन उनकी देखरेख करने वाले अधिकारी और ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। इसी मालामाल की रेस के कारण इन दिनों भोपाल दुग्ध संघ में दो अफसरों के बीच अधिकारों लड़ाई चल रही है। दरअसल, यहां पदस्थ एक राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने अधिकारी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए विभागीय मंत्री से अनुमोदन कराकर एक अधिकारी का तबादला कर दिया था। लेकिन यह बात विभाग के अपर मुख्य सचिव को नागवार गुजरी। उन्होंने आव देखा न ताव और उक्त अधिकारी का तबादला आदेश निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि जिस अधिकारी का तबादला निरस्त किया गया है, वे पूर्व में भी यहां से हटाए गए थे। दरअसल, इन साहब पर ठेकेदारों की अच्छी खासी मेहरबानी है। इनकी शिकायतें लगातार बड़े साहब के पास पहुंच रही है। शायद यही वजह है कि उन्होंने उनका तबादला निरस्त करवाया हो। लेकिन बड़े साहब ने एमडी के जिस आदेश को निरस्त किया है, खुद विभागीय मंत्री ने इसके लिए अनुमोदन किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री की अनुशंसा को निरस्त किया जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या इसके लिए मंत्री से दोबारा अनुमोदन कराया है। दरअसल, यहां अधिकारों को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, वह ठेकेदारी के कारण है।

अब ऑनलाइन ही दर्शन

कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन व्यवस्था ने ऐसा रूप ले लिया है कि अब हर कोई एक-दूसरे से ऑनलाइन ही मेल-मुलाकात की कोशिश करता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब तो सरकार भी ऑनलाइन के आदी हो गए हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार के मुखिया अब अपनी बातें फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफार्म से करते हैं। यही नहीं मीडिया को भी ऑनलाइन दर्शन देते हैं। जब भी जनता से कोई बात करनी होती है, अफसरों के साथ मीटिंग करनी होती है, तो माननीय ऑनलाइन हो जाते हैं और इस दौरान मीडिया को लिंक से कनेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे में मीडिया केवल श्रोता बनकर रह जाती है। इससे माननीय तो अपनी बात रख देते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से जनता की बात उन तक नहीं पहुंच पाती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि माननीय कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को ही अपनी बात बताते हैं और उसे लाइव करवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सोशल मीडिया पर ही अपनी बात कहते हैं। ऐसे में मीडिया से माननीयों की दूरी बढ़ती जा रही है।

लक्ष्मी कमाने में व्यस्त

वैसे तो प्रदेश में जो भी अधिकारी मालदार विभाग में पदस्थ होता है, उसका मुख्य ध्येय होता है कि अधिक से अधिक लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जाए। लेकिन इन दिनों आम जनता से जुड़े एक विभाग में पदस्थ एक प्रमोटी आईएएस और विभागीय मंत्री के ओएसडी जमकर कमाई करने में जुटे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रमोटी आईएएस जनवरी में रिटायर हो जाएंगे। इसलिए साहब ने अपना पूरा फोकस कमाई पर कर रखा है। साहब का भाग्य भी कुछ ऐसा है कि उन्हें जाते-जाते ऐसा विभाग मिल गया है, जहां उन्हें कमाने का मौका मिल गया है। वहीं उस विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रीजी के ओएसडी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे भी अगले साल रिटायर होने वाले हैं। इसलिए दोनों की पटरी भी जमकर बैठ रही है। अब दोनों अफसर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि रिटायरमेंट से पहले अपनी झोली भर ली जाए। भले ही सरकार का खजाना खाली रह जाए और जनता बेहाल हो जाए।

2024 तक हर घर में नल से मिलेगा जल

आत्मनिर्भर मप्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हर घर नल जल योजना का कार्य तेजी से हो रहा है। प्रदेश के 54,903 गांव हैं, जिनमें से 40 हजार गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग काम कर रहा है। लेकिन योजना के पूरा होने के बाद इसके संधारण और संचालन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसको लेकर गत दिनों मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की उपस्थिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत 40 हजार गांवों में नल से जल पहुंचाया जाना है। इसका काम तेजी से चल रहा है।

बैठक में इन 40 हजार गांवों में नल जल योजना के संधारण और संचालन पर भी विचार-विमर्श किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि 15 हजार गांवों में नल जल योजना का संधारण और संचालन लोक स्वास्थ्य विभाग करेगा और 25 हजार गांवों में यह जिम्मेदारी जल विकास निगम की होगी। बताया जाता है कि मुख्य सचिव ने दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तत्परता से जुट जाएं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हर घर नल जल योजना के तहत अब तक 5.71 लाख घरों को नल कनेक्शन दे चुके हैं, अब मप्र सरकार अगले 4 वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाएगी। मप्र में कुल 1.21 करोड़ घर हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण अंचल में घर-घर नल से जल पहुंचाया जाना है।

मप्र सरकार अगले चार वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना में 47,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च होगी। प्रदेश में कुल 1.21 करोड़ घर हैं। इनमें से अब तक महज 21 लाख घरों में सीधे नल कनेक्शन हैं। शेष आबादी अपने संसाधनों से पानी जुटा रही है। आत्मनिर्भर मप्र के तहत जल पर गठित सब कमेटी ने अपने एक्शन प्लान में यह बात कही है। अहम बात यह है कि इस एक्शन प्लान पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके तहत जारी वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 1.81 लाख घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया। दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 3.87 लाख घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया है कि कर्तव्य के प्रति इच्छाशक्ति से ही उद्देश्य की पूर्ति संभव हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की कुछ जल-प्रदाय योजनाओं को जल जीवन मिशन में शामिल कर अतिरिक्त राशि दिए जाने के निरंतर प्रयासों पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। श्रीवास्तव ने बताया कि इसी तरह जायका के ऋण से मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के ग्रामों में प्रस्तावित समूह योजनाओं को जल जीवन मिशन से वित्त पोषण के प्रयासों को भी सफलता मिली है। अब जल-प्रदाय की 2558 करोड़ लागत की समूह योजना के लिए भी भारत सरकार ने 1279 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि 2024 तक हर घर में नल-जल योजना के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। तब माताओं-बहनों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना नहीं होगा।

मिशन के क्रियान्वयन से अब तक प्रदेश के 3236 ग्रामों में हर घर में सरल, सुगम और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। इस काम को सभी जिलों में तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। मिशन में ग्रामीण आबादी के घरों सहित स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में भी पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लक्ष्य, प्रत्येक ग्रामीण परिवार, आंगनबाड़ी और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

अशोक शाह की चिट्ठी से गहराया विवाद

एक तरफ प्रदेश में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत आंगनबाड़ियों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। जिन 41205 आंगनबाड़ियों में पाइप्ड वाटर कनेक्शन (नल से पानी) देने की बात कही गई, महिला विकास विभाग की पड़ताल में सिर्फ 6327 में ही नल कनेक्शन मिला। इस स्थिति की जानकारी तब मिली, जब महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक शाह ने 10 दिसंबर को पीएचई के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को चिट्ठी लिखी। इसमें बताया गया कि प्रदेश में 84,465 आंगनबाड़ियां चल रही हैं, जिसमें पाइप्ड वाटर कनेक्शन (नल से पानी) इसी योजना से उपलब्ध कराना है हाल ही में 6 दिसंबर को पीएचई ने डब्ल्यूसीडी को रिपोर्ट दी कि 41205 आंगनबाड़ियों में पाइप्ड वाटर कनेक्शन दे दिया गया। यह रिपोर्ट आते ही डब्ल्यूसीडी विभाग के अशोक शाह ने मैदानी अमले से जांच करा ली। चार दिन में हकीकत सामने आ गई कि सिर्फ 6327 आंगनबाड़ियों में ही पानी की सप्लाई पाइप्ड वाटर कनेक्शन से हो रही है। अब इस मामले को लेकर विवाद गहरा रहा है। मंत्रालयीन अधिकारियों का कहना है कि शाह का पत्र यह दर्शाता है कि विभाग समन्वय के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अगर वाकई में आंगनबाड़ियों में पर्याप्त नल कनेक्शन नहीं हो पाया है तो वे मलय श्रीवास्तव से चर्चा भी कर सकते थे। क्योंकि दोनों एक ही बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पत्र लिखने और उसके सार्वजनिक होने से सरकार की छवि खराब हो रही है।

विधायकों पर रहेगी सख्ती

मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की कोशिश है कि यह सत्र पूरे दिन चले। इसके लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ताकि सदन में अधिक से अधिक काम हो सके।

मप्र विधानसभा के लगभग हर सत्र में सदन का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। इसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 20 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं ताकि सदन में जनहित के मुद्दों पर अधिक से अधिक काम हो सके। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों के लिए आचार संहिता लागू की जा रही है। जानकारी के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर यह प्रयास शुरू किया जा रहा है कि सदन में अधिक से अधिक काम हो सके। इसके लिए विधायकों को सवाल दोहराने की अनुमति नहीं होगी। चाहें तो पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। गिरीश गौतम का कहना है कि हमारा प्रयास है कि सदन में जनहित के विषयों पर ज्यादा चर्चा हो, इसलिए तय किया है कि विधायक लिखित सवाल न दोहराएं। उससे जुड़े पूरक प्रश्न पूछ लें। इससे समय बचेगा। बचे हुए समय में अन्य विधायकों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रयास है कि प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा सवालों को लिया जाए और पर चर्चा हो सके। जनहित से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकें। एक घंटे के प्रश्नकाल में चर्चा के लिए 25 सवालों को शामिल किया जाता है। चयन लॉटरी के जरिए होता है। सवालों पर लंबी चर्चा या हंगामा, शोर-शराबा के कारण सवाल अधूरे रह जाते हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष टाइम मैनेजमेंट में जुटे हैं। ऐसे में तय किया गया है कि विधायक लिखित सवाल न दोहराएं, क्योंकि ये सवाल तो पहले से ही संबंधित विभाग के मंत्री के पास मौजूद हैं। जवाब भी लिखित में है। यदि कोई विधायक इसी विषय से जुड़ा सवाल पूछना चाहता है तो आजादी होगी, लेकिन पूरक प्रश्न ज्यादा नहीं होगा इससे समय बचेगा और इस बचे हुए समय में शेष सवालों को शामिल किया जा सकेगा। प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा विधायकों के सवाल शामिल किए जा सकेंगे।

पिछले कुछ साल से विधानसभा में हंगामें के कारण कामकाज प्रभावित हो रहें हैं। प्रश्नकाल के दौरान आमतौर पर 25 में से 15-16 सवालों पर चर्चा हो पाती है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब सभी 25 सवाल पूछे जा सके हों, जब-जब ऐसा हुआ तब-तब संसदीय कार्य मंत्री या फिर अन्य **विधायकों की ओर से आसंदी** को धन्यवाद दिया गया। सदन में कई बार हंगामा और शोर-शराबे के चलते महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। राज्य का बजट भी कई बार बिना चर्चा के पारित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि निर्धारित किए गए दिन में प्रश्नकाल के दौरान सिर्फ नए विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। संशोधित नियम के तहत यदि किसी सदस्य ने विधायक के तौर पर सवाल पूछे और इस बीच वह मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है तो उसके लिखित सवाल निरस्त कर दिए जाएंगे या निरस्त माना जाएगा। सरकार की ओर से इनके जवाब भी नहीं दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में इंदौर-भोपाल में कमिश्नर प्रणाली का विधेयक लाया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही कई विधेयक भी सरकार विधानसभा के पटल पर रखेगी। यह विधानसभा सत्र पिछली बार की तरह हंगामे वाला हो सकता है। पांच दिनों तक चलने वाला यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में इंदौर और भोपाल में लागू की जाने वाली कमिश्नर प्रणाली को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक पर विपक्ष के नेता कमलनाथ ने भी समर्थन दिया है। उनका कहना है कि यह विधेयक हमारी सरकार भी लाना चाहती थी। इस सत्र में राज्य सरकार का अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। इसके अलावा कई और विधेयकों को लाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस सत्र में हंगामे के मूड में है। विपक्ष इस बार किसान आत्महत्या को लेकर मुद्दा गर्मा सकता है। इसके अलावा अवैध खनन, अतिवृष्टि और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। पांच दिनों के सत्र की बैठकें और अधिक बढ़ाने पर विपक्ष मांग कर सकता है, वहीं सरकार की कोशिश रहेगी कि पांच दिन में ही सारे काम निपटा लिए जाएं।

● **राकेश ग्रोवर**

विधानसभा का घटता महत्व

मप्र विधानसभा का महत्व लगातार घटता जा रहा है। पहले 5 साल में विधानसभा में लगभग 300 बैठकें होती थीं जो अब घटकर 100-125 तक आ गई हैं। पिछले लंबे समय से मप्र विधानसभा में किसी गंभीर मुद्दे पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई है। बीते दो साल में जितने कानून विधानसभा में पारित हुए हैं, किसी पर भी दो मिनट चर्चा नहीं कराई गई है। ध्वनिमत से कानून बनाने की नई परिपाटी बनती जा रही है। मप्र में दिग्विजय सिंह के पहले कार्यकाल (1993-1998) में 282 बैठकें हुईं, उनके दूसरे कार्यकाल (1998-2003) में 288 बैठकें हुईं। इसके बाद भाजपा के पहले कार्यकाल (2003-2008) में 159 बैठकें, दूसरे कार्यकाल (2008-2013) में 170 बैठकें और तीसरे कार्यकाल (2013-18) में मात्र 135 बैठकें हुईं। मौजूदा सत्र में कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने बीते तीन साल में अभी तक मात्र 43 बैठकें हुई हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है।

मप्र में करीब 7 साल बाद पंचायत चुनाव का घमासान शुरु हो गया है। भले ही पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं। इसलिए पार्टियों की साख भी दांव पर होती है। ऐसे में मप्र की मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के लिए पंचायत चुनाव काफी अहम है, क्योंकि इसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। पंचायत चुनावों से यह तस्वीर निकलकर आएगी कि किस पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है।

अब पंचायत चुनाव का घमासान

प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर होते हैं लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियों की हिस्सेदारी पूरी रहती है। इसलिए करीब 7 साल बाद होने वाले पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट की तरह हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता होने के कारण भाजपा काफी आशान्वित है। पार्टी को उम्मीद है कि 2014 की अपेक्षा इस बार के चुनाव में भाजपा समर्थित और अधिक नेता पंचायतों में जीत का परचम लहराएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क, रोजगार के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास किए गए हैं। अब सरकार का फोकस ग्रामीण रोजगार पर है। सरकार के इन प्रयासों से मप्र के गांव आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों के दौरान गांवों के विकास को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग देख सकेंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों का कार्यकाल 5 के बजाय 7 साल का हो गया। इसी कारण सरपंचों सहित अन्य पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 के बजाय 7 साल का हो गया। 7 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन वह भी वर्ष 2014 के समय के पुराने आरक्षण के आधार पर। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की ही दावेदारी कायम रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी संगठन को सक्रिय कर दिया है। वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। उधर, आदिवासी क्षेत्रों में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) भी चुनाव की तैयारियों में जुटा है।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरण में होने हैं। पंचायत चुनाव के माध्यम से तीन लाख 92 हजार 921 प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इन महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। मप्र में होने वाला त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को भाजपा और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि इन चुनावों से दोनों पार्टियों की मैदानी पकड़ और वोट बैंक का आंकलन हो पाएगा। इसलिए पंचायत चुनावों को भाजपा-कांग्रेस के लिए अग्निपरीक्षा माना जा रहा है। इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने-अपने समर्थकों के लिए मोर्चा संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, दो साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को आपसी समन्वय बनाकर पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में चुनाव की तैयारियों के लिए कह चुके हैं। इससे पंचायत चुनाव की महत्ता समझी जा सकती है। भाजपा संगठन ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को सक्रिय करने का निर्णय किया है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि चुनाव कोई भी हो, पार्टी हमेशा तैयार रहती है। मतदान केंद्र स्तर तक हमारी टीम है जो हमेशा सक्रिय रहती है। जयस ने आदिवासी क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी करने का निर्णय लिया है। संगठन अपने कार्यकर्ताओं को पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का चुनाव लड़ाएगा।

कांग्रेस ने तय किया है कि गांव से लेकर जिला स्तर तक आपसी सहमति और समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। खासतौर पर जनपद और जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्याशी का चयन जिला प्रभारी व स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, जिला और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस ने जिला स्तर पर निर्देश दिए हैं कि सभी में समन्वय रहे। उम्मीदवारी को लेकर

6 करोड़ आबादी पर फोकस

मप्र में गांवों की संख्या 51,527 है। ये गांव प्रदेश के 52 जिलों के अंतर्गत आते हैं। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 6 करोड़ से भी अधिक आबादी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। पंचायत चुनावों में यही आबादी पंच, सरपंच का चुनाव करेगी। पंचायत चुनाव के माध्यम से तीन लाख 92 हजार 921 प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इन महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसलिए भाजपा का पूरा फोकस इस आबादी पर है। दरअसल, 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 6 करोड़ आबादी का समर्थन किसी भी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों पर पूरा फोकस कर दिया है।

सामने आ रहे नामों में जिताउ का ही चयन करें। प्रयास हो कि पार्टी के लोग एक-दूसरे के मुकाबले न खड़े हों। तय किया गया है कि इस मामले में प्रदेश स्तर से दखल नहीं दिया जाएगा, यदि जिले स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो प्रदेश स्तर से मामले का निपटारा किया जाएगा। कांग्रेस को भरोसा है कि आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ है। वर्ष 2018 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़कर खरीद-फरोख्त कर अपनी सरकार बना ली। प्रदेश की जनता समझदार है। भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है। किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, उद्योग धंधे चौपट है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। पार्टी को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में उन्हें इसका लाभ होगा। पंचायत चुनाव में **जयस के मैदान में** आने से भाजपा और कांग्रेस का गणित गड़बड़ाने के आसार हैं। जयस का आदिवासी इलाकों में खासा वर्चस्व है। पिछले पंचायत चुनाव में भी जयस के उम्मीदवार खड़े थे। इसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी इत्यादि जिले प्रमुख रहे। जयस के संरक्षक डॉ. हीरा अलावा का कहना है कि जयस को पिछले चुनाव में खासी सफलता मिली थी। जयस के 150 से अधिक सरपंच का चुनाव जीते थे। इस बार और अधिक पंचायतों में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि यह चुनाव दल के आधार पर नहीं होते इसलिए पार्टी से ज्यादा क्षेत्र के जिताऊ व्यक्ति को महत्व मिलता है।

पंचायत चुनाव भले ही राजनीतिक दलों का अखाड़ा न हो, पर समर्थकों की जीत हार से दलों के दमखम का पता तो चल ही जाता है, वहीं दिग्गज नेताओं और क्षत्रपों की व्यक्तिगत स्तर पर जमावट भी रंग दिखाती है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव इस लिहाज से भाजपा के लिए अग्निपरीक्षा साबित होंगे। वजह है परिवारवाद के खिलाफ लकीर को इन चुनावों तक खींचना। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव की तर्ज पर पार्टी पंचायत चुनाव पर

भी नजर रखेगी कि किसी भी परिवार के सदस्य को जिला और जनपद पंचायत में उपकृत करने की कोशिश न की जाए, बल्कि प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को मौका देने की रहेगी। दरअसल, अब तक जिला या जनपद पंचायत पर पार्टी के क्षत्रपों का ही कब्जा रहा है। मंत्री-विधायक या कद्दावर नेता अपनी बहू-बेटी या रिश्तेदार को इन पदों पर बिठाते रहे हैं। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए मौका नहीं बचता है, साथ ही किसी एक नेता के मजबूत होने से पार्टी में स्थानीय स्तर पर असंतुलन की स्थिति भी बनती रही है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने परिवारवाद से किनारा करते हुए सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के परिवार वालों को मौका देने में काफी हद तक परहेज किया है। कुछ चुनिंदा नेताओं के बेटे-बेटियों को ही मौका मिल सका है, जिन्होंने पहले से जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगाते हुए पार्टी संदेश देना चाहती है कि भाजपा में सिर्फ समर्पित कार्यकर्ताओं को ही सम्मान और मौका मिलता है।

पिछले साल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नवंबर में विधानसभा के 28 सीटों के उपचुनाव और बीते दिनों खंडवा लोकसभा सहित तीन विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव में पार्टी ने वंशवाद से खुद को दूर रखा। इसके नतीजे भी आशा के अनुरूप आए। पार्टी मानती है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं नेताओं के बच्चे भी अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पंचायत चुनाव में परिवारवाद को नकारे जाने से प्रदेश के 313 जनपद पंचायत और 52 जिला पंचायतों में नए चेहरे दिखाई पड़ने की संभावना अधिक है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस फैसले को लेकर समन्वय समिति गठित की जाएगी, जो स्थानीय दिग्गज नेताओं और क्षत्रपों से बात करेगी। सूत्र अनुशासन का दावा करते हुए कहते हैं कि पार्टी लाइन से कोई भी नेता कभी असहमत नहीं होता, इसलिए परिवारवाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए सभी साथ है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व समग्र विचार कर रहा है। संचालन समिति, समन्वय समिति के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। भाजपा में जो तय होता, उसी को हर कार्यकर्ता चाहे वह मंत्री, विधायक-सांसद या पदाधिकारी हो, सभी स्वीकार करते हैं। भाजपा के लिए गए निर्णय पर विजय सुनिश्चित है।

● **कुमार राजेन्द्र**

भाजपा शासनकाल में गांवों में तेजी से हुआ विकास

मप्र आज बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है, इसके पीछे ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांवों के विकास पर सबसे अधिक फोकस किया है। इससे प्रदेश में गांवों की स्थिति अब तेजी से सुधर रही है। ग्रामीण इलाकों में विकास के नए सोपान गढ़े जा रहे हैं। प्रदेश को कई योजनाओं में देश में प्रथम स्थान मिलने से इसकी पुष्टि होती है। ग्राम सभाओं में भागीदारी, पंचायतों के सशक्तिकरण, सामूहिक विकास में समुदाय का समावेशन, सामुदायिक निगरानी, सहभागिता, सामुदायिक स्वामित्व जैसे मुद्दों के साथ ग्रामीण अधोसंरचना विकास, मूलभूत सुविधाएं, आवागमन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, रोजगार-स्वरोजगार, नवीन तकनीकियों की ग्राम स्तर तक पहुंच, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका क्षेत्र में प्रतिबद्धता से काम किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों से गांवों की तस्वीर बदलती दिख रही है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रदेश के गांवों में जो विकास हुआ है उसके कारण जनता उसके साथ है। इसी आधार पर पार्टी पंचायत चुनाव के रास्ते मिशन 2023 के लिए अपना जनाधार मजबूत करेगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत कृषि, पशुपालन में बुनियादी सुविधाएं, सिंचाई, भंडारण, वृहद बाजारों को गांव से जोड़ने के लिए भी उल्लेखनीय जतन किए गए हैं।

मप्र को 23 सड़कों की सौगात

विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहे मप्र में उच्च तकनीक की सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से मप्र को बड़ी सौगात मिली है। सीआरआईएफ (सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) योजना से मप्र में 1814 करोड़ रुपए लागत की 23 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे प्रदेश में सड़क नेटवर्क अब और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने मप्र के प्रस्ताव पर 600 किमी की नई सड़क बनाने की स्वीकृति केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के तहत दे दी। इसमें भोपाल के बैरागढ़ में लगभग पौने तीन किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे भोपाल और इंदौर आना-जाना आसान हो जाएगा। शहरवासियों को आमतौर पर लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा। इस बार केंद्र सरकार ने मप्र के तीन गुना अधिक राशि (एक हजार 814 करोड़ रुपए) के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के तहत केंद्र सरकार को 4 हजार 80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें से एक हजार 814 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। अभी तक प्रदेश को 500-600 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिला करती थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इंदौर प्रवास के दौरान 16 सितंबर 2021 को परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। विभाग की ओर से प्रस्तुतिकरण भी दिया गया था। इसके आधार पर सड़क निर्माण के 23 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें सागर के नरयावली विकासखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से का निर्माण कार्य भी शामिल है। सड़क निर्माण के लिए पूरी राशि केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए राशि व्यय करनी होगी।

मप्र में जिन परियोजना को स्वीकृति दी गई है, उनमें चांदपुर-छिरारई बलेह-धनगौर-बांसा काला मार्ग, शाहपुर-दरारिया-चनोआ-जामघाट-पाटर-रानगिर मार्ग, बही-बालागुड़ा-कंगहट्टी उग्राम मार्ग, समनापुर-बजाग मार्ग, मऊ जोड़ से गुलावता-धामंदा-खुजनेर मार्ग, बरोठा-सेमलिया-चउ मार्ग, कुंडम-निवास मार्ग, कलवाना नहर से प्रतापपुर बरधा मार्ग, चिनौर-करहिया और करहिया से भितरवार मार्ग, चिटोली से रानीघाटी मार्ग, डबरा-पिछोर सड़क से कटारे बाबा की मड़ी से सरनागत बडेरा मार्ग, देवतालाब से नईगढ़ी मुख्य जिला मार्ग, भादवामाता-सरवानिया महाराज-जावरा थाना-धानी-सरोदा-चंदोल मार्ग, बंडोल-बंकी-सागर-चंदोरीमरगोदी-जमकनरगाव-कोहका मार्ग, जवासियापंथ-फतेहाबाद से चंद्रवटीगंज मार्ग, ब्योहारी-माडल गांव- न्यू सपटा मार्ग, स्वर्णरेखा नाला ग्वालियर आइआइटीएम से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा मार्ग, बैरागढ़ एलिवेटेड कारिडोर, भोपाल, बकतरा-भारकच्छ सड़क से देहरी बम्होरी-सोमलवाड़ा-नांदेर-खैरी सिलेगाना-जौनतला-जैत-सरदारनगर-हथनौरा-संदानिया बनेटा से शाहगंज मार्ग, बकतरा-सागपुर-रिछोड़ा-खोहा-क्वाड़ा-सत्रहमऊ-बोदरा-ग्वादिया-नीमटोन-डुंगारिया मार्ग, रीवा शहर में सिरमौर चौराहे में बने फ्लाई ओवर के तीसरे पिलर का निर्माण, पन्ना पहाड़ी खेड़ा मार्ग आदि शामिल हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बार-बार ग्वालियर की एलिवेटेड रोड को सीआरआईएफ योजना के तहत शामिल करने के लिए बार-बार पत्र लिखते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 21 सितंबर को नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। इसमें ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जिले की सड़क निर्माण की मांग की गई थी। केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत इन सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति देने का अनुरोध सिंधिया ने किया था। लगभग 600 किमी लंबाई की यह सड़कें उनके द्वारा ही प्रस्तावित की गई थीं। जिसमें ग्वालियर-चंबल की सड़कें ज्यादा थीं।

उधर, राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में 234 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसका निर्माण केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की सीआरआईएफ स्कीम में होगा। गत दिनों केंद्र सरकार ने प्रदेश की विभिन्न सड़कों के लिए 1814 करोड़ की राशि स्वीकृत की। इसमें संतनगर में लाउखेड़ी से सीहोर नाले तक एलिवेटेड रोड भी शामिल है। इसके निर्माण से यातायात सुगह होने के साथ व्यापारियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने 5 साल पहले यानी साल 2017 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। विधायक ने बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर) की लोकेलिटी और दो लाख की आबादी और व्यापारिक गतिविधियों का हवाला देते हुए एलिवेटेड रोड बनाने का आग्रह किया था।

● **नवीन रघुवंशी**

बुदनी के खेत में मेडिकल कॉलेज

प्रदेश में किस तरह विकास हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार बुदनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पहले अस्पताल, फिर नर्सिंग, फिर फार्मेसी और उसके बाद मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। जबकि प्रदेश के कई बड़े जिले ऐसे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता है, लेकिन बुदनी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए उस क्षेत्र पर अधिक मेहरबानी दिखाई जा रही है।

केन-बेतवा प्रोजेक्ट को हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खास बात यह है कि इसका 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके तहत 176 किलोमीटर की लिंक कैनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मप्र के सागर-विदिशा सहित 12 जिलों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही 10 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। 16 साल पिछड़ने से परियोजना की लागत भी बढ़ गई है। करीब 8 हजार करोड़ रुपए की नदी जोड़ो परियोजना अब 44 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। जबकि वर्ष 2015 में परियोजना की लागत 37 हजार करोड़ आंकी गई थी। लागत में भारी भरकम इजाफा 16 साल की देरी के साथ जीएसटी लगने से भी हुआ है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि उप्र में चुनाव से पहले नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इसका भूमिपूजन अगले महीने झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। इससे पहले मोदी कैबिनेट ने दोनों राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से नॉन मानसून सीजन (नवंबर से अप्रैल के बीच) में मप्र को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उप्र को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इस योजना से सागर-विदिशा समेत मप्र के 8 जिलों को पानी पहुंचाना है। बता दें कि इसे लेकर मप्र और उप्र के बीच चल रहा विवाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 8 महीने पहले सुलझ गया था। इसी साल, विश्व जल दिवस पर 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 5-5 प्रतिशत हिस्सेदारी मप्र व उप्र वहन करेंगे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय वर्ष 2002 में केन और बेतवा नदी को जोड़ने की रूपरेखा बनी थी। अगस्त 2005 में उप्र और मप्र सरकार के बीच इसको लेकर पहला समझौता हुआ। इसमें केन नदी को पन्ना जिले में प्रस्तावित ढोढ़न बांध से लगभग 221 किमी लंबी केन-बेतवा लिंक नहर के जरिए झांसी के बरुआसागर के पास बेतवा नदी से जोड़ा जाना था। उस दौरान इसकी लागत 8 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी। सबसे अधिक खर्च पुनर्वास पर किया जाना था। डूब के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क को स्थानांतरित किया जाना था। लेकिन परियोजना पर काम शुरू होने के बजाय उप्र एवं मप्र के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद के चलते परियोजना लगातार पीछे खिसकती गई। इस वजह से पुनर्वास लागत भी बढ़ती गई। 2015 में जब एक बार फिर दोनों राज्य परियोजना को लेकर सहमत होने लगे तब इसकी लागत बढ़कर 37 हजार करोड़ तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी परियोजना जल बंटवारे को लेकर 6 साल उलझी रही।

प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर ढोढ़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिया बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं, दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना करीब 10.62 लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावॉट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना में दो बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावॉट है। परियोजना से बुंदेलखंड के उप्र और मप्र के 12 जिलों को पानी मिलेगा। मप्र के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी को पानी मिलेगा। वहीं, उप्र के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार के दखल के बाद 22 मार्च 2021 को आखिरकार उप्र एवं मप्र की राज्य सरकारें पानी के **बंटवारे को लेकर सहमत हो गईं।** अब परियोजना पर काम शुरू होने का समय आ गया है। ऐसे में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने परियोजना की लागत का फिर से आंकलन किया जा रहा है, जो अब 75 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। लागत बढ़ने की वजह जीएसटी को भी माना जा रहा है। जो परियोजना पर 18 फीसदी जोड़ा गया है। वहीं, पुनर्वास खर्च में बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में लागत का करीब 30 फीसदी बढ़ना तय है हालांकि अभी लागत पूरी तरह तय नहीं हुई है। लागत को लेकर परीक्षण का काम चल रहा है। परियोजना की कुल लागत का 90 फीसदी बजट केंद्र सरकार को देना है, जबकि शेष 10 प्रतिशत बजट उप्र एवं मप्र सरकार अपने-अपने पानी के अनुपात में वहन करेंगे। इस लिहाज से दोनों ही राज्यों को इस परियोजना में काफी कम लागत खर्च करनी होगी। लेकिन बढ़ी लागत के अनुसार केंद्र का खर्च बढ़ गया है।

● **जितेंद्र तिवारी**

2005 में गौर-मुलायम ने किए थे हस्ताक्षर

परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मौजूदगी में दोनों प्रदेशों के बीच अनुबंध हुआ था। मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। तब परियोजना का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ था। अब डीपीआर तैयार है। इस कारण पानी की भराव क्षमता में कुछ बदलाव हुआ है। इस कारण से तीनों सरकारों के बीच संशोधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। 2005 में उप्र को रबी फसल के लिए 547 एमसीएम और खरीफ फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय हो गया था। 2018 में उप्र की मांग पर रबी फसल के लिए 700 एमसीएम पानी देने पर सहमति बन गई थी। केंद्र सरकार ने उप्र को 788 एमसीएम पानी देना तय कर दिया था, लेकिन उप्र सरकार ने जुलाई 2019 में 930 एमसीएम पानी मांग लिया था, जिसे मप्र ने इनकार कर दिया था।

स्मार्ट सिटी के नए टेंडर पर रोक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी भोपाल में बंद पड़े कैमरों और सागर के निर्माणाधीन लाखा बंजारा तालाब की धीमी प्रगति पर अफसरों से नाराजगी जताई। चौहान ने कहा कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी मिशन में हुए कार्यों, उनके औचित्य, टेंडर प्रक्रिया, व्यय राशि तथा अनियमितताओं की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिन निर्माण कार्यों के टेंडरों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वह कमलनाथ सरकार के दौरान जारी हुए थे। इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव सवाल उठा चुके हैं। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने यह मामला उठाया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी निर्माण में सौंदर्यीकरण के स्थान पर उपयोगिता और जनता की सुविधा को प्राथमिकता बनाया जाएगा। कोई भी नया टेंडर नहीं होगा। जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। राशि का मितव्ययी और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सातों स्मार्ट सिटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और सतना के जन-प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। सभी सात शहरों में संचालित योजनाओं की वे स्वयं बिंदुवार समीक्षा करेंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 6600 करोड़ से 587 योजनाएं संचालित हैं। इसमें से महज 1577 करोड़ के काम पूरे हो पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम एवं पुलिस सहित नगरीय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों से बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें। मिशन में जनता की आवश्यकता और शहर की प्राथमिकता के अनुसार जन-प्रतिनिधियों और **नगरवासियों की सलाह** से कार्यों की प्राथमिकता तय होगी तथा उसके अनुरूप ही निर्माण कार्य संचालित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े शहरों के साथ मझौले और छोटे शहरों का नियोजन भी भविष्य की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। स्मार्ट सिटी मिशन के वित्तीय संसाधनों का उपयोग केवल स्मार्ट सिटी तक ही सीमित नहीं रहे। इसके वित्तीय संसाधनों का उपयोग संपूर्ण शहर के विकास में सुनिश्चित किया जाए। मूलभूत कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी से नगर निगम या अन्य एजेंसियों को राशि हस्तांतरित करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के लंबे ब्रेक के बाद अब मप्र में स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के काम में तेजी लाई जाएगी। इसका काम तेज गति से करने के लिए जिम्मेदार अफसरों को फ्री हैंड दे दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विगत दिनों स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के अभी तक के काम की समीक्षा के लिए गत दिनों भोपाल में बैठक ली थी। जिसमें काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने अफसरों को फ्री हैंड दिया था। उन्होंने कहा था कि भोपाल और इंदौर की तरह अन्य स्मार्ट सिटी भी पीपीपी और कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट बनाएं। स्मार्ट सिटी में पूरे अधिकार आपके पास ही हैं। सभी प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। प्रोजेक्ट पर अमल के लिए किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए।

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जमीन नीलामी में भारी गड़बड़ी और घोटाला सामने आ चुका है। इस मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई है। ईओडब्ल्यू अब इस मामले की जांच कर रहा है। हाल ही में भोपाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने करोड़ों रुपए की जमीन नीलाम की है। ईओडब्ल्यू को मिली शिकायत में नीलामी की शर्तों में हेराफेरी कर कई नामी बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। यह शिकायत उन बिल्डर्स की ओर से की गई है, जिन्हें शर्तें पूरी करने के बाद भी स्मार्ट सिटी में जमीन नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक टीटी नगर इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। इस इलाके में करीब 100 एकड़ जमीन को बेचा जाना है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए है। इसमें से कुछ जमीन की नीलामी भोपाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने पिछले दिनों कर दी है। इस राशि का उपयोग अलग-अलग क्षेत्र के 23 प्रोजेक्ट पूरा करने में किया जाना है। आरोप है कि नीलामी के पहले जमीन पर निर्माण की शर्तें कुछ और थीं, लेकिन नीलामी के बाद जमीन आवंटित होते ही शर्तों को बदल दिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए सभी सातों शहरों में किए जाने वाले कामों में तेजी लाएं। इस दौरान यह ध्यान रखा जाए कि काम की गुणवत्ता बनी रहे। स्मार्ट सिटीज में जो 216 परियोजनाओं के 3442 करोड़ के काम चल रहे हैं, उसकी मॉनीटरिंग का काम भी होता रहे। इसके अलावा करीब 1350 करोड़ रुपए के जो काम टेंडर में हैं और जिनकी डीपीआर तैयार की गई है, उसके काम में भी तेजी लाई जाए।

● **राजेश बोरकर**

कागजों में प्रोजेक्ट, शहर कैसे होगा स्मार्ट?

भोपाल सहित प्रदेश के सात स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों बैठक की। बैठक में अफसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की उपलब्धियां गिनाने लगे। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्होंने रोकते हुए जमकर फटकार लगाई और बोले कि प्रोजेक्ट कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ऐसे में शहर कैसे स्मार्ट बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कई प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और लापरवाही को लेकर भी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री बोले- भोपाल में स्मार्ट सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। पहले बहुत गड़बड़ हुई है। फाइलें निकालकर देखिए। उन्होंने सीसीटीवी का काम पुलिस को देने की बात कहीं। मीटिंग की शुरुआत में अफसर अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट में कमियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में बताने में 20 घंटे लगे तो भी मैं बैठूंगा। आप इसे पूरी तरह से बताइए। उन्होंने टेंडर को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा- हमें प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि पहले क्या करना है। सबसे पहले खराब सड़कें सुधारें। कुछ प्रोजेक्ट को लेकर वे बोले- मुझे डीटेल में समझना है। जब तक मैं इसे डीटेल से नहीं देख लूंगा, चैन नहीं पड़ेगा। हम पीपीपी मॉडल पर जाएं।

माफिया ने रोकी नर्मदा की धार

पोकलेन से रास्ता बना, निकाल रहे रेत

ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि होशगांबाद व सीहोर जिले के बीच नर्मदा नदी में बने जांजना टापू से अवैध कारोबारी कश्तियों से अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं। विगत एक माह से जाजना टापू पर पहुंचने के लिए नर्मदा नदी की धार को रोककर आधा किमी से ज्यादा लंबा रास्ता बना लिया गया है। बीच नर्मदा नदी में 100 से अधिक पाइप डालकर पुल का निर्माण किया जा रहा है। नाव से जाजना टापू पर पोकलेन उतारी जाती है। जो दूसरे छोर से रास्ता तैयार कर रही है। नर्मदा नदी के बीच जो टापू है, उसका आधे से अधिक भाग होशंगाबाद जिले में आता है। जहां भारी मात्रा में रेत के अवैध खनन व चोरी के लिए कारोबारी जुटे हुए हैं।

मप्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन का काला करोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज पर प्रदेश में रेत का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं लाइसेंस लेकर तो कहीं बिना लाइसेंस के अवैध खनन जारी है। रेत का यह अवैध कारोबार प्रशासनिक अमले की भी कमाई का जरिया बना हुआ है। इसी कारण कार्रवाई नहीं की जाती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि प्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा नदी हो या कोई अन्य नदी उनमें बेधड़क अवैध खनन चल रहा है। आलम यह है कि सरकार की नई रेत खनन नीति केवल कागजी शोभा बनकर रह गई है। प्रदेश में नर्मदा, चंबल, सोन सहित जितनी नदियां हैं उनमें अवैध रेत का खनन जोरों पर है। सोन नदी में रेत उत्खनन व परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद रेत की निकासी पर रोक नहीं लग पा रही है। रेत की वैध खदानों में भी नियमों को दरकिनार कर बीच नदी में टू-टेन मशीनों के माध्यम से धड़ल्ले से रेत की खुदाई की जा रही है। इससे नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि सीहोर जिले के रेत माफिया बीच नदी की धार में पाइपलाइन डालकर आधा किमी रोड बनाने की तैयारी कर रहा है, जो जाजना टापू से रेत का अवैध परिवहन करना चाहता है। इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों डंपर गुजर रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। डंपर से धूल उड़ रही है, जिससे पूरे गांव में धुंध छा जाती है। हालत यह है कि ग्रामीण दहशत के मारे घरों से नहीं निकल पा रहे है। वहीं रोक-टोक करने पर बंदूक की नोक पर डराया जा रहा है। यदि शीघ्र अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई और रास्ते का निर्माण नहीं रोका गया तो पूरे ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, वहीं समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। जानकारी के अनुसार होशगांबाद व सीहोर जिले के बीच नर्मदा नदी में बने जाजना टापू से रेत माफिया कश्तियों से अवैध रेत परिवहन करते आ रहा है, लेकिन पिछले एक माह से जाजना टापू पर पहुंचने के लिए आधा किमी लंबा रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों डंपर रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं बीच नदी में 100 से अधिक पाइप डालकर पोकलेन व बुलडोजर रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। हालत यह है कि नाव से जाजना टापू पर पोकलेन उतार दी गई है, जो दूसरे छोर से रास्ता तैयार कर रही है।

छीपानेर घाट पर दिन-रात चल रहे इस अवैध खनन की जानकारी पुलिस और प्रशासन दोनों को है। बावजूद इसके इस पर अभी तक कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। देवास का माफिया खुलेआम रेत का खनन नर्मदा नदी में ट्रैक्टर ट्राली से कर रहा है। वहीं हरदा जिले में मशीनों से रेत निकलकर कश्तियों में भरकर छीपानेर घाट पर लाई जाती है और यहां से ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ककेड़ी नदी पर बनाए हुए अस्थाई पुल के जरिए देवास की सीमाओं पर ले जाई जा रही है।

नर्मदा नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीण कई बार मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। गौरतलब है कि दो हफ्ते पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज आए थे। जहां उन्होंने मंच से जिला प्रशासन को सख्त लहजे में कहा था कि अवैध खनन पर कार्रवाई करें नहीं तो मैं आप पर कार्रवाई करूंगा। सिवनी-मालवा तहसील मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर बाबरी घाट और पथाड़ा घाट के पास बीच नर्मदा नदी में बने रेत के बड़े टापू पर रेत का अवैध उत्खनन के लिए सीहोर जिले के रेत माफिया सक्रिय हैं। रेहटी तहसील के पास नर्मदा किनारे के ग्राम जांजना मगांव से बीच नर्मदा नदी में अवैध कारोबारियों ने पाइप डालकर और नाव जोड़कर पुल बनाकर होशंगाबाद जिले से रेत चुराने के लिए पोकलेन मशीनों से मार्ग बना डाला।

अवैध खनन और ओवरलोड डंपरों की भारी आवाजाही से परेशान होकर सीहोर जिले के नर्मदा किनारे के ग्राम जांजना, मठागांव, बाबरी, डिमावर के ग्रामीण गत दिनों रेहटी तहसील कार्यालय और थाने पहुंचे। जहां पर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सीहोर जिले के रेत माफिया बीच नर्मदा नदीं की धार में पाइप डालकर आधा किमी रोड बना रहे हैं। जो जांजना टापू से रेत की चोरी की कोशिशें कर रहे हैं। गांव में से दर्जनों डंपर रोज गुजरने से हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अवैध खनन व डंपरों को निकालने से रोकने पर रेत माफिया व उनके हथियारबंद लोग धमका रहे हैं। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग करेगा। होशंगाबाद जिले के खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने कहा कि बाबरी घाट के पास नर्मदा नदी में रेत के टापू पर जाने का रास्ता सीहोर जिले की तरफ से अवैध मार्ग बन रहा है, जिससे उत्खनन करने की संभावना है। इस बारे में सीहोर जिला खनिज अधिकारी को पत्र भेजा है। जल्द संयुक्त टीम बनाकर अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

● **लोकेंद्र शर्मा**

‘भ्रष्टों’ की बनेगी कुंडली

केंद्र सरकार ने मप्र सहित अन्य राज्यों को अपने कैडर के ब्यूरोक्रेइस की सेवाओं का 15:25:50 के फॉर्मूले पर आंकलन करने और इसकी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही डीओपीटी ने ब्यूरोक्रेइस की कमाई का आंकलन भी शुरु कर दिया है। इसके पीछे असली वजह यह है कि केंद्र सरकार भ्रष्ट, नाकारा और कामचोर अफसरों को सेवामुक्त करना चाहती है। नए साल के दूसरे या तीसरे महीने में भ्रष्टों की कुंडली सार्वजनिक करने की तैयारी की जा रही है।

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले नौकरशाही की कार्यप्रणाली को बदलने की कवायद शुरू की थी। इन 7 साल के दौरान दर्जनभर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। एक बार फिर से बड़े स्तर पर अफसरों की सेवाओं और संपत्तियों का आंकलन करने की तैयारी चल रही है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अनुपातहीन संपत्ति के मामले में मप्र के 104 आईएएस, 82 आईपीएस और 18 आईएफएस कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संदेह के दायरे में हैं। इसलिए डीओपीटी ने नौकरशाहों की कार्यप्रणाली पर नजर रखनी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि मप्र के कई ब्यूरोक्रेड्स के साथ ही देश के अन्य राज्यों के सैकड़ों ब्यूरोक्रेड्स भ्रष्टाचार की जद में हैं। प्रदेश में कई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में मामले दर्ज हैं। अब इन अफसरों के साथ ही अन्य कई अफसरों की सेवाओं और संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है। डीओपीटी जहां अपने स्तर पर आंकलन करा रहा है, वहीं प्रदेश सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है।

नौकरशाहों सहित सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति पर सरकार की पैनी नजर है। कौन सा अधिकारी कहां से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके लिए पैसे कहां से जुटाए हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डीओपीटी ने जहां राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अधिकारियों-कर्मचारियों से अपनी प्रापर्टी की जानकारी अपने विभाग को देने के लिए कहें। वहीं डीओपीटी अपने स्तर से भी जानकारी जुटा रहा है। गौरतलब है कि अधिकारी-कर्मचारी को अपने विभाग में अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देने का प्रावधान है, लेकिन कई विभागों में देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी यह सूचना देने से बच रहे हैं। वे न तो लेनदेन करने से पहले और न ही उसके बाद अपने विभाग को कुछ बताते हैं। जो कर्मचारी लेनदेन की पूर्व सूचना देते हैं, वह आधी-अधूरी होती है। केंद्र सरकार अब सभी विभागों में इस बात को लेकर सख्ती बरत रही है। सभी अधिकारी-कर्मचारी सीसीएस (कंडक्ट) रुल्स 1964 के अनुसार उक्त जानकारी देना सुनिश्चित करें। आचरण नियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है।

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक द्वारा 25 नवंबर को इसे लेकर एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति से संबंधित लेन-देन की सूचना अपने कार्यालय में देनी होगी। यह सूचना देना एवं उसके पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस

ये आईएएस और आईपीएस होंगे पदोन्नत

इधर, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों को पदोन्नत कर दिया जाएगा। इस दौरान आईएएस अफसर निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आकाश त्रिपाठी, मुकेश गुप्ता और शोभित जैन को सचिव से प्रमुख सचिव, जबकि कमिश्नर जनसंपर्क सुदाम खाड़े, अपर सचिव पंचायत व ग्रामीण विकास धनंजय सिंह भदौरिया, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बाबू सिंह जामोद, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी और कमिश्नर होशंगाबाद संभाग माल सिंह को सचिव के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा। वहीं भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर समेत तीन अफसरों को एडीजी बनाया जाना है। उनकी पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक 21 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसमें 1997 बैच के आईपीएस अफसरों को आईजी से एडीजी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इनमें भोपाल के पुलिस कमिश्नर बनाए गए मकरंद देउस्कर, गृह सचिव डी. श्रीनिवास वर्मा और जबलपुर आईजी उमेश जोगा के नाम शामिल हैं। अभी एडीजी के स्वीकृत पद भरे होने की वजह से नए चार पद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2004 बैच के आईपीएस अफसर डीआईजी से आईजी बनाए जाएंगे। इनमें भोपाल के एडिशनल कमिश्नर इरशाद वली, डीआईजी सीआईडी गौरव राजपूत और डीआईजी भोपाल देहात संजय तिवारी का नाम है। वर्ष 2008 बैच के आईपीएस अफसर ललित शाक्यवार एसपी से डीआईजी बनेंगे। जबकि 2009 बैच के अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा।

संदर्भ में मुख्य कार्यालय द्वारा जब जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा। कई मामलों में लेनदेन के पूर्व में न कोई सूचना दी जाती है, और न उसके लिए विभाग की मंजूरी ली जाती है, जो सूचना मिलती है, उसमें कई खामियां व त्रुटियां पाई जाती हैं। इससे अनावश्यक पत्र-व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। विभागों से कहा गया है कि लेनदेन से संबंधित जो फार्म संख्या-1 और 2 जारी किए गए हैं, उन्हें ठीक तरह से भरकर विभाग के पास जमा कराया जाए। वे फार्म निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। इनमें अचल संपत्ति व चल संपत्ति के लिए अलग-अलग फार्म हैं। भूखंड, फ्लैट आदि की बुकिंग करना भी लेनदेन माना जाता है, इसलिए यह जानकारी भी विभाग को देनी होगी। चल संपत्ति के संबंध में ट्रांजेक्शन पूर्ण होने की तिथि के एक माह के भीतर ही अधिकारी, कर्मचारी द्वारा उसकी सूचना दी जानी है। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन किसी आधिकारिक संबंध रखने वाले व्यक्ति से हो रहा है, तब उसकी कार्यालय में पूर्व सूचना देना, मंजूरी लेना अनिवार्य है।

अधिकारी-कर्मचारी के लिए ट्रांजेक्शन में लगने वाली धनराशि के स्रोत का स्पष्ट ब्यौरा देना जरूरी है। धन स्रोतों के समर्थन में कई तरह के दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें बैंक ऋण की फोटो कॉपी, जिसमें लोन की राशि एवं उसे वापस चुकाने के निबंधन स्पष्टतया प्रकाशित हों। रिश्तेदार से ऋण के संबंध में अलग प्रावधान किया गया है। रिश्तेदार द्वारा लोन के संबंध में प्राप्त सहमति पत्र, जिसमें यह स्पष्ट हो कि ऋण ब्याज सहित है या ब्याज मुक्त है। उसमें ऋण को चुकाने के निबंधन एवं रिश्तेदार (जिस से ऋण लिया गया है) की कमाई का स्रोत भी स्पष्ट होना चाहिए। जीवन साथी के परिवार के सदस्यों के योगदान को लेकर कई सूचनाएं देनी होंगी। जैसे रोजगार का स्रोत आदि। स्रोत से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे।

किसी भी स्थिति में गृह निर्माण के लिए दूसरी बार पैसा निकालना सही नहीं है। इसी क्रम में आवेदक (कर्मचारी-अधिकारी) द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें धन का एक स्रोत दर्शाया गया हो। यह भी स्पष्ट किया गया हो कि उन्होंने पूर्व में कभी भी मकान-निर्माण (प्लॉट या बने-बनाए फ्लैट की खरीद आदि) के लिए जीपीएफ से पैसा नहीं निकलवाया है। आवेदक के द्वारा प्रमाण पत्र में दिए गए कथन को संबंधित अधिकारी द्वारा उनके रिकॉर्ड जांच के उपरांत ही सत्यापित कर अनुमोदित करना है। यह बिंदु अधिकारियों द्वारा किसी भी आवेदन को अग्रसारित करते समय ध्यान में रखा जाना है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के जीवन साथी या घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा उनकी निजी राशि (जिसमें स्त्रीधन, उपहार, विरासत आदि शामिल हैं) में से कोई लेनदेन किया जाता है जिसपर खुद अधिकारी-कर्मचारी का कोई अधिकार न हो और न ही जो अधिकारी-कर्मचारी की निधि से किया गया हो, तो ऐसे लेनदेन की सूचना देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी अपनी किसी अचल या चल संपत्ति (जो कि निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो) को अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर स्थानांतरित करता है, तो उनके द्वारा रूल 18 (2)×(3) के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी को ऐसे लेनदेन की सूचना देना या उनसे इसकी पूर्व में मंजूरी लेना अनिवार्य है।

मप्र के 104 आईएएस, 82 आईपीएस और 18 आईएफएस अफसरों सहित देशभर के 2200 अधिकारी एक बार फिर पीएमओ और डीओपीटी के निशाने पर हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों से बचने के लिए धन कुबेर नौकरशाहों के पैतृक गांवों में करोड़ों रुपए के निवेश के संकेत मिले हैं। पीएमओ के एक अधिकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से सभी राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में काम कर रहे अफसरों के कामकाज की समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है। पीएमओ ने सीबीआई से ऐसे अफसरों को रडार पर लेने को कहा है जिनके कामकाज का प्रदर्शन संतोषप्रद न होने के साथ संदिग्ध भी नजर आ रहा है।

भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सीबीआई व आयकर विभाग की चपेट में आए मप्र के आला अफसरों की लंबी फेहरिश्त है। कई अफसरों के खिलाफ तो केंद्र एवं राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के अलावा प्रवर्तन निदेशालय में भी छानबीन चल रही है।

● **सुनील सिंह**

मप्र को मिलेंगे 29 आईएएस-आईपीएस

प्रदेश को इस साल 29 आईएएस-आईपीएस अधिकारी मिल जाएंगे। इसके लिए 20 दिसंबर को राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस और राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग आवंटन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी करेंगे। बैठक भोपाल में प्रस्तावित की गई है। इसमें 18 राज्य प्रशासनिक सेवा और 11 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईएएस और आईपीएस संवर्ग आवंटन होगा। आईएएस के लिए 1994 बैच के विनय निगम, विवेक सिंह और 1995 बैच के पंकज शर्मा के नाम भी विचार के लिए बैठक में रखे जाएंगे। दोनों को पिछले साल जांच चलने के कारण मौका नहीं मिल पाया था। वरिष्ठता के अनुसार सुधीर कोचर, रानी बाटड, चंद्रशेखर शुक्ला, त्रिभुवन नारायण सिंह, नारायण प्रसाद नामदेव, दिलीप कुमार कापसे, बुद्धेश कुमार वैद्य, जयेंद्र कुमार विजयवत, डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान, मनोज मालवीय, नीतू माथुर, अंजू पवन भदौरिया और जमना भिडे को आईएएस संवर्ग मिलना तय माना जा रहा है। इसी तरह राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 11 पद उपलब्ध हैं। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेवा अभिलेखों के आधार पर 1995-96 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन को आईपीएस संवर्ग आवंटित हो सकता है। अब देखना है किन अफसरों की लॉटरी लगती है।

गुणवत्ताहीन उपज खरीदने पर होगी जेल!

मप्र में समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी में होने वाले खेल को रोकने के लिए प्रदेश सरकार मप्र कृषि उपज उपार्जन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय का विनियमन विधेयक-2021 लाने की तैयारी कर रही है। इसमें गुणवत्ताहीन उपज खरीदने पर जुर्माना लगाया जाएगा और कारावास का भी प्रविधान रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में हर साल मंडियों और खरीदी केंद्रों पर अमानक गेहूं, धान, चना, मूंग सहित अन्य उपज की खरीदी कर ली जाती है। बाद में केंद्र सरकार उसे रिजेक्ट कर देती है। जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगती है।

दरअसल, प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में ऐसा अनाज उपार्जन केंद्रों द्वारा खरीद लिया जाता है, जिसे भारतीय खाद्य निगम या नागरिक आपूर्ति निगम अमानक बताकर लेने से इंकार कर देते हैं। जबकि, किसानों को भुगतान हो चुका होता है। ऐसे में सरकार को इसका वित्तीय भार उठाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने मप्र कृषि उपज उपार्जन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय का विनियमन विधेयक-2021 लाने की तैयारी की है। इसमें गुणवत्ताहीन उपज खरीदने पर जुर्माना लगाया जाएगा और कारावास का भी प्रविधान रहेगा।

प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मूंग सहित अन्य उपज खरीदने की व्यवस्था को सख्त बनाने जा रही है। प्रदेश में किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रमुख रूप से गेहूं और धान की खरीद की जाती है। दो साल पहले समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूं खरीदकर मप्र देश में रिकार्ड भी बना चुका है। इसी तरह धान का उपार्जन भी प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष 40 लाख टन से अधिक धान की खरीद संभावित है। ग्रीष्मकालीन मूंग भी पहली बार लगभग आठ लाख टन खरीदी गई है। सरकार इसमें हजारों करोड़ रुपए व्यय कर रही है, जिसका इंतजाम आरबीआई से ऋण लेकर किया जाता है। नागरिक आपूर्ति निगम पर लगभग 55 हजार करोड़ रुपए का ऋण है।

केंद्र सरकार जब सेंट्रल पूल में गेहूं, धान, चना, मूंग आदि उपज ले लेती है तो फिर उसका भुगतान होता है लेकिन दो-साल से गुणवत्ताहीन उपज खरीदने के मामले सामने आ रहे हैं। लगभग चार लाख टन अनाज उपार्जन केंद्रों ने ऐसा खरीद लिया जिसे गुणवत्ताहीन बताकर एजेंसियों ने लेने से इंकार कर दिया। इसी तरह सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों से गेहूं और धान बिकने के लिए आने के मामले भी सामने आए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था को सख्त बनाने का निर्णय लिया है। अब सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी उपार्जन केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा और गड़बड़ी पाए जाने पर सामग्री और वाहन को जब्त भी कर सकेगा। औसत गुणवत्ता से कम की उपज खरीदने पर दस हजार रुपए या उपार्जित उपज के समर्थन मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

प्रस्तावित विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। औसत गुणवत्ता से कम की उपज खरीदने पर दस हजार रुपए या उपज के समर्थन मूल्य के बराबर जुर्माना लगेगा। सुरक्षित भंडारण न करने पर नुकसान की भरपाई संबंधित व्यक्ति या संस्था से होगी। उपज में मिलावट करने या चोरी करने पर अर्थदंड या छह माह के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। उपार्जन करने वाली संस्था की गड़बड़ी प्रमाणित होने पर उसे दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति उपार्जन में गड़बड़ी करता है तो उसे भविष्य में उपार्जन के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियम का उल्लंघन करने पर पचास हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। संस्था द्वारा त्रुटि करने पर संस्था के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कलेक्टर के किसी भी आदेश के विरुद्ध संभागायुक्त के पास अपील होगी। अभियोजन संबंधी कार्यवाही सरकार की अनुमति के बाद ही की जा सकेगी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अतिवर्षा से प्रभावित बाजरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर इस वर्ष कमजोर गुणवत्ता वाला बाजरा भी खरीदा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार मप्र को विशेष अनुमति देगी। दरअसल, ग्वालियर-चंबल संभाग में अतिवर्षा की वजह से बाजरा की उपज प्रभावित हुई है। दाना भी छोटा रह गया। इसके कारण समर्थन मूल्य पर खरीद रोक दी गई थी। किसानों के हित को देखते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से विशेष छूट देने की अनुमति देने को लेकर बात की। तोमर ने भरोसा दिलाया है कि वे केंद्र सरकार के स्तर पर निर्धारित एफएक्यू (औसत गुणवत्ता) से कमजोर बाजरा खरीदने को लेकर सहमति बनवा लेंगे। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से सस्ता अनाज योजना के तहत वितरित किया जाएगा। 29 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के साथ-साथ राज्य सरकार ने बाजरा की खरीद भी प्रारंभ कर दी थी लेकिन कमजोर दाना होने की वजह से इसे रोक दिया गया है। किसानों ने इसकी जानकारी सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को दी तो उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा की और अपर मुख्य सचिव सहकारिता अजीत केसरी के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र भिजवाया। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष ग्वालियर-चंबल इलाके में अतिवर्षा के कारण बाजरा का दाना छोटा रह गया है। इसके कारण समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल दो हजार 250 रुपए) पर हो रही खरीद में इसे गुणवत्ताहीन बताया गया। अब सरकार की तैयारी है कि एफएक्यू में विशेष रियायत देते हुए बाजरा खरीद की अनुमति दी जाए। बाजरा की खेती ग्वालियर-चंबल संभाग में ज्यादा होती है।

भगवान भरोसे गाय माता

प्रदेश में गाय पर खूब सियासत होती है। चुनाव के वक्त भी गाय की सबको याद आती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सियासी पार्टियां और नेताओं की प्राथमिकता से गाय गायब हो जाती है। यही वजह है कि सरकारी फंड के सहारे चलने वाली गौशालाएं दुर्दशा का शिकार हो रही हैं और गौशालाओं में रहने वाली गायों को खाने के लिए पर्याप्त चारा तक नहीं मिल रहा। कोरोनाकाल में तो गौशालाओं की हालत और खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में बीते एक साल में शुरू की गई गौशालाओं में संचालकों द्वारा अनुदान के नाम पर खेल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद से नई गौशालाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इस खेल की शिकायत मिलने के बाद अब मप्र गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा प्रदेश की सभी गौशालाओं का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

प्रदेश की राजधानी में भोपाल में सरकारी अनुदान से चलने वाली 33 गौशालाओं को पिछले सात महीने से अनुदान नहीं मिला है। ऐसे में यह गौशालाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। सरकारी अनुदान नहीं मिलने की वजह से गायों के खाने के लिए भूसा, हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऐसे में पर्याप्त चारा नहीं मिलने के चलते गायों की लगातार मौतें हो रही हैं। राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर कुठार गांव की गौशाला का संचालन 2020 से शुरू हुआ था। संचालन के दो माह तक तो सरकारी फंड मिला, लेकिन इसके बाद से अब तक कोई फंड नहीं आया है। यह केवल राजधानी भोपाल के पास की एक गौशाला का मामला है, जबकि पड़ताल में पता चला कि पिछले सात महीने से भोपाल में संचालित होने वाली सभी गौशालाओं का यही हाल है।

वहीं मप्र में बीते एक साल में शुरू की गई गौशालाओं में संचालकों द्वारा अनुदान के नाम पर खेल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद से नई गौशालाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इस खेल की शिकायत मिलने के बाद अब मप्र गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा प्रदेश की सभी गौशालाओं का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। दरअसल सरकार ने बीते साल ही नवंबर में गौ कैबिनेट का गठन किया था। इसके बाद प्रदेश में लगभग 1250 नई गौशालाओं का निर्माण किया गया है। इनमें निराश्रित गायें रखी जाती हैं। सरकार ने प्रदेश में 2000 गौशालाओं का निर्माण का लक्ष्य तय किया था, लेकिन उनमें से करीब 750 का निर्माण अभी नहीं हो सका है। अब इनका निर्माण रोक दिया गया है। इसकी वजह मप्र गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को मिली वह शिकायतें है जिनमें कहा गया है कि इनमें से करीब आधा सैकड़ा गौशालाएं ऐसी हैं, जिनमें एक भी गाय नहीं हैं, फिर भी उनमें गायों के नाम पर अनुदान लेकर हजम किया जा रहा है। इन गौशालाओं को हर दिन एक गाय पर 20 रुपए के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है।

आयोग के पास इस तरह की शिकायतें रायसेन, नरसिंहपुर और रीवा जिले की करीब 50 गौशालाओं की मिलीं हैं। इसके बाद से ही अब गौपालन बोर्ड द्वारा सभी 1250 गौशालाओं का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि गौशालाओं में गायों की वास्तविक संख्या पता करने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है, उन सभी में निराश्रित गायें पाली जा रही हैं या नहीं। इस दौरान जिन गौशालाओं में गायें नहीं मिलेंगी, उनका अनुदान बंद कर उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में फिलहाल करीब 1900 गौशालाएं संचालित हैं। इनमें करीब 3.25 लाख निराश्रित गायें पाली जा रही हैं। इनमें से 650 गायें गौपालन बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जिनका संचालन निजी समितियों द्वारा किया जा रहा है। इनमें करीब 2 लाख गायें होने की जानकारी है। इसी तरह से गौपालन बोर्ड द्वारा बनाई गईं 1250 गौशालाओं में करीब सवा लाख निराश्रित गायें पाली जाने का दावा है। इनके संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायतों के पास है।

सरकार द्वारा इन गौशालाओं के संचालन के लिए हर साल करीब 237 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में इस समय करीब निराश्रित गौवंश की संख्या करीब 10 लाख है। पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर जिले के सालरिया गौ-अभयारण्य में गौ कैबिनेट के गठन की घोषणा की थी। इसमें पशुपालन, कृषि, पंचायत, वन, गृह और राजस्व विभाग को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में गायों के संवर्धन एवं संरक्षण करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 हजार गौशालाओं के निर्माण और गौवंश संरक्षण के लिए गौ-अधिनियम बनाने की बात भी कही थी।

● **अरविंद नारद**

हाईटेक गौशालाएं भूली सरकार

अगस्त, 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की पहल पर कुमार मंगलम बिड़ला ने मप्र में डेढ़ साल के अंदर 100 हाईटेक गौशालाएं बनाने की सहमति दी थी, लेकिन ये गौशालाएं नहीं बन पाईं, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार गौशालाओं के निजी निवेश को लेकर भूमि आवंटन की पॉलिसी ही नहीं तैयार कर पाई थी। सरकार बदलते ही यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। सरकार गौशाला में गायों की देखरेख के लिए हर दिन 20 रुपए प्रति गाय अनुदान देती है। राजधानी भोपाल में सरकारी अनुदान पर चलने वाली 33 गौशालों में 6500 गौवंश है। लेकिन फिलहाल इन गौशालाओं को फंड नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन गौशालाओं का संचालन भगवान भरोसे ही चल रहा है। उपसंचालक पशुपालन अजय रामटेके का कहना है की हमने गायों को दिए जाने वाले अनुदान के लिए सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक हमें भी फंड नहीं मिला जिसके चलते गौशालाओं को अनुदान मिलने में देरी हुई है। पैसे आते ही गौशालाओं को अनुदान दिया जाएगा।

नर्मदा परियोजनाएं पकड़ेंगी रफ्तार

मप्र सरकार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से नर्मदा की दस परियोजनाओं के लिए करीब 12,500 करोड़ का नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। यह वे परियोजनाएं हैं, जिनके समय पर पूरा नहीं होने की वजह से मप्र को अपने हिस्से के पानी को गंवाना पड़ सकता है। सरकार की लेटलतीफी की वजह से यह परियोजनाएं अब तक शुरू ही हो सकी हैं, जबकि इनसे 2024 तक पानी लिए जाने का लक्ष्य है। अब इन परियोजनाओं के लिए आधा दर्जन वित्त संस्थाओं से कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। इन संस्थाओं में शामिल नाबार्ड से करीब चार हजार करोड़, बैंक आफ महाराष्ट्र से डेढ़ हजार करोड़, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से करीब सात हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से पहले दौर की चर्चा की जा चुकी है। इस चर्चा में इन संस्थाओं द्वारा कर्ज देने के लिए उनकी प्रारंभिक सहमति भी मिल चुकी है।

दरअसल प्रदेश की जीवनदायनी नदी नर्मदा के जल बंटवारे को लेकर मप्र के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच वर्ष 2024 में पुनर्विचार होना है। इसके लिए जरूरी है कि मप्र अपने हिस्से के 3.7 एमएएफ पानी का उपयोग कर ले, नहीं तो उसके हिस्से के पानी की कटौती कर उसे अन्य राज्यों को दे दिया जाएगा। हालांकि जिस गति से मप्र में काम हो रहा है उससे समय रहते पूरा उपयोग हो पाना नामुमकिन ही लगा रहा है। दरअसल सरकार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। इसकी वजह से कुछ परियोजनाएं आधी-अधूरी हैं तो बजट के अभाव में 10 परियोजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई हैं। यही नहीं हालात यह हैं कि दो एमएएफ पानी लेने के प्रोजेक्ट के टेंडर ही नहीं हो पाए हैं। करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट का काम लगभग 70 फीसदी अधूरा है। भुगतान के अभाव में ठेकेदारों द्वारा काम बेहद धीमी गति से किया जा रहा है।

नर्मदा नदी पर बनने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। अभी तक सफेद हाथी साबित हो रही नर्मदा परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार बड़ी राशि का लोन भी लेने जा रही है।

किस राज्य के हिस्से में कितना पानी

नर्मदा जल विवाद अभिकरण ने वर्ष 1979 में चारों राज्यों के बीच नर्मदा के पानी का बंटवारा किया था। तब मप्र के हिस्से में 18.25 एमएएफ, गुजरात के नौ एमएएफ, महाराष्ट्र के 0.25 एमएएफ और राजस्थान के हिस्से में 0.50 एमएएफ पानी आया था। मप्र इसमें से वर्तमान में 14.55 एमएएफ पानी का उपयोग कर पा रहा है। यानी 3.7 एमएएफ पानी का उपयोग नहीं हो रहा है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पैसों के अभाव में आठ बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर रोक रखा है। इन प्रोजेक्ट की लागत करीब 27 हजार करोड़ के आसपास मानी जा रही है। इसकी वजह है टेंडर जारी होने पर 150 करोड़ रुपए तत्काल लगेंगे। इन प्राजेक्ट को पूरा होने में चार से पांच साल लग सकते हैं, क्योंकि वन पर्यावरण सहित तमाम तरह की अनुमतियां लेनी होंगी। इन प्रोजेक्ट के पूरे होने पर प्रदेश में करीब पांच लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। हालत यह है कि ठेकेदारों को हर माह 800 करोड़ की जगह महज 300 करोड़ का ही भुगतान हो पा रहा है। फिलहाल नर्मदाघाटी विकास विभाग का बजट ही 3500 करोड़ है।

सभी परियोजनाओं से नर्मदा नदी से लगभग 25 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होना है। इसमें 13 लाख हैक्टेयर सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग के जरिए विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के भी कई निर्माण कार्य काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं कई परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। इनमें चिकी वोरास बैराज नरसिंहपुर, शंकर पेंच जिक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दूधी परियोजना नरसिंहपुर, अपर नर्मदा परियोजना डिंडौरी, हाडिया बैराज हरदा, राघवपुर बहुउद्देश्यीय डिंडौरी, बसानिया मंडला, होशंगाबाद बैराज होशंगाबाद, कुक्षी परियोजना धार और सांवेर उद्वहन इंदौर। मप्र 2024 तक 18.25 एमएएफ पानी नहीं ले पाता है तो बाकी पानी गुजरात के कोटे में चला जाएगा। इसके बाद मप्र नर्मदा से कोई भी परियोजना लॉन्च कर पानी नहीं ले सकेगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने पानी का बंटवारा कर मप्र के अलावा गुजरात को 9 एमएएफ, महाराष्ट्र को 0.50 एमएएफ और राजस्थान को 0.25 एमएएफ पानी देने का निर्णय किया है।

दरअसल, इसके लिए प्रस्तावित 21 सिंचाई परियोजनाओं में से एक भी पूरी नहीं हुई है। इनमें से 10 परियोजनाओं को पिछले साल (वर्ष 2020) में मंजूरी दी गई थी, पर अब तक इनके टेंडर तक जारी नहीं हुए हैं। जबकि पहले से निर्माणाधीन 11 परियोजनाओं का निर्माण कार्य सरकार की माली हालत खराब होने के कारण अटका हुआ है। इसी तरह बीते पांच साल में 21 परियोजनाओं की घोषणा की गई। जिनमें से एक भी चालू नहीं हो पाई है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

75 एकड़ में मेट्रो डिपो

मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब एमआर-10 से लेकर रिंग रोड तक नजर आने लगा है। वहीं 25 मेट्रो ट्रेन के 75 कोच खरीदने के भी 683 करोड़ रुपए के टेंडर पिछले दिनों जारी किए गए। वहीं सुपर कॉरिडोर पर 75 एकड़ पर विशाल डिपो निर्मित होना है, जिसकी ड्राइंग-डिजाइन के साथ मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर बुलवाए हैं। 284 करोड़ का यह टेंडर है। वन विभाग से लगभग 60 एकड़ जमीन हासिल करने के साथ 6 एकड़ से अधिक जमीन गांधी नगर गृह निर्माण संस्था से भी इस डिपो के निर्माण हेतु ली जा रही है। इस डिपो में ही इंदौर प्रोजेक्ट के तहत दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन खड़ी होगी और सर्विस स्टेशन सहित अन्य सुविधाएं भी यहां पर रहेगी। एक बड़ा एडमिस्ट्रेशन ब्लॉक भी बनेगा और तकनीशियन और अन्य कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर भी निर्मित किए जाएंगे। अभी पहले चरण में मेट्रो का काम एयरपोर्ट से शहीद पार्क तक दिलीप बिल्डकॉन को सौंपा गया है, जिसके चलते आधा दर्जन से अधिक पिलर भी तैयार हो गए हैं।

इंदौर मेट्रो का पहला चरण 2023 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और कलेक्टर मनीष सिंह भी लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते ठप पड़े प्रोजेक्ट में गति भी आई। वहीं मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने 2661 करोड़ के टेंडर भी पिछले दिनों जारी किए गए, जिसमें कोच के साथ सिग्नल, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंस्टॉलेशन सहित अन्य कार्य होना है। वहीं 284 करोड़ रुपए का टेंडर डिपो निर्माण के लिए भी जारी कर दिया है। 75 एकड़ पर बनने वाली इस डिपो की डिजाइन तैयार हो गई है और टेंडर मंजूरी के साथ सुपर कॉरिडोर पर इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। गांधी नगर क्षेत्र में वन विभाग की 28 एकड़ जमीन डिपो निर्माण के लिए ली गई और इसके बदले विभाग को अन्य जमीन उपलब्ध करवाई गई है।

इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के उप महाप्रबंधक अनिल जोशी के मुताबिक जल्द ही सुपर कॉरिडोर पर मेट्रो रेल डिपो का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके टेंडर रेल कार्पोरेशन ने जारी कर दिए हैं। 2092 दिन कार्य समाप्ति की अवधि तय की गई है। वन विभाग की जमीन के अलावा लगभग 6 एकड़ जमीन गांधी नगर संस्था से भी हासिल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दिलीप बिल्डकॉन को दिए गए ठेके की अवधि पूर्व में भी समाप्त हो गई थी, जिसे अगस्त-2023 तक बढ़ाया गया, क्योंकि कोविड के चलते भी मेट्रो प्रोजेक्ट ठप पड़ा रहा। अभी गांधीनगर से चंद्रगुप्त चौराहा और वहां से एमआर-10, विजय नगर से रिंग रोड तक का काम तेज गति से चल रहा है। एमआर-10 पर तो मेट्रो प्रोजेक्ट के कई पिलर नजर भी आने लगे हैं। अब सभी निर्माण एजेंसियों के बीच तालमेल भी सुधर गया और भोपाल की अफसर छवि भारद्वाज भी दो मीटिंग इंदौर आकर ले चुकी हैं। एमआर-10 ब्रिज से शहीद पार्क तक मेट्रो निर्माण की गतिविधि चल रही है। पिछले दिनों बिजली लाइन भी शिफ्ट कर दी गई और सेंट्र डिवाइडर पर बने ग्रीन कॉरिडोर को भी निगम ने हटा दिया। डिवाइडर कुछ जगह बचे हैं, उन्हें भी काम के साथ हटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 5.29 किलोमीटर के इस हिस्से में 182 पिलर बनना है। पिछले दिनों 2661 करोड़ का जो टेंडर आमंत्रित किया था उसमें 156 मेट्रो कार, जिसे कोच कहा जाता है, के अलावा टेस्टिंग, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन सहित अन्य कार्य होना है। इसमें 683 करोड़ की राशि से इंदौर में दौड़ने वाली 25 मेट्रो ट्रेन के 75 कोच भी शामिल हैं। सुपर कॉरिडोर पर जो विशाल डिपो बनेगा उसी में ये सारे कोच रात में खड़े रहेंगे, जहां पर सर्विस स्टेशन से लेकर अन्य सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। सुपर कॉरिडोर के अलावा अब रिंग रोड पर भी प्रोजेक्ट की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। यहां भी पिलरों का निर्माण आने वाले दिनों में नजर आने लगेगा।

मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जहां एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर और उसके पूरे ट्रैक में तमाम विभागों की जमीनें शामिल हैं। प्राधिकरण ने तो सुपर कॉरिडोर पर जमीन उपलब्ध करवाई ही है, वहीं गांधी नगर में विशाल डिपो का काम जल्द शुरू होना है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्से में भी कुछ समय पूर्व मेट्रो रेल कंपनी ने लालबाग क्षेत्र में जमीन का आवंटन मांगा था। महू नाका के पास मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन मांगी गई, जो लगभग 19 हैक्टेयर थी। इसमें इंदौर कस्बे की खसरा नंबर 997 से लेकर 1000 और अन्य नंबरों की जमीनें मेट्रो प्रोजेक्ट की आवश्यकता के लिए मांगी गई। मगर जब प्रशासन ने इन जमीनों की स्थिति पता की तो मालूम पड़ा कि यह जमीन लालबाग के आसपास स्थित है और लालबाग भी पुरातत्व विभाग के पास ही है। लिहाजा जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। मगर अब दूसरे चरण की कवायद शुरू होने के साथ पश्चिमी क्षेत्र में भी डिपो के लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी।

गांधी नगर से आईएसबीटी तक पाइलिंग का काम पूरा होने के साथ अन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्राधिकरण द्वारा जो आईएसबीटी कुमेर्डी में बनाया जा रहा है उसके साथ मेट्रो स्टेशन जुड़ेगा और साढ़े 5 किलोमीटर ट्रैक पर पाइलिंग का काम शुरू हो गया है। गांधी नगर से आईएसबीटी होते हुए शहीद पार्क के ट्रैक के लिए भी टेंडर हो चुके हैं और दूसरे तरफ का जिम्मा आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम को मिला है।

● **विकास दुबे**

1034 करोड़ के नए कार्यों के लिए शिवराज का इंतजार

पिछले दिनों रोबोट चौराहा से लेकर राजवाड़ा और वहां से एयरपोर्ट तक के लिए जो दूसरे चरण का काम होना है उसकी भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई। 1034 करोड़ का ठेका रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल को मिला है। उसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाकर भूमिपूजन कराया जाना था, मगर टंट्या भील के आयोजन में शासन-प्रशासन व्यस्त रहा। अब फिर से प्रयास किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दूसरे चरण के कार्यक्रम के लिए इंदौर आएं, क्योंकि पिछले दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री ने ही मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों की शुरुआत की थी। चूंकि यह काम शहर में होना है। लिहाजा पंचायत चुनाव की आचार संहिता का असर भी नहीं पड़ेगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से शहर यानी निगम सीमा में ही हो रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा के साथ ही उसमें आने वाली समस्याओं को भी लगातार दूर कराया जा रहा है।

मप्र बनेगा निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य

मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में औद्योगिक विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को औद्योगिक निवेश का रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास करना तथा प्रदेश को निवेश की दृष्टि से सबसे आकर्षक राज्य बनाना मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता है। उनका मानना है कि देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर हों। इसलिए आत्मनिर्भर मप्र के लिए चार बिंदुओं पर आधारित रोडमैप बनाया गया है। ये बिंदु हैं भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसके लिए अधोसंरचना और बेहतर संपर्क की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि शुरू से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने पर रहा है। इसके लिए पूर्व के कई इंवेस्टर्स समिट आयोजित किए गए थे। जिनके परिणाम स्वरूप प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है। अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में उद्योगों का इस तरह जाल बिछे कि यहां का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश के लिए वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि निवेशक नियमों के मकड़जाल में न उलझें। उन्हें राज्य में निवेश का उपयुक्त माहौल मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सोमवार का शुरुआती आधे दिन का समय निवेशकों के साथ आमने-सामने की मुलाकात के लिए निर्धारित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही प्रयास है कि आज मप्र तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। गौरवशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मप्र आज अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है। संपूर्ण, समृद्ध और विकसित मप्र के लिए शिवराज अपना सबकुछ समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सुशासन राज्य सरकार का लक्ष्य है। जन-सुविधाएं ठीक ढंग से आम जनता तक पहुंचे और जनता की समस्याएं दूर हों, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। शिवराज के प्रयासों से ही मप्र अब बीमारू के अभिशाप से मुक्त हो गया है। मप्र निवेश के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। यहां बड़े उद्योगों के साथ लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास का प्रकाश आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति और प्रदेश के प्रति समर्पण भाव ही है कि प्रदेश आज विकास के निर्णायक मोड़ पर है। पिछले 17 साल में मप्र में आर्थिक विकास खूब हुआ है। समाज और सरकार की इस जुगलबंदी का परिणाम अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिरता के रूप में मिला है। सुशासन, आर्थिक विकास की तेज रफ्तार और कमजोर वर्गों के विकास के लिए योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। खाली पड़ी औद्योगिक जमीनों पर बार-बार अवैध कब्जे हो जाने की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मप्र औद्योगिक विकास निगम प्रदेश के कई शहरों के इंडस्ट्रियल एरिया में कमर्शियल शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहा है। मप्र औद्योगिक विकास निगम ने प्रदेशभर के इंडस्ट्रियल एरिया में सख्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाकर अपने औद्योगिक भूखंड नाजायज कब्जेधारियों से मुक्त तो करा लिए, मगर इन पर फिर से कब्जे न हों, इसके लिए इन औद्योगिक जमीनों पर छोटे-बड़े मध्यम साइज के कमर्शियल प्लॉट बनाकर इन पर शॉपिंग सेंटर बनाने की दो प्रकार की कार्ययोजना पर काम कर रहा है। पहली योजना के अनुसार खाली पड़े छोटे मध्यम भूखंडों को नीलाम कर दिया जाए। दूसरी प्लानिंग यह है कि इन भूखंडों पर मप्र औद्योगिक विकास निगम खुद कमर्शियल शॉपिंग सेंटर बनाकर उन्हें किराए पर दे दें या टेंडर निकालकर पहले आओ-पहले पाओ के नियमानुसार बेच दे। इस तरह की योजना बनाने के पीछे दो कारण हैं। पहला उद्देश्य यह है कि पिछले कई सालों में एकेवीएन अपनी जमीनों पर कब्जे हटाने की कई बार कार्रवाई कर चुका है। कब्जे हटाने के कुछ महीनों बाद लोग दोबारा कब्जे कर लेते हैं। इस वजह से आए दिन न सिर्फ विवाद होते हैं, बल्कि अवैध कब्जे करने वाले गैरकानूनी काम भी करने लगते हैं। दूसरा मुख्य कारण यह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर औद्योगिक शहर को स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाए। खाली पड़े भूखंडों पर एक जैसी शॉप्स या शॉपिंग सेंटर बनेंगे तो न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया स्मार्ट नजर आएगा, बल्कि अतिक्रमण व कब्जों की समस्या से भी हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी।

● **कुमार विनोद**

मील के पत्थर साबित होंगे एक्सप्रेस-वे

मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो इसके लिए कई योजनाएं-परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। निवेशकों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए अटल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इन एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक केंद्र और टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार उद्योग लगाने के लिए नियम कायदे सहज बनाने का काम किया है और वह कारोबार शुरू करने की लागत कम करने तथा कारोबारी सुगमता को और आसान बनाने पर काम कर रही है।

अधूरे दस्तावेजो में बांट दिया लोन

कई स्तरों पर की गई है गड़बड़ी

अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ का बकरी घोटाला मामला तूल पकड़ रहा है। इस पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही है। जांच के पहले पड़ाव में पशु विभाग, बैंक, बीमा एजेंट, पशु चिकित्सक और वेंडर की मिलीभगत सामने आई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि बैंक ने लोन की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही लोन स्वीकृत कर दिया जबकि बैंक को पहले पशुपालन विभाग को जानकारी और हितग्राहियों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और विभागीय पत्र लेना चाहिए था। सिर्फ बैंक ही नहीं वेंडर ने भी बीमा एजेंट, बैंककर्मियों और पशु पालन विभाग के साथ मिलकर विभागीय प्रमाण पत्र के बिना ही हितग्राहियों को कम बकरियां बांट दी गई और फोटो खिंचवाने के बाद हितग्राहियों को मांग के चेक देकर दूसरे हितग्राहियों को बकरियां बांट दी गईं। ऐसा ही कई हितग्राहियों के साथ किया जा रहा है। जांच में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि बैंक ने हितग्राहियों के खाते की राशि वेंडर के खाते में डाल दी वहीं 2 साल बाद बैंक ने लोन की राशि चुकाने के लिए आनन-फानन में नोटिस जारी कर दिया। जिसके बाद हितग्राहियों ने अनूपपुर कलेक्टर से शिकायत की और इस विषय में जांच पड़ताल शुरू की गई। उपसंचालक पशुपालन और डेयरी विभाग का कहना है कि बैंक से पूरे दस्तावेजों को मिलाने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी कि हितग्राहियों को कितनी राशि दी गई है और कितने का लोन किया गया था।

पशु पालन विभाग द्वारा बकरी ईकाई योजना में वर्ष 2018-21 के दौरान अनूपपुर जिले में बांटे गए लोन में जिम्मेदारों ने आधे-अधूरे कागजी दस्तावेजों को जमाकर लोन राशि का वितरण कर दिया। जिसमें बैंक ने जहां विभाग द्वारा बिना स्वीकृत सब्सिडी की राशि वाली लोन राशि को हितग्राही के नाम कर दिया, वहीं पशु पालन चिकित्सक और बीमा कंपनी व बैंक अधिकारियों ने बिना कमेटी सदस्यों के बीच हितग्राही को बांटी गई बकरियों की तस्वीर प्रमाणिक रूप में दस्तावेज के साथ संलग्न कर कर्जदार बना दिया। जबकि प्रावधानों के अनुसार वेंडर द्वारा हितग्राहियों को दिए गए बकरियों के दौरान बैंक अधिकारी, बीमा कंपनी, पशु चिकित्सक, पंचायत सरपंच, वेंडर और हितग्राही के साथ साक्षी की उपस्थिति अनिवार्य थी। लेकिन यहां वेंडर और हितग्राही के साथ बकरियों की तस्वीर लगी पड़ी हैं। इसके अलावा हितग्राहियों से संयुक्त टीम की जांच विवेचना में लिए गए बयान में हमेशा अस्थिरता आई, जिसमें वेंडर द्वारा कम संख्या में बकरियां देकर कम पैसों में उससे खरीदी के मामले भी सामने आए हैं। वहीं दो हितग्राहियों के नाम बैंक ने लोन जारी नहीं किया, और उनके नाम लोन के कर्ज में शामिल हो गया है।

माना जाता है कि लोन प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदारों ने सुनियोजित तरीके से लोन का वितरण किया, जिसमें अधूरी कागजी कार्रवाई के साथ लोन वितरण की प्रक्रिया के बाद हितग्राहियों को बकरियों को बांटा। जिसमें वेंडर ने बकरियों की खरीद फरोख्त में अहम भूमिका निभाई। वहीं अब उपसंचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग ने कलेक्टर को अनंतिम जांच प्रतिवेदन सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए दस्तावेज में शिकायतकर्ताओं के दिए शिकायत व हितग्राहियों के नामों के अनुसार विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम की संयुक्त जांच कार्रवाई और बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज को शामिल किया है। अधिकारी का कहना है कि जांच टीम द्वारा दर्ज किए गए बयानों और विभाग को बैंक से मिले दस्तावेजों में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पशु पालन विभाग की बकरी ईकाई योजना में सभी जिम्मेदारों ने सुनियोजित तरीके से बैंक के लोन और विभागीय अनुदान की राशि में गड़बड़ी की है। इसमें विभागीय पशु चिकित्सक के साथ बैंक, हितग्राही, वेंडर, गांव के प्रधान के साथ गवाहों की भूमिका संदिग्ध मानी गई है।

विभाग को बैंक से मिले दस्तावेजों में हितग्राहियों के नाम ऋण वितरण उपरांत निरीक्षण, बकरी प्रदाय आदेश, बीमा कंपनी की बीमा पॉलिसी, संतुष्टि एवं सहमति अदाएगी, कोटेशन के दस्तावेजों पर लोन वितरण कमेटी के जिम्मेदारों के हस्ताक्षर के साथ गवाहों के भी समर्थन दर्ज है। यहीं नहीं बैंक ने दस्तावेजों में हितग्राहियों के घरों पर बैंक ऋण वितरण उपरांत निरीक्षण में दर्ज बयान में बताया है कि हितग्राही द्वारा पशु एवं आहार सामग्री का क्रय कर लिया गया है, निरीक्षण में सही पाया गया। हितग्राही पूर्ण रूप से सहमत और संतुष्ट है। इस आशय के तहत बकरी सप्लायर को भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा बकरियों के पशु विभाग के स्वास्थ्य प्रमाण के साथ पाने और किसी प्रकार की कोई और बकरी नहीं पाने और पशु विभाग एवं बैंक के दिए निर्देशों का पालन करने और कर्ज चुकाने पर भी अपनी सहमति प्रदान की है। लेकिन अब हितग्राहियों के पास बकरियां ही नहीं हैं। जबकि योजना में उपलब्ध कराए गए बकरियों के बच्चों को पालन कर उसे बेच लोन का कर्ज चुकाने के प्रावधान थे।

पूरी जांच प्रक्रिया और बैंक द्वारा सौंपे गए खुद के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है। जिसमें पुष्पराजगढ़ के 19 केस में 10 हितग्राहियों की शिकायत में 3 हितग्राही के बिना सब्सिडी के लोन जारी किए गए हैं। 2 हितग्राहियों को सब्सिडी जारी होने बाद भी लोन बैंक से वितरित ही नहीं हुआ। 5 हितग्राहियों को जारी सब्सिडी में 1 ने राशि निकाल ली। 2 हितग्राहियों की सब्सिडी बैंक ने एफडी कर दी, और 2 हितग्राही संतुष्ट है। अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीणा कहती हैं कि जांच प्रतिवेदन मिला है, इसका अवलोकन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उपसंचालक पशु व डेयरी विभाग अनूपपुर डॉ. वीपीएस चौहान कहते हैं कि बैंक के दस्तोवज के साथ हितग्राहियों के कथन व जांच टीम की रिपोर्ट को अनंतिम जांच प्रतिवेदन के रूप में कलेक्टर को सौंपा गया है। एलडीएम के दस्तावेजों की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रथम दृष्टया में लोन प्रकरण में सभी जिम्मेदार दोषी नजर आ रहे हैं।

● **बृजेश साहू**

पुलिस कमिश्नर प्रणाली पावर के साथ चुनौतियां भी

आखिरकार 40 साल बाद मप्र के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। इस प्रणाली के लागू होने से जहां पुलिस अधिक पावरफुल हुई है, वहीं उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। अब भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर पर जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधिकारों का तेजी और ताकत के साथ उपयोग करें और प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों की जनता के मन में विश्वास पैदा करें। राजधानी भोपाल व प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति के साथ ही अब पुलिस विभाग के पास इन शहरों में अपराध पर नियंत्रण को लेकर कोई बहाना नहीं बचा। अब तक यह होता रहा है कि जब भी अपराध बढ़े, पुलिस विभाग की ओर से दबी जुबान में यह सवाल उठाया गया कि हमारे हाथों में ज्यादा कुछ नहीं है।

● राजेंद्र आगाल

देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से आखिरकार मप्र के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। जानकारों का कहना है कि मप्र में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली देश की सबसे अच्छी प्रणाली है। वहीं दोनों शहरों की कमान सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है। भोपाल की कमान 1997 बैच के आईपीएस मकरंद देउस्कर को और इंदौर की कमान 2003 बैच के आईपीएस हरिनारायणचारी मिश्र को सौंपी गई है। दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही वहां की करीब 50 लाख आबादी को उम्मीद जगी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अब सुदृढ़ होगी। वैसे भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही भले ही पुलिस का पावर बढ़ा है, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि सरकार और जनता के विश्वास पर दोनों शहरों के अफसर कितने खरे उतरते हैं। हालांकि अभी नए ढांचे में ढलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही।

ऐसा होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस का सिस्टम बदल जाएगा। अब राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर ही जिले का सर्वोच्च पुलिस अफसर होगा। इसे अब हम पुलिस कप्तान भी कह सकते हैं, जो पहले भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में आईजी हुआ करते थे। यह एकमात्र पद होगा। वहीं 2 एसीपी यानी अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर होंगे। ये सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। इनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होंगी। ये डीआईजी रेंज के अफसर होंगे। एक एसीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सिस्टम देखेंगे तो दूसरे क्राइम और हेडक्वार्टर का जिम्मा। शहर में आठ डीसीपी यानी आठ एसपी हो जाएंगे। अभी ये तीन हुआ करते थे लेकिन डायरेक्ट फील्ड में दो ही रहते थे। आठ एसपी होने पर यातायात, क्राइम, हेडक्वार्टर, इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी आदि की जिम्मेदारी अलग-अलग डीसीपी के पास होगी। शहर में एडिशनल एसपी लेवल के 12 अफसरों की पोस्टिंग एडिशनल डीसीपी के रूप में हो जाएगी। ये अलग-अलग मामलों को लेकर डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। इनसे यातायात, क्राइम, हेडक्वार्टर संबंधी काम, आम लोगों के लिए जागरुकता कार्यक्रम, सिक्योरिटी, एससी-एसटी महिलाओं से जुड़े अपराध देखने होंगे। सीएसपी लेवल के 29 सहायक पुलिस आयुक्त होंगे। ये एडिशनल एसपी को रिपोर्ट करेंगे। इनमें से 29 फील्ड ऑफिसर होंगे जबकि 1 रेडियो का जिम्मा संभालेंगे। इन अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर जिले की कानून व्यवस्था को संचालित करेंगे। फिलहाल कमिश्नर के सामने चुनौती होगी कि वे पुलिस बल को समन्वयकारी बनाएं। यानी पुलिस जनसहयोगी बने। हालांकि कोरोना संक्रमणकाल में पुलिस के जनसहयोगी रूप को सबने देखा है। अब कोशिश है कि पुलिस का यही रूप हमेशा कायम रहे, ताकि जनता अपनी समस्याएं लेकर पुलिस के पास आने से हिचके नहीं।

गौरतलब है कि करीब 40 सालों से मप्र में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का इंतजार हो रहा था। अब जाकर यह इंतजार खत्म हुआ है। सरकार ने भोपाल का पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को और इंदौर का पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र को बनाया है। अब इन दोनों अधिकारियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधिकारों का तेजी और ताकत के साथ उपयोग करें और प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों में अपराध कम करके दिखाएं। राजधानी भोपाल व प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति के साथ ही अब पुलिस विभाग के पास इन शहरों में अपराध पर नियंत्रण को लेकर कोई बहाना नहीं बचा। अब तक यह होता रहा है कि जब भी अपराध बढ़े, पुलिस विभाग की ओर से दबी जुबान में यह सवाल उठाया गया कि हमारे हाथों में ज्यादा कुछ नहीं। इस सवाल का इशारा आईएएस अफसरों के पास निहित मजिस्ट्रियल अधिकारों की ओर होता रहा और इसी की आड़ में पुलिस विभाग अन्यमनस्क मन:स्थिति में बना रहा। किंतु अब पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति के साथ ही यह **अन्यमनस्कता** टूटनी चाहिए। अब यह तय हो चुका है कि यदि भोपाल में अपराध बढ़े तो नव-नियुक्त पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर और इंदौर में अपराध बढ़े तो हरिनारायणाचारी मिश्र से सवाल पूछे जाएंगे। अब इन दोनों बड़े शहरों में अपराधों पर नियंत्रण की कमान, अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी सबकुछ इन दोनों अफसरों पर है।

क्या है कमिश्नर प्रणाली

कमिश्नर प्रणाली के गुण-दोष और जरूरतों पर चर्चा से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार कमिश्नर प्रणाली क्या है? कमिश्नर प्रणाली को आसान भाषा में समझें तो अभी तक दोनों शहरों के पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते थे। वो आकस्मिक परिस्थितियों में कलेक्टर, संभागीय कमिश्नर या शासन के दिए निर्देश पर ही काम करते थे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ये अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल गए हैं। इसमें शहर में धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना, दंगे के दौरान लाठीचार्ज या कितना बल प्रयोग हो ये निर्णय सीधे पुलिस ही करेगी। यानी उनके अधिकार और ताकत बढ़ गए हैं। पुलिस खुद फैसला लेने की हकदार हो गई है। ऐसा क्यों माना जाता है कि कानून व्यवस्था के लिए कमिश्नर प्रणाली ज्यादा बेहतर है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर कोई भी निर्णय खुद ले सकते हैं। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में ये अधिकार जिलाधिकारी के पास होते हैं। यही नहीं पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से अब पुलिस का बल भी बढ़ जाएगा। शहर को जोन में बांट दिया गया है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती की गई है।

बता दें भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत जिलाधिकारी यानी कलेक्टर के पास पुलिस को कंट्रोल करने के अधिकार होते हैं, जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस विभाग को मिल गए हैं। यानी जिले की बागडोर संभालने वाले कलेक्टर के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल गए हैं।

जानकारों के अनुसार कमिश्नर प्रणाली प्रशासन की सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। जिन शहरों में यह प्रणाली लागू है, वहां कानून व्यवस्था से संबंधित निर्णय तत्काल किए जाते हैं। इसलिए मप्र के इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से लोगों में विश्वास जगा है कि अब उन्हें त्वरित न्याय मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक देशभर में दिल्ली, उप्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, असम, हरियाणा, नागालैंड, ओडिसा के 77 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इनमें डीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थ किया जाता है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरू में डीजी स्तर की पुलिस कमिश्नर प्रणाली है जबकि चेन्नई और कोलकाता में सबसे पुरानी पुलिस कमिश्नर प्रणाली होने के बाद भी यहां अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस कमिश्नर बनाए जाते रहे हैं।

कमिश्नर प्रणाली की मांग वर्षों से

देश के लगभग सभी बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। मप्र में इंदौर और भोपाल में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग वर्षों से होती रही है। लेकिन जब से ये दोनों शहर मेट्रोपॉलिटिन सिटी के रूप में बदले हैं, तब से इसकी मांग तेज हो गई थी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इंदौर और भोपाल में इस प्रणाली की जरूरत लंबे समय से अनुभूत की जा रही थी। जब-जब दिल दहला देने वाला कोई बड़ा हत्याकांड होता, सुर्खियां बटोरने वाली बड़ी डकैती डलती या फिर शर्मिंदा करने वाला दुष्कर्म का कोई मामला

पुलिस को मिलेंगे यह अधिकार

कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस को कई अधिकार मिलेंगे। मेट्रोपोलिटिन में पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। वे डीजीपी के नियंत्रण व परिवेक्षण में रहेंगे। जेल में बंद कैदियों को पैरोल और आपातकाल में पैरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जाएगा। गैरकानूनी जहर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी पर से बरामद जहर या तेजाब जब्त किया जाएगा। वैश्यावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस पेशे में धकेली गई महिलाओं को मुक्त कराया जा सकेगा। संरक्षण गृह में भेजा जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रुकने के स्थान अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित किए जा सकेंगे। वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी। गुंडे-बदमाशों को और ऐसे अपराधी तत्वों के गैंग और आदतन अपराधियों को जिलाबदर किया जा सकेगा। सरकारी गोपनीय दस्तावेज रखने और इस अधिनियम के विरुद्ध की गई गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे पुलिस अब तेजी से काम करेगी। किसी भी तरह की स्थिति में पुलिस अधिकारी त्वरित निर्णय ले सकेंगे।

रासुका लगाने के पावर अभी नहीं

रासुका के अधिकार पुलिस कमिश्नर को अभी नहीं दिए गए हैं। भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर को भी 1 जनवरी 2022 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के उपयोग का अधिकार मिल सकता है। इसी दिन इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद प्रदेश के 52 कलेक्टरों और दो पुलिस कमिश्नरों के पास एनएसए के उपयोग का अधिकार होगा। अभी यह अधिकार कलेक्टरों के पास है। राज्यों को एनएसए के अधिकार केंद्र सरकार देती है। राज्य हर तीन माह के लिए यह अधिकार कलेक्टरों को देते हैं। अभी दिसंबर तक के अधिकार कलेक्टरों को मिले हैं।

पुलिस कमिश्नर का नया कुनबा

भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के साथ ही अधिकारियों के ऑफिस की व्यवस्थाएं भी तेजी से की जा रही हैं। पुलिस की पुरानी और नई बिल्डिंग में अधिकारियों के ऑफिस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस ऑफिस में अफसरों की कोर्ट भी होंगी, जहां वे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। नए पुलिस कंट्रोल रूम की बिल्डिंग में पुलिस कमिश्नर के अलावा दोनों एडिशनल पुलिस कमिश्नर के ऑफिस भी होंगे। पुराने डीआईजी ऑफिस में आईजी देहात और डीआईजी देहात के ऑफिस होंगे। यह ऑफिस अगले आठ से दस दिन में तैयार हो जाएंगे। भोपाल में पुलिस द्वारा अपने बजट से ही ऑफिस तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस को अलग से बजट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। कई ऑफिसों से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। अफसरों का तर्क है कि उनके पास खुद की बिल्डिंग हैं, केवल उनका रिनोवेशन कर व्यवस्थित ऑफिस तैयार करना है। भोपाल में जिन अफसरों की पोस्टिंग होगी, उनके वाहनों की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि उन्हें पहले से ही पुलिस मुख्यालय से वाहन आवंटित हैं। पुराने डीआईजी ऑफिस में आईजी देहात और डीआईजी देहात के ऑफिस होंगे। अफसरों को वाहन पहले से आवंटित, पीएचक्यू को अलग व्यवस्था नहीं करना पड़ेगी।

घटित होता, तब-तब पुलिस पर प्रश्न उठते। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग उठती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपने चौथे कार्यकाल में यह करना संभव हो पाया है। उनके पहले कार्यकाल में 2008 में पहली बार ऐसी उम्मीद जागी थी। तब उपसमिति की रिपोर्ट में हरी झंडी मिलने के बाद भी निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेज दी थी। तब मंत्रिमंडलीय उपसमिति में जयंत मलैया, हिम्मत कोठारी, नरोत्तम मिश्रा और नागेंद्र सिंह थे और मलैया की अध्यक्षता में बनी उपसमिति ने चुनावी साल में रिपोर्ट सौंपी थी।

शिवराज सिंह चौहान ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी फरवरी 2012 में विधानसभा सत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने का ऐलान किया था। मगर तब भी मामला उससे आगे नहीं बढ़ा और घोषणा तक ही रह गया। उनके तीसरे कार्यकाल में भौंरी पुलिस अकादमी में भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस पर विचार की बात कहकर पुलिस को उम्मीद जगाई थी। तब वहां गृह विभाग के आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे और आईएएस लॉबी ने इस विचार को पंचर कर दिया था। पुलिस सुधार के नाम पर त्रिखा कमेटी बनाई गई थी तो पीएचक्यू में एक वरिष्ठ अधिकारी को ही पुलिस सुधार शाखा में बैठा दिया गया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विचार आते ही पुलिस के कुछ अधिकारियों को प्रस्ताव बनाए जाने का काम भी समय-समय पर सौंपा गया था। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संजय राणा से लेकर मौजूदा एडीजी संजीव शमी तक ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले शहरों का अध्ययन कर उनके बेहतर बिंदुओं के आधार पर प्रस्ताव बनाए लेकिन उनका हश्र रद्दी की कोठरी में ही हुआ।

दिग्विजय सिंह के दस साल के मुख्यमंत्रित्वकाल में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम के प्रस्ताव दो बार आए और राजनीतिक **इच्छाशक्ति की कमी** के चलते उनका हश्र अच्छा नहीं रहा। एक बार उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जो वहां काफी समय तक लंबित रहा और आखिरकार निरस्त कर लौटा दिया था। सुभाषचंद्र त्रिपाठी के डीजी रहते उन्होंने पुलिस सुधार के लिए तब राजेंद्र चतुर्वेदी को काम सौंपा था जिसमें पांच लाख आबादी वाले शहरों में इस सिस्टम को लागू करने की रिपोर्ट दी थी। मगर उस रिपोर्ट पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमोबेश कमलनाथ सरकार के समय भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की भ्रूण हत्या हो चुकी है। उस समय स्वतंत्रता दिवस में मुख्यमंत्री के संबोधन में इसका ऐलान होने की चर्चा थी लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में वह शामिल ही नहीं किया गया। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने हिम्मत दिखाई और **40 साल का सूखा** खत्म करते हुए कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया।

अब पुलिस के पास कई अधिकार

अब जनता की चेष्टा रहेगी कि पुलिस कमिश्नर अपने अधिकारों का पूरी क्षमता और तेजी से उपयोग करें, पुलिस विभाग में डाउन-लाइन अर्थात् मैदानी अमले तक में उत्साह जगाएं और अपराध पर नियंत्रण की नई इबारत लिख दें। सनद रहे कि जनता के सामने इंदौर, भोपाल के कमिश्नरों के कामकाज की तुलना के लिए मुंबई, लखनऊ, वाराणसी सहित कुछ अन्य शहरों के उदाहरण सामने रहेंगे। एक बात और है, जिसकी जिम्मेदारी मकरंद देउस्कर और हरिनारायणचारी मिश्र पर होगी, और वह यह कि वे अपनी कमिश्नरी को जितना सफल साबित करेंगे, उतनी अधिक संभावना जबलपुर और ग्वालियर में भी इस प्रणाली को लागू करने की बनेगी। वैसे तो इन दोनों शहरों में भी इंदौर, भोपाल के साथ ही इस प्रणाली को लागू कर दिया जाना चाहिए था, किंतु अब शासन को ऐसा करने का साहस और बल देने का आधार इंदौर और भोपाल के कंधों पर होगा।

अगर मप्र की कमिश्नर प्रणाली की तुलना दूसरे राज्यों से करें तो हम पाते हैं कि राजस्थान में एसीपी को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांतिभंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी हैं। इन मामलों में जमानत देने या न देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिलाबदर करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार हैं। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर में पुलिस कमिश्नर ही देता है। उप्र के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकार भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं। लेकिन मप्र में कमिश्नर को सीआरपीसी की धारा 133 का अधिकार नहीं मिला है, लेकिन पुलिस एक्ट 34 उसके पास है।

पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग पर रहेगा फोकस

नवागत पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने तीन दिन पहले भोपाल पुलिस के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पहली मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने भोपाल पुलिस के कप्तान होने के नाते एक बात साफ की। उन्होंने कहा कि आप मेरा स्वागत करें या में आपका स्वागत करूं सब को करना काम ही है। टीम वर्क पर फोकस करें, पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग पर ध्यान दें। थानों में आने वाले फरियादियों की इतमिनान के साथ फरियाद सुनें। पुरानी पुलिसिंग के तरीकों से बाहर निकलें। थानों में किसी के भी साथ बदसलूकी की खबरें नहीं आनी चाहिए, ऐसे कोई काम न हों जिससे नए सिस्टम पर उंगली उठाने का किसी को भी मौका मिले। पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने बताया कि कमिश्नर सिस्टम भोपाल पुलिस के लिए नई चुनौती है। फील्ड पर मौजूद अधिकारी स्वयं को इस सिस्टम के अनुसार प्रशिक्षित कर तैयार करें। एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट के जो दायित्व पुलिस को मिले हैं, उन्हें इमानदारी से निभाने भोपाल पुलिस के अधिकारी स्वयं को प्रशिक्षित करने में जुट गए हैं। सीपी ने आगे कहा कि मफियाओं के खिलाफ प्रशासन की मदद लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। चोरी नकबजनी से ज्यादा लोग सायबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। सायबर क्राइम पर अंकुश लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नए सिस्टम के तहत बचे हुए पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। नवागत कमिश्नर ने आमजनों से भी अपील की है कि बिना डरे शहर की पुलिसिंग में मौजूदा कमियों को सीधा उन्हें बताएं। पुलिसिंग को अधिक बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गुंडे-बदमाश और माफियाओं को किसी हाल में नहीं बक्शा जाएगा। पुलिस सूत्रों की मानें तो नवागत सीपी शहर में मौजूद भू-माफिया, ड्रग माफिया, जुआ और सट्टा माफिया सहित अवैध रूप से बड़े पैमाने पर सूदखोरी करने वालों की सूची तैयार करा रहे हैं।

कसौटी पर कमिश्नर प्रणाली

मप्र के दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली तो लागू कर दी गई है, लेकिन अब पुलिस की अग्निपरीक्षा होने वाली है। प्रदेश के इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों में कमिश्नर प्रणाली की सफलता प्रदेश में भविष्य में कमिश्नर प्रणाली के विस्तार और लाभ की एक कसौटी भी साबित होगी। जानकारों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से लोगों को त्वरित न्याय मिलना आसान हो जाएगा। ऐसे में शहर में मामले भी अधिक दर्ज होंगे। अपराधों के आंकड़े भले ही बढ़ें, लेकिन इस प्रणाली से लोगों का विश्वास पुलिस में मजबूत होगा। गौरतलब है कि पुलिस के पास ऐसे बहुत से कानून व्यवस्था के मामले आते हैं, जब जनहित में बहुत तेजी से फैसला लेने की जरूरत पड़ती है। तेजी से फैसला न ले पाने की स्थिति में कई बार वैसी घटनाएं घट जाती हैं जो ना घटे तो अच्छा हो। ऐसे में पुलिस कमिश्नर के पास अतिरिक्त अधिकार आ गए हैं, जो अब तक पुलिस कप्तान या डीआईजी के पास नहीं हुआ करते थे। प्रदेश की साख महिला अत्याचारों को लेकर बहुत अच्छी नहीं रही है और यहां कि हर सरकार इस बात का प्रयास करती रही है कि महिला अत्याचारों में कमी लाई जाए। महिला अत्याचार के बहुत से मामले बड़े शहरों से ही आते हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नर प्रणाली यदि महिला अत्याचार को कम करने में सफल होती है तो यह इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी।

दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे देश के बड़े शहर पहले से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं। शहरों की पुलिस कमिश्नर प्रणाली का अनुभव भी मप्र के दोनों प्रमुख शहरों के लिए महत्वपूर्ण नजीर की तरह काम करेगा। भोपाल शहर का एक हिस्सा तो बहुत पुराना है, जिसे हम सिटी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा हिस्सा मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक

अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से मिलकर बना है। यहां पर भी शांति व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। शहर का तीसरा हिस्सा कोलार रोड, इंदौर रोड, होशंगाबाद रोड के रूप में नए उपनगर के तौर पर विकसित हुआ है। शहर के इन तीनों इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरतें अलग-अलग तरह की हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर तीनों में सामंजस्य बनाकर बेहतर नतीजे देंगे। वहीं इंदौर शहर मप्र का सबसे बड़ा शहर है और सबसे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र भी है। यहां के व्यस्त बाजार, चौड़ी सड़कें और खुशमिजाज लोग निश्चित तौर पर नई प्रणाली को अपना पूरा सहयोग देंगे। मप्र की कमिश्नर प्रणाली में सुनसान स्थलों पर ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की भी व्यवस्था की गई है, जहां हमेशा कुछ लोग उपस्थित रहें। इससे राहजनी, छीनाझपटी, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की कमी आएगी।

जनता को फायदा क्या?

जनता के मन में यह सवाल है कि कमिश्नर प्रणाली से उसे क्या लाभ होगा? तो विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रणाली से जहां पुलिस का पावर बढ़ा है, वहीं उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ा है। जनता की सहूलियतों पर अब पुलिस की निगरानी रहेगी। यदि जनता की दृष्टि से बात करें तो आम आदमी यही सोचता है कि उसके बच्चे स्कूल-कॉलेज सुरक्षा की भावना के बीच में जाएं। बाजारों में कारोबार करना सहज हो, सड़क की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर अतिक्रमण न हो। जाहिर है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में इन बातों को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर आम आदमी पुलिस के पास तत्परता से अपनी शिकायत पहुंचा सके और उसकी शिकायतों का तेजी से निराकरण हो सके तो निश्चित तौर पर आम व्यक्ति भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली का स्वागत ही करेगा। वर्तमान में ट्रैफिक सिस्टम के लिए ट्रैफिक पुलिस को नगर निगम, रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसियों के भरोसे रहना पड़ता था। लैटर कम्युनिकेशन और परमिशन में वक्त लगता था। अब पुलिस का ट्रैफिक डिपार्टमेंट यह व्यवस्थाएं करेगा। इससे शहर का ट्रैफिक बेहतर होगा। वाहनों की स्पीड लिमिट भी पुलिस तय करेगी। लोगों में खौफ पैदा करने वाले गुंडों, आदतन क्रिमिनल्स को पुलिस जिलाबदर कर सकेगी। इससे लोगों को गुंडों के खौफ से मुक्ति मिलेगी। वर्तमान शहर में दो एसपी थे, अब आठ होंगे। साथ ही, अन्य लेवल के अफसरों की संख्या बढ़ गई है। इसका फायदा शहर की चौकसी में होगा। इससे शहर में क्राइम भी कम होगा।

पूर्व डीजीपी एसके दास का कहना है कि इससे ट्रैफिक में तो सुधार होगा ही। इसके साथ, आरोपियों पर कार्रवाई भी हो सकेगी। पहली चीज ट्रैफिक में भी सुधार आएगा। अभी इसके लिए कलेक्टर पर निर्भर रहना होता है, लेकिन अब सीधे पुलिस डिसीजन ले पाएगी। एसडीएम के पावर पुलिस के पास आ जाएंगे। इसमें माफिया में भी डर का माहौल पैदा होगा। उन्हें जेल में डालकर अपने हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में भी मौके पर फैसला लिया जाएगा। पूर्व डीजीपी दिनेश जुगरान का कहना है कि यह जनता के लिए तोहफा है। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इस सिस्टम से पावर एक जगह हो जाएगा। अभी तक लोगों को अनुमतियों के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब एक जगह ही जनता के काम हो जाएंगे। उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। गुंडे-बदमाशों पर पुलिस जिलाबदर जैसी कार्रवाई कर सकेगी। थानों में जल्द सुनवाई होगी। एक और पूर्व डीजीपी आरएलएस यादव बताते हैं कि पुलिस की खुद की आचार संहिता होगी। ट्रेनिंग होगी। दोनों शहरों में आईपीएस अधिकारियों की सख्या भी बढ़ेगी। सुपरविजन बेहतर होगा। क्राइम, साइबर अपराध, चोरी, डकैती, बैंक डकैती जैसे जितनी भी तरह के क्राइम हैं, उनके लिए अलग से आईपीएस होगा। छानबीन बेहतर होगी। दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की जरूरत थी।

पुलिस का सबसे बड़ा काम तो अपराध और अपराधियों पर लगाम कसना ही है। दोनों ही पुलिस कमिश्नर अपनी छवि के अनुसार सख्त और न्याय प्रिय स्वभाव के माने जाते हैं ऐसे में आम जनता यह उम्मीद कर सकती है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की पुलिस विभाग के दायरे में आने वाली तकलीफों पर काफी कुछ अंकुश लग जाएगा।

कुछ लोग पुलिस कमिश्नर प्रणाली को पुलिस प्रशासन और आईएएस बिरादरी में अधिकारों की लड़ाई के तौर पर देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की दृष्टि न्याय संगत नहीं है। चाहे पुलिस अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी, अंतत: वे सभी राज्य व्यवस्था का अंग हैं और सबकी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं। कौन-सी जिम्मेदारी किसके हिस्से में आएगी, यह राज्य ही तय करता है। ऐसे में अगर प्रशासन की कुछ जिम्मेदारियां पुलिस के पास आ रही हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा शक की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ा प्रयोग है, जिसका इंतजार मप्र पिछले चार दशक से कर रहा था और अब यह जब अमल में आ गया है तो इसे काम करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अगर इसे प्रशासन और पुलिस के संघर्ष के तौर पर देखा गया तो मौजूदा पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए काम करने में काफी चुनौतियां आएंगी। जाहिर है, यह सब बातें राजनीतिक नेतृत्व की निगाह में भी होंगी और इसका कोई सुगम रास्ता निकल ही जाएगा।

आजादी से पहले भी था कमिश्नर सिस्टम

पुलिस कमिश्नर प्रणाली कोई नई बात नहीं है। पुराने रिकॉर्ड्स देखें, तो आजादी से पहले अंग्रेजों के दौर में कमिश्नर प्रणाली लागू थी। इसे आजादी के बाद भारतीय पुलिस ने अपनाया। इस सिस्टम में पुलिस कमिश्नर का सर्वोच्च पद होता है। अंग्रेजों के जमाने में ये सिस्टम कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हुआ करता था। इसमें ज्यूडिशियल पावर कमिश्नर के पास होता है। यह व्यवस्था पुलिस प्रणाली अधिनियम, 1861 पर आधारित है। अब यह प्रणाली भोपाल और इंदौर में लागू कर दी गई है। इससे जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के योग्य आईपीएस अधिकारियों को दोनों शहरों की कमान सौंपी है। अब दोनों शहरों में निगरानीतंत्र भी मजबूत होगा। उधर, दोनों शहरों के कमिश्नर ने पदभार संभालने के साथ ही अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।

बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी!

तीसरी बार बिजली की दरों में इजाफा

बता दें कि जहां देश के कई अन्य राज्यों की तरह मप्र में भी कोयले की कमी से बिजली की सप्लाय पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। वही, इस बीच अब प्रदेश में फिर बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। बताते चलें कि, इसी साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब फिर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है। वहीं अगर कंपनी के पक्ष में फैसला आता है तो इस तरह 16 माह में तीसरी बार बिजली की दरों में इजाफा होगा। बताया जाता है कि इस बार तीनों कंपनियों ने लेखा-जोखा तैयार किया है। उसमें करीब 40 हजार करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की मांग बताई है। इस लिहाज से तीन से चार प्रतिशत बिजली दरें बढ़ सकती हैं। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक के लिए ये दरें होंगी। इसका निर्णय साल के शुरुआत में हो जाएगा।

बिजली कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की नई दरें निर्धारित करने के लिए टैरिफ याचिका नियामक आयोग के समक्ष पेश कर दिया है। सूत्रों की मानें तो इस बार विभाग चार प्रतिशत के लगभग दरें बढ़ाने की तैयारी में है। विभाग ने 34 हजार करोड़ रुपए की जरूरत बताई है। 14 दिसंबर को नियामक आयोग में प्रारंभिक सुनवाई की गई। अब से टैरिफ याचिका को सार्वजनिक करते हुए जनसुनवाई के लिए आपत्तियां आमंत्रित किए जाएंगे। मप्र की बिजली सप्लाई कंपनियों की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 1 दिसंबर को नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दायर की थी। इस बार याचिका में बढ़ाई गई दरों का खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। कंपनी अधिकारियों का दावा है कि नियामक आयोग ही प्रस्तावित दरों का खुलासा करेगी।

14 दिसंबर को नियामक आयोग में प्रारंभिक सुनवाई की गई। इसमें याचिका लगाने वाली कंपनी का पक्ष सुना गया। याचिका में जिन दस्तावेजों में कमी पाई गई, उसकी पूर्ति के निर्देश दिए गए। अब तय होगा कि कब इस टैरिफ याचिका को सार्वजनिक करते हुए इस पर आम लोगों से आपत्तियां बुलवाई जाए। इसके बाद जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई वर्चुअल होगी या भौतिक ये बाद में तय होगा। बिजली कंपनी के मामले में जानकार रिटायर्ड इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल ने बिजली कंपनियों की ओर से दायर की गई टैरिफ याचिका की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। अग्रवाल के मुताबिक अभी नियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-202 के लिए नई रेग्युलेशन नीति बनानी है। इसकी जनसुनवाई 24 अगस्त को हो चुकी है। पर अभी तक आपत्तियों को समाहित करते हुए खुदरा टैरिफ निर्धारण हेतु रेग्युलेशन नीति जारी नहीं हो पाई है। बिजली कंपनी ने ड्राफ्ट के आधार पर इस प्रत्याशा में टैरिफ याचिका दायर कर दी है। यह टैरिफ याचिका ही पूरी तरह से वैधानिक नहीं है। पहले रेग्युलेशन नीति तय होना चाहिए थी। बिजली कंपनियों ने इसी साल जुलाई में 0.63 प्रतिशत दर बढ़ाए थे। सूत्रों की मानें तो इस बार कंपनियों ने 4 प्रतिशत के लगभग दर बढ़ाने की मांग टैरिफ याचिका में की है।

बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में 6 प्रतिशत की बढ़त का प्रस्ताव बनाकर राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने ऊर्जा सचिव को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 को नोटिफाइड आपदा घोषित किया है। जनहित में फैसला लेते हुए वर्ष 2022-23 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी न की जाए। दरअसल, पिछले दिनों खबर आई थी कि मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली की दरों में 6 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। अगर कंपनी के पक्ष में फैसला होता है तो 16 माह में तीसरी बार बिजली की दरें बढ़ेंगी। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने ऊर्जा सचिव को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी की स्थिति अन्य विपदाओं से अलग है। प्रदेश के सभी नागरिकों को आर्थिक विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 30 जून 2021 को कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक राहत देने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन कानून की धारा-2 के तहत न्यूनतम मापदंडों की गाइडलाइन बनाई गई है। इसी गाइडलाइन के तहत 2022-23 में बिजली की दर न बढ़ाई जाए। इस संबंध में प्रदेश सरकार जल्द से जल्द निर्णय लें और विद्युत नियामक आयोग जल्द से जल्द आवश्यक निर्देश जारी करें।

नए साल में प्रदेशवासियों को जोरदार झटका लग सकता है, बढ़ती महंगाई के बीच मप्र के लोगों को यह झटका बिजली विभाग दे सकता है। एक बार फिर मप्र में बिजली की दरें फिर से बढ़ सकती हैं। बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर बिजली दर में वृद्धि होने का अंदेशा है। नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दर निर्धारण के लिए बिजली नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से लेखा-जोखा यानी खर्च और लागत की जानकारी मांगी है। कंपनियों की मांग के अनुरूप बिजली दरें निर्धारित होती हैं। तीन से चार प्रतिशत बिजली दरें बढ़ सकती है। दरअसल, हर साल बिजली दरें निर्धारण करने के पहले नियामक आयोग पावर मैनेजमेंट कंपनी से प्रस्ताव मांगती है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियां पावर मैनेजमेंट के माध्यम से आय-व्यय का ब्यौरा देकर आगामी वित्तीय वर्ष में कितने राजस्व की जरूरत होगी, इसकी भी डिमांड जाती है। इसके बाद ही आयोग सुनवाई करता है। प्रस्ताव में अगर संशोधन होता है तो वह भी कराया जाता है। आम जनता से दावे-आपत्तियां बुलाए जा हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग दर निर्धारित करता है।

● **अक्स ब्यूरो**

सत्ता में आने के बाद तो भाजपा विपक्ष मुक्त भारत की मुहिम में ही जुट गई थी, लेकिन 2015 में बिहार, 2019 में विशेष परिस्थितियों महाराष्ट्र और 2021 में पश्चिम बंगाल में देश की जनता ने भाजपा को बार-बार ये भी समझाने की कोशिश की कि ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है और शायद आगे भी न हो पाए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की सत्ता पक्ष के कितने भी ज्यादा मजबूत हो जाने पर बैलेंसिंग फैक्टर होता है और वही लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखता है।

कांग्रेस मुक्त विपक्ष!

राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन ही ऐसा मुद्दा बचा है जिस पर विपक्ष साथ खड़ा है। अगर तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों के खिलाफ राज्यसभा सभापति की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया होता तो कांग्रेस के साथ ये दोनों पार्टियां तो नहीं ही नजर आतीं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर तब कांग्रेस पूरी तरह अलग-थलग पड़ी नजर आती, लेकिन तब कांग्रेस के साथ विपक्ष के वे नेता ही खड़े देखने को मिलते जो अभी तक ममता बनर्जी के राष्ट्रीय राजनीति में उभार को बर्दाश्त या हजम नहीं कर पा रहे हैं।

जब सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग खारिज कर दी तो कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने सदन से वॉक आउट किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जब संसद परिसर में विपक्ष की तरफ से निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ तो टीएमसी सांसद डोला सेन और शांता छेत्री शामिल जरूर हुए, तृणमूल कांग्रेस की ये रणनीति है, लेकिन वो पूरी तरह संकोच छोड़ नहीं पा रही है। ये सब ममता बनर्जी की रणनीति तो दर्शाता है, लेकिन उनकी मजबूरी भी छिपा नहीं पाता।

संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों की मीटिंग पहले से ही बुलाई जा चुकी थी। मीटिंग की अध्यक्षता राहुल गांधी ने की लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से अपील की कि सारे मतभेदों को भूलकर देश हित में संसद के भीतर एकजुट होकर खड़े हों। राहुल गांधी की मुश्किल ये है कि जब उनकी बातों को न कांग्रेस के भीतर गौर से नहीं सुना जाता तो बाहर कहां संभव है।

विपक्षी नेताओं की एक और भी बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद मौजूदा संसद सत्र के आखिर तक गांधी प्रतिमा के पास धरना देंगे, लेकिन एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने बैठक से खुद को अलग रखा और ये कांग्रेस नेतृत्व को संदेश देने का ही एक और तरीका समझ में आता है। विपक्षी एकजुटता में दरार तो ममता बनर्जी के चुनाव बाद पहले ही दौरे में ही महसूस की जाने लगी थी, लेकिन हालिया दौरे में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर जो बयान दिया, स्थिति

न पक्ष, न विपक्ष-और न ही तटस्थ

देश के मौजूदा राजनीतिक समीकरण में सत्तापक्ष और विपक्ष का ही ठीक-ठीक बंटवारा नहीं है, तो पूरे विपक्ष के कंसेप्ट को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर दो गठबंधन आमने-सामने देखे जरूर जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के रुख ने काफी घालमेल कर रखा है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पहले भी सत्तापक्ष के साथ न होते हुए भी तमाम मुद्दों पर खामोश देखा जाता रहा है। अब भी परिस्थितियां कुछ राज्यों में ऐसी ही हैं। यही वजह है कि सत्तापक्ष का हिस्सा न होते हुए भी भाजपा नेता मायावती की बातें भाजपा के फायदे वाली लगती हैं और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी तो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं, जबकि ये दोनों ही सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। जगनमोहन रेड्डी ही नहीं, जम्मू-कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी, असम की बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां मानसून सत्र के पहले और संसद के मौजूदा सत्र के पहले भी विपक्षी खेमे से बाहर रहीं, लेकिन ज्यादा हैरानी हुई शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया स्टैंड देखकर।

ज्यादा स्पष्ट नजर आने लगी और अब तो उसके सैंपल भी सामने आने लगे हैं। ममता बनर्जी का कहना रहा कि हर बार उनका सोनिया गांधी से मिलना क्यों जरूरी है।

ममता बनर्जी का नया अंदाज अभी ये तो नहीं जता रहा कि वो कांग्रेस को विपक्षी खेमे से पूरी तरह आउट करना चाह रही हैं, लेकिन ये तो साफ है कि वो अपनी शर्तों पर ही विपक्ष में शामिल होना चाहती हैं और तृणमूल कांग्रेस नेता की ताजा रणनीति में कांग्रेस मुक्त विपक्ष की अवधारणा काफी गहरी और ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, ये सत्ता पक्ष की तरह से विपक्ष के खिलाफ उठाया गया बड़ा और सख्त कदम रहा। निलंबित सांसदों में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी की डोला सेन सहित कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस के दो, शिवसेना के दो, सीपीआई के एक और सीपीएम के भी एक सांसद शामिल हैं।

ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि ये वे सांसद ही हैं जिन्होंने पिछले सत्र में किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा मचाया था और तब राज्यसभा क उपसभापति हरिवंश पर कागज भी फेंके गए थे। इनमें से कई सांसद टेबल पर चढ़ गए थे और सभी के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही थी। सभापति वेंकैया नायडू को फैसला लेना था और नए सत्र के पहले दिन उन्होंने सुना भी दिया। बस **यही एक मामला है** जो बुरी तरह बंटे हुए विपक्ष के लिए परदे का काम कर रहा है। देश की स्वाभाविक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस विपक्ष के नेतृत्व का झंडा थामे हुए हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नंबर के हिसाब कांग्रेस ही विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी पार्टी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा और बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार के बाद विपक्ष के झंडे को लेकर छीनाझपटी मच गई है।

पश्चिम बंगाल में लगातार तीन चुनाव जीतकर सरकार बनाने के पहले से ही ममता बनर्जी ने अपना इरादा जगजाहिर कर दिया था, एक पैर से बंगाल और दो पैरों से दिल्ली जीतेंगे। तय प्लान के मुताबिक ममता बनर्जी ने दिल्ली में जोरदार दस्तक भी दी, लेकिन तभी राहुल गांधी रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। फिर भी ममता बनर्जी ने 10 जनपथ जाकर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से मुलाकात की। जाते-जाते ममता बनर्जी का मन खट्टा हो चुका था और ये भी देखा कि जब वो गोवा गईं तो वहां भी राहुल गांधी धावा बोल दिए। ममता बनर्जी जब दोबारा दिल्ली पहुंची तो सोनिया गांधी से न मिलकर मैसेज तो दिया ही, मेघालय में मुकुल संगमा को टीएमसी का नेता बनाकर कांग्रेस को करीब करीब पैदल कर दिया और ये तृणमूल कांग्रेस नेता की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व को नमूने के साथ बहुत बड़ा संदेश था।

ये तो विपक्ष में भी विपक्ष बन गया है

कांग्रेस ने ये सोचकर सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की मीटिंग बुलाई होगी कि मिलजुल कर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। ममता बनर्जी के तेवर को देखते हुए उसे तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी अंदाजा हो ही गया होगा। आम आदमी पार्टी तो वैसे भी कांग्रेस के मेहमानों की लिस्ट में कभी जगह नहीं बना पाती और उप्र चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी से भी कोई अपेक्षा नहीं रही होगी। करीब-करीब वैसे ही ख्याल मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी आए होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विपक्षी खेमे की बैठकों से परहेज करना है। शिवसेना के साथ जहां कांग्रेस महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का हिस्सा है, वहीं झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सहयोगी पार्टी के तौर पर सत्ता में शामिल है, लेकिन नए दौर में ये दोनों ही पार्टियां कांग्रेस नेतृत्व को आंखे दिखाने लगी हैं। उप्र में तो कांग्रेस मुक्त विपक्ष 2019 के आमचुनाव में ही खड़ा हो गया था, जब सपा-बसपा गठबंधन बना और कांग्रेस को वैसे ही अछूत की तरह ट्रीट किया गया। जैसे अब तक राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार अरविंद केजरीवाल के साथ पेश आता रहा है। हालांकि, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सार्वजनिक तौर पर मायावती और अखिलेश यादव पर सीधे हमले से बचते रहे। वैसे कांग्रेस ने अपनी तरह से गठबंधन को डैमेज करने में कोई कसर भी बाकी नहीं रखी, अब तो बिहार में भी उपचुनावों के दौरान जो नजारा दिखा लगता तो ऐसा ही आरजेडी ने भी कांग्रेस मुक्त विपक्ष की राह चल दी है।

2014 से पहले ही भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और 2019 आते-आते ममता बनर्जी भी भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना समझाने लगी थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनका एक्सपाइरी डेट पीएम कहना लोगों को अच्छा नहीं लगा और भाजपा को पहले के मुकाबले ज्यादा बहुमत के साथ दिल्ली भेजकर जनता ने ममता बनर्जी और सोनिया गांधी को अपने जैसे अपने मन की बात सुना दी थी। राहुल गांधी की अमेठी में हार भी एक संदेश ही लगता है। पश्चिम बंगाल में जीत का हैट्रिक लगाने के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में कांग्रेस ही आड़े आ रही है। ऐसा भी नहीं कि ये ममता बनर्जी सिर्फ अपने लिए महसूस कर रही हैं, बल्कि असल बात तो ये है कि कांग्रेस को लेकर विपक्षी खेमे के कई दलों के नेताओं के मन में यही सवाल है। यही वजह है कि कांग्रेस मुक्त विपक्ष की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं।

अभी जो बंटा हुआ विपक्ष है, उसके लिए कांग्रेस तो काफी हद तक जिम्मेदार नजर आती ही है। आदर्श स्थिति तो कुदरत में ही नहीं बन पाती, लेकिन अगर विपक्षी दलों में संभव एकजुटता वास्तव में बन गई तो लोकतंत्र के लिए अच्छा जरूर माना जाएगा। मानसून सत्र से पहले के प्रयासों में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को विपक्षी खेमे से दूर रखने की कोशिश की थी और शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस के गठबंधन साथियों को ही उससे दूर रखने में सफलता हासिल कर रही है। पिछले सत्र की शुरुआत में दौरान ममता बनर्जी दिल्ली में थीं, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही दिल्ली से लौट गईं और शीतकालीन सत्र के शुरू होने पर मुंबई पहुंच गईं।

● **रजनीकांत पारे**

आधी आबादी का दम

उप्र चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ, राहुल गांधी, अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने-अपने प्रचार अभियान में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री आखिलेश यादव ने जिलों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 'मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं' नारे के साथ सक्रिय हो गई हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उप्र चुनाव में प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाएगी? क्या प्रियंका गांधी की बदौलत कांग्रेस का वोट बैंक 6 से 30 प्रतिशत तक बढ़ पाएगा?

देखा गया है कि प्रियंका गांधी जब-जब कुछ बोलती हैं तो सत्तापक्ष के साथ विरोधी पार्टी के नेता सन्नाटे में आ जाते हैं फिर गौर से देखते हैं और हमला करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रियंका गांधी की बातों में एक वजन होता है जिसका सीधा असर आम जनमानस पर देखा जाता है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का देश में अपना एक वजूद है उनके आकर्षक व्यक्तित्व और बातों से आम मतदाता सीधा प्रभावित होता है। लगभग 10 वर्ष के राजनीतिक सफर के पश्चात अब आगामी समय में प्रियंका गांधी जो कह रही है उसका कुछ ज्यादा ही असर दिखाई दे रहा है, जैसे हाल ही में उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी उप्र के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकटें देगी, इसके साथ ही राजनीतिक फिजा बदलने लगी है।

असल में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक तो वैसे ही खिसकता जा रहा है, बचा-खुचा चंद्रशेखर रावण के पाले में जा रहा है। समाजवादी पार्टी में खुद ही फूट पड़ी है, शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के लिए ठीक नहीं हैं, ऊपर से प्रियंका का भाजपा की महिला नेताओं से सामना होगा जिनका पहले से ही उप्र में बोलबाला है। जिनकी संगठन से लेकर सरकार तक में भागीदारी है। यही कारण है कि ये उप्र चुनाव में प्रियंका गांधी के रास्ते का बड़ा रोड़ा बन सकती हैं।

स्मृति ईरानी- प्रियंका गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भिड़ना होगा। ख्याल रहे अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर सबसे बड़े राजनीतिक किले को भेद दिया था। वहीं उप्र 2022 चुनाव में भाजपा स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी अपने अलग अंदाज में प्रियंका गांधी के सक्रियता का जवाब देंगी। स्मृति ईरानी गांधी परिवार की पॉलिटिक्स के खिलाफ मुखर रहती हैं। कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी के नारे 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' को लेकर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था, 'घर पर लड़का है, पर लड़ नहीं सकता।'

अदिति सिंह- कांग्रेस की बागी विधायक रहीं अदिति सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। एक समय था जब अदिति सिंह को प्रियंका गांधी के काफी करीब माना जाता था लेकिन अब ये नजदीकियां दूरियों में तब्दील हो चुकी हैं। अदिति सिंह का जख्म ताजा-ताजा है, ऐसे में वे कई बार प्रियंका गांधी की आलोचना कर चुकी हैं। अदिति सिंह ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर विधानसभा में तब भाषण दिया था जब पूरे विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ सदन का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ही कांग्रेस ने अदिति सिंह को निलंबित कर दिया था। असल में अदिति स्वर्गीय बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। रायबरेली में उनके परिवार की काफी लोकप्रियता है। अदिति, कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली सदर से 2017 में चुनाव जीतीं और विधायक बन गईं। इसके पहले इस सीट पर 1993 से 2017 तक उनके पिता अखिलेश सिंह का कब्जा था। ऐसे में अदिति के भाजपा में शामिल होने से रायबरेली सदन में भाजपा की राहें आसान हो गई हैं जबकि कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अदिति की काट खोजना कांग्रेस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर के

राजनीति में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान

महिलाओं का सक्रिय राजनीति में आवाज एक जगह से 20वीं शताब्दी के आसपास से ही शुरू हो गया था। एनी बेसेंट इसका एक बड़ा उदाहरण हैं। इसके पश्चात जब महात्मा गांधी का युग आया तो उन्होंने अपने हर आंदोलन में एक तरह से महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया उन्होंने महसूस किया कि आजादी की लड़ाई में और समाज के उत्थान में 50 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा कर देश को नेतृत्व नहीं मिल सकता हैं। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका का 1907 का सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन हो अथवा ऐतिहासिक डांडी मार्च, उनके द्वारा लाई गई बुनियादी तालीम हो या भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने हर एक मोर्चे पर महिला शाक्ति को देश के लिए संघर्ष में आगे-आगे रखा। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से की थी, आगे जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, भीखाजी कामा, सुशीला नैयर, सुचेता कृपलानी, कमला नेहरु, प्रभावती देवी, कमला देवी चटोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर जैसी असंख्य महिलाओं ने आजादी आंदोलन में अपना योगदान दिया और भारतीय राजनीति को दिशा दी। आजादी के बाद भी महिलाओं का राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी वर्तमान में भी अनेक महिला नेत्री ममता बनर्जी, मायावती, अंबिका सोनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मगर आरक्षण से एक तरफ से महिलाओं के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे और भारतीय राजनीति का चित्र भी बदलने लगेगा।

उप्र में भाजपा नेत्रियों के साथ ही मायावती का भी सामना प्रियंका के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। मायावती और उनकी पार्टी बसपा इस समय प्रदेश में भले ही कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन उनकी साख अभी भी मजबूत है। इसलिए प्रियंका के लिए राह आसान नहीं है।

समान है। बगावत करने के बाद अदिति को रेबेल ऑफ रायबरेली कहा जाने लगा, अब देखना है कि प्रियंका गांधी किस तरह अदिति के वार का जवाब देती हैं।

साध्वी निरंजन ज्योति- फतेहपुर से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को कौन नहीं जानता। ये अपने बेबाक विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। साध्वी निरंजन ज्योति की पृष्ठभूमि और उनका निषाद जाति से आना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वे दूसरी बार सांसद बनी हैं। इसके पहले वे विधायक भी रह चुकी हैं। अपने क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ है। उनकी वेशभूषा की वजह से पार्टी को चुनाव में काफी लाभ मिलता है। ऐसे में प्रियंका गांधी पर अगर ये निशाना साधती रहती हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी।

स्वाति सिंह- भाजपा की इस महिला नेता का पार्टी से नाता ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन अपने क्षेत्र में पकड़ काफी मजबूत है। असल में स्वाति सिंह का नाम इनके पति दयाशंकर सिंह के बयान के बाद आया। जब दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीम पर अश्लील टिप्पणी की थी। इसके बाद बसपा के नेता दयाशंकर सिंह के परिवार पर हमलावर हो गए। उसी बीच अचानक से एक तेज तर्रार चेहरा उभरा जिसने बसपा कार्यकर्ताओं की अभद्र बातों का तर्क के साथ जवाब दिया। वो चेहरा दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह का था। स्वाति सिंह ने जिस तरह बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अमर्यादित बयान के खिलाफ बात की। इसी को देखते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने स्वाति सिंह को मौका दिया। जब भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी ने स्वाति सिंह को भी मंत्री बनाया। अब उप्र चुनाव में एक बार फिर भाजपा स्वाति सिंह को प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है।

रीता बहुगुणा जोशी- एक समय था जब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस का बड़ा चेहरा मानी जाती थीं लेकिन अब वे भाजपा का बड़ा चेहरा हैं। दरअसल, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। इन्हें ब्राह्मण वर्ग और पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं इनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। इलाहाबाद की रानीति में बहुगुणा ने कई बार अपने जुझारूपन को साबित किया है। उप्र चुनाव में रीता बहुगुणा के बड़े कद का भाजपा का फायदा मिलेगा, अब यह प्रियंका गांधी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है।

गीता शाक्य- इस नाम को भले ही आपने अब तक ना सुना हो लेकिन यह चेहरा महिलाओं को लेकर उप्र चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। असल में भाजपा ने चुनाव से पहले ही राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को उप्र में महिला मोर्चा की कार्यभार सौंप दिया था। यानी गीता शाक्य को चुनाव में बड़े स्तर पर योजना बनाएंगी और महिला मतों को जोड़ने का काम करेंगी। भले ही राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग राहुल गांधी का नाम सुनते ही नाक-मुंह सिकोड़ लेते थे वही अब प्रियंका गांधी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की इन दिग्गज महिला नेताओं का उप्र में जिस तरह का बोलबाला है, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि प्रियंका के लिए उप्र फतह करना आसान तो बिल्कुल नहीं है।

दरअसल, महिला आरक्षण एक ऐसा मसला है जिसे देश के राजनीतिक दल न तो छोड़ना चाहते है और न ही लागू करना चाहते है। ऐसे मे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वक्त की नब्ज पर हाथ रख उप्र विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर तुरूप का पत्ता फेंका है। एक तरह से मुख्यमंत्री योगी को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने सत्तापक्ष भाजपा को उप्र चुनाव में 'महिलाओं के सशक्तिकरण' के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान कर दी है- 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं।'

● **इन्द्र कुमार**

महिला आरक्षण बिल, भूल गया देश...

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर 2008 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद अब तक लोकसभा मे भी पास हो गया होता। मगर पुरुष शासित राजनीतिक दल उसके नेता ऐसा नहीं करना चाहते हैं। शायद आपको याद हो कि उस समय समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण को लागू करने के लिए खुलकर विरोध किया था। यह भी देश ने देखा है कि अपने वेतन, भत्ते सुविधाओं की बढ़ोतरी, इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स और राजनीति मे धन और अपराधियों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर जबरदस्त एकजुटता प्रदर्शित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा महिला आरक्षण बिल को पास न करना उनकी हकीकत को सामने लाता है। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण जैसे विषय पर पहल करके एक उथल-पुथल ला दी है। प्रियंका गांधी का ऐलान 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' हर महिला के लिए है। और आने वाले भविष्य में इसके लाभ देश को दिखाई देने लगेंगे। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों की बागडोर पुरुष नेताओं के हाथों में है यही कारण है कि प्रायः नाम मात्र ही महिलाओं को टिकट नहीं मिलती हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी और नवीन पटनायक की बीजेडी जरूर अपवाद हैं, जिन्होंने विगत विधानसभा चुनावों में क्रमशः 40 प्रतिशत और 37 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देकर के एक पहल की है। आगे प्रियंका गांधी का यह आगाज महिलाओं को और भी ज्यादा राजनीति में महत्व दिलाएगा।

राम नाम पर कांग्रेस के काम

भारतीय राजनीति में जब भी 'राम' नाम का जिक्र होता है तब भगवा दल भाजपा की छवि ही जेहन में आती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इस रूढ़ सियासी स्वरूप को तोड़ने के लिए हरसंभव प्रयास करती दिख रही है। अब तक राम वन गमन पथ परियोजना से लेकर कौशल्या मंदिर चंदखुरी में दीपोत्सव, राम रथ यात्रा, नवधा मानस मंडलियों को प्रोत्साहन और स्कूलों में प्रार्थना के दौरान रघुपति राघव राजा राम भजन गायन जैसे राम को समर्पित कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। भाजपा इसे वोट साधने के लिए छल करार दे रही है। विश्लेषक इसे हार्डकोर हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसे यहां की संस्कृति में रचे बसे 'समावेशी राम' बता रही है।

मान्यता है, वनवास के दौरान भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में लंबा वक्त बिताया था। राम जहां गए थे, ऐसे 75 स्थानों की पहचान कर सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में कोरिया से सुकमा तक लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से 9 जगहों को संवारा जा रहा है। इनमें सीतामढ़ी हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर) और रामाराम (सुकमा) शामिल हैं। बघेल सरकार ने दिसंबर 2020 में दो वर्ष पूरे होने पर राम के नाम पर रथयात्रा भी निकाली थी। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर को हुई। प्रदेश के उत्तरी छोर सीतामढ़ी और दक्षिणी छोर रामाराम से निकली रथयात्रा 17 दिसंबर को माता कौशिल्या मंदिर चंदखुरी में समाप्त हुई। पूरा बघेल मंत्रिमंडल एक बस में सवार होकर कौशल्या मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा था। 19 जिलों से होकर गुजरी यह यात्रा 1,575 किलोमीटर लंबी थी। हर जगह की मिट्टी रथ में इकट्ठा की गई। यात्रा जहां-जहां से होकर गुजरी वहां रामायण पाठ हुआ।

रायपुर से 24 किलोमीटर दूर चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली माना जाता है। यहां जलसेन तालाब के बीच माता कौशल्या का पुराना और दुनिया का इकलौता मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान राम अपनी मां की गोद में विराजित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ योजना के अंतर्गत करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार कराया है। यहां भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया।

छत्तीसगढ़ के अधिकतर गांवों-शहरों में नवधा रामायण का आयोजन होना आम है। इस दौरान 9 दिनों तक रामचरितमानस का संगीतमय पाठ किया जाता है। विभिन्न मानस मंडलियां इसमें शिरकत करती हैं। इसे प्रोत्साहन देने के लिए भी भूपेश सरकार ने पहल की है। मानस मंडली प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत लगभग 7 हजार रामायण मंडलियों को विशेष प्रोत्साहन के तहत वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कहते हैं, जब चुनाव आता है तभी कांग्रेस नेता टीका लगाते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। राम राज्य वह है जिसमें जनता सुखी रहे, जनता के लिए काम हो। यहां तो तीन साल में दो-तीन चीजें ही प्रसिद्ध हुई हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कोल माफिया, शराब माफिया और भूमि माफिया का राज है। वरिष्ठ भाजपा नेता कहते हैं, कांग्रेस के लोग सिर्फ नारे लगाते हैं और कुछ नहीं करते। राम वन गमन पथ की बात करते तीन साल हो गए, यह केंद्रीय योजना का हिस्सा था लेकिन आज तक इसे लेकर एक रुपए का काम नहीं हुआ है। राम नाम की राजनीतिक आवश्यकता को बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अनुपमा सक्सेना रेखांकित करते हुए कहती हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राम भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं। लेकिन आज राम राजनीतिक जरूरत भी बन गए हैं। लेकिन यदि राम की आक्रामक छवि की जगह उनके सौम्य स्वरूप और मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए तभी इसे सधा हुआ सियासी फैसला माना जा सकता है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

राजनीति में सबके अपने राम

कांग्रेस सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि उनके राम भाजपा के राम से काफी अलग हैं। 7 अक्टूबर को राजधानी रायपुर से लगे चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण समारोह में बघेल ने राम पर अपनी सरकार का नजरिया बताया। उन्होंने कहा, भगवान राम को लेकर सबका नजरिया अलग है। कुछ लोगों के लिए वे वोट पाने का जरिया हैं, लेकिन हमारी तो संस्कृति में राम बसे हुए हैं। हमारे राज्य में राम को भांजा राम, वनवासी राम, गांधी के राम, कबीर के राम, तुलसी के राम और शबरी के राम के रूप में देखा जाता है। हम तो गांधी के अनुयायी हैं जिनके मुंह से आखिरी शब्द राम ही निकला था। भले ही छत्तीसगढ़ सरकार राम से जुड़े अपने विभिन्न फैसलों को सांस्कृतिक संरक्षण का नाम देकर किसी सियासी इरादे से इनकार करे लेकिन इसके प्रचार-प्रसार में वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए वह अपना संदेश जनता तक पहुंचा रही है। राम वन गमन पथ के अंतर्गत माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार की जानकारी देने वाले होर्डिंग राज्य की सड़कों और प्रमुख जगहों पर आसानी से देखे जा सकती हैं। दरअसल भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के कुछ महीनों बाद ही प्रदेश में कांग्रेस की 'रामभक्ति' दिखने लगी थी। दिसंबर 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आते ही उन स्थलों की पहचान कर उन्हें विकसित करने की योजना बनने लगी, जिनके बारे में मान्यता है कि वे राम से जुड़े हुए हैं। सालभर के भीतर ही इस पर काम भी शुरू हो गया और राज्य कैबिनेट ने राम वन गमन पथ को विकसित करने का निर्णय लिया।

शरद पवार की ख्वाहिशें...

शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे बिना फायदे के कोई कदम नहीं उठाते हैं। शरद पवार पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी कुछ ख्वाहिशें भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन ममता बनर्जी की सक्रियता उनकी राह में रोड़ा बनता दिख रहा है। चुनावी रणनीतिकार ममता बनर्जी के लिए जोड़-तोड़ करने में जुटे हुए हैं। शरद पवार और प्रशांत किशोर का कांग्रेस को लेकर स्टैंड तो सीधे-सीधे, आमने-सामने टकरा रहा है। अगर ये दोनों ममता बनर्जी के वास्तव में हितैषी हैं तो मतभेदों के बावजूद ऐसा कोई रास्ता खोजते तो कॉमन हो और ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद हो, लेकिन जो कुछ चल रहा है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी को निजी हितों के लिए हथियार बनाया जा रहा हो और बैलेंस या ऐडजस्ट करने में ममता बनर्जी ही मिसफिट हो जा रही हों।

कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर और शरद पवार के मकसद बिलकुल अलग-अलग हैं। प्रशांत किशोर डाटा पॉलिटिक्स करते हैं, तो शरद पवार के पास राजनीति के खांटी दांवपेंच का बरसों का प्रैक्टिकल अनुभव है। हाल फिलहाल ऐसे दो मौके देखने को मिले जब शरद पवार ने ये साबित भी किया। एक बार, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उनको ईडी का नोटिस मिला था और दूसरी बार, जब मूसलाधार बारिश में सतारा के मंच पर चढ़कर भाषण दिए और भाजपा के दिग्गज उम्मीदवार की हार पहले ही सुनिश्चित कर डाली। प्रशांत किशोर अपने प्लान के मुताबिक, अगर सब कुछ मन माफिक होता तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके होते और शरद पवार महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनवाने के बाद ही यूपीए के अध्यक्ष न सही, किसी विपक्षी फोरम के संयोजक बने होते, लेकिन दोनों में से किसी का भी काम अब तक नहीं बना है।

जब निजी तौर पर कोई किसी टास्क को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता तो उसके लिए खास टूल की जरूरत होती है और अभी तो ऐसा ही लगता है जैसे शरद पवार और प्रशांत किशोर दोनों को ही ममता बनर्जी की **राजनीति में एक** बेहतरीन टूल नजर आ रहा है। बेशक ममता बनर्जी महाराष्ट्र में कांग्रेस को गठबंधन सरकार से आउट करने का इरादा लेकर शरद पवार के पास पहुंची थीं, लेकिन न सिर्फ एनसीपी नेता ने ऐसा करने से मना कर दिया, बल्कि सामना के जरिए शिवसेना ने भी ऐसे प्रयासों को आगे के लिए भी खारिज कर दिया है। लेकिन क्या ममता बनर्जी वास्तव में कांग्रेस को पूरी तरह रास्ते से हटा देना चाहती हैं? तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन की बातों से तो लगता है कि ममता बनर्जी भी ऐसा नहीं चाहतीं। ममता बनर्जी अलग-अलग जगह अलग रणनीति पर काम के पक्ष में हैं।

थोड़ी देर के लिए तो ये भी लगता है जैसे शरद पवार भी जेपी की तरह सोच रहे हों। हालांकि, शरद पवार की रणनीति में निजी राजनीतिक नफा-नुकसान भी समझा जा सकता है। शरद पवार की एक कोशिश अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए भी कोई कारगर इंतजाम करना जरूरी है। वो अब तक न तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिट हो पाई हैं, न दिल्ली की राजनीति में ही। जेपी यानी जय प्रकाश नारायण की तरह वो कुछ नहीं कर सके तो इतनी कोशिश तो होगी ही कि विपक्षी मोर्चे का संयोजक बन कर वो सुप्रिया सुले के लिए कोई सम्मानजनक इंतजाम तो कर ही दें।

अगर ममता बनर्जी को भी लगता है कि 80 साल की उम्र में शरद पवार प्रधानमंत्री पद की होड़ में उनके लिए राह का रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या राजनीति की आखिरी पारी वो राष्ट्रपति भवन में गुजारने के भी ख्वाहिशमंद नहीं होंगे? फिर तो जरूरी है कि वो वक्त रहते ऐसा कोई इंतजाम कर लें जो उनको मंजिल तक पहुंचा सके। जैसे जेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने का इरादा कर लिया था, शरद पवार भी तो कुछ-कुछ वैसा ही सोचते हैं। ये सब महाराष्ट्र में भाजपा से शिवसेना को अलग कर सरकार बनवाने के उनके प्रयास ही बताते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उद्धव ठाकरे सरकार का रिमोट कंट्रोल भी शरद पवार के पास ही रहता है।

शरद पवार चाहते हैं कि महाराष्ट्र की ही तर्ज पर देश के बाकी हिस्सों और दिल्ली में भी राजनीतिक मोर्चेबंदी हो सके और सब मिल जुलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर कोशिश करें। शरद पवार भी ममता बनर्जी की ही तरह कांग्रेस से निकलकर आए हैं और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार की तैयारियों के दौरान की गतिविधियों को याद करें तो कांग्रेस के प्रति शरद पवार का नजरिया भी समझा जा सकता है। शिवसेना के साथ बातचीत में पहले शरद पवार एनसीपी के साथ-साथ कांग्रेस की तरफ से भी डील कर रहे थे, जब सोनिया गांधी ने कुछ कांग्रेस नेताओं को उद्धव ठाकरे के पास भेजा तो मालूम हुआ कि डील की कई बातें तो कांग्रेस को न तो मालूम है, न वैसी कोई पहल ही हुई है।

● **बिन्दु माथुर**

तीसरे मोर्चे की कोशिश फेल ही होती है

ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को अलग करके किसी विपक्षी गठबंधन का आइडिया लेकर चल रही हैं तो ये तीसरे मोर्चे की ही कवायद ही समझी जाएगी, जो एक-दो बार नहीं बल्कि बार-बार फेल हो चुकी है। अगर भाजपा और कांग्रेस किसी विपक्षी गठबंधन से अलग होंगे तो तीसरे मोर्चे के अलावा भला क्या नाम दिया जाएगा। आम चुनाव से पहले ऐसी कोशिशें अरसे से होती रही हैं। 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद मुलायम सिंह 2015 के बिहार चुनाव के दौरान 2019 के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे थे। बिहार में महागठबंधन तो बन गया, लेकिन तीसरा मोर्चा खड़ा होने से पहले ही ढेर हो गया। 2019 के पहले भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ऐसी ही कोशिशों को लेकर फटाफट कई मुलाकात किए थे। वो भी ममता बनर्जी से मिले थे और चाहते थे कि ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दें, लेकिन ममता ने ऐसा नहीं किया और फिर वो शांत होकर बैठ गए।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

गुटबाजी से त्रस्त है भाजपा...

राजस्थान में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले ही भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। पार्टी के दिग्गज नेताओं की गुटबाजी से अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता त्रस्त हैं। उधर, आलाकमान पूरे मामले पर मौन है।

राजस्थान भाजपा में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरह जहां राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष पूनिया भी राजे के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच गृहमंत्री शाह ने दोनों नेताओं के बीच चल रहे शीतयुद्ध का पटाक्षेप करने की कोशिश की है और गुजरात मॉडल अपनाकर राज्य में चुनाव जीतने का मंत्र दिया।

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गत दिनों भाजपा की राज्य कार्यसमिति को संबोधित करने के लिए जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना है। किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे के रूप में पेश करने से बचना चाहिए। शाह ने सभी को याद दिलाया कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण संगठन होता है और जो संगठन के साथ चलते हैं, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। उन्होंने तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरों सिंह शेखावत का उदाहरण दिया, जिन्हें कभी भी पार्टी का साथ न छोड़ने का फायदा हुआ। गृहमंत्री शाह ने राजस्थान भाजपा को गुजरात से सीख लेने की नसीहत भी दी। जहां भाजपा पन्ना प्रमुख मॉडल को अपनाकर पिछले दो दशकों से सत्ता में है।

राज्य भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मौजूद राजस्थान के एक प्रमुख भाजपा नेता कहते हैं कि जयपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया निर्देश वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी, जो 2023 में उन्हें भाजपा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की लगातार पैरवी कर रहे हैं। शाह के **संदेश से साफ नजर आ रहा है** कि भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के खेमे द्वारा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है।

एक अन्य नेता द्वारा बताया गया कि भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया कई बार हाईकमान से वसुंधरा राजे की शिकायत कर चुके हैं। राजे लगातार राज्य के पार्टी नेतृत्व की सलाह को दरकिनार करते हुए काम कर रही हैं। वहीं जो दायित्व उन्हें प्रदेश भाजपा की तरफ से दिए जाते है, वे उनकी भी लगातार अनदेखी कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने 2018 के बाद से हुए उपचुनावों में भाजपा के लिए प्रचार तक नहीं किया है, जिसमें हाल ही में हुए दो सीटों के उपचुनाव भी शामिल हैं। इन चुनावों में प्रचार में भाग नहीं लेने के पीछे उन्होंने अपनी बहू का खराब स्वास्थ्य का कारण बताया था।

सूत्र ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष पूनिया का खेमा राजे द्वारा खुद को पार्टी से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिशों से भी नाराज है। शाह की जयपुर यात्रा से ठीक पहले राजे ने चार दिन की देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान वे वहां भी गई जहां उपचुनावों में भाजपा को करारी हार मिली। यात्रा के दौरान राजे ने उन नेताओं और परिजन से मुलाकात की, जिन्होंने कोविड के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं पिछले साल राजे के समर्थकों ने उनके नाम पर ही एक समानांतर मंच वसुंधरा राजे समर्थक मंच भी स्थापित किया था। हाल ही में राजस्थान में कई जगह पूनिया भगाओ वाले पोस्टर भी दिखाई दिए थे। हालांकि राजे ने खुद इस तरह के काम करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी।

प्रदेश की राजनीति में नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे अपने समर्थकों की दो टीमें भी तैयार कर चुकी हैं, जो लंबे समय से राज्य के सभी 33 जिलों और 200 विधानसभा सीटों पर कार्य कर रही है। इनमें एक टीम वसुंधरा और दूसरी वसुंधरा समर्थक मंच है। यह दोनों टीमें सभी क्षेत्रों में वसुंधरा राजे के प्रचार और उनके लिए अभी से चुनाव कार्यों में जुट गई है। इन टीमों में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा समेत सभी स्तर पर मोर्चा बनाए जा चुके हैं। इन टीमों के गठन और कार्यों से भाजपा में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल कई नेताओं को खासी आपत्ति भी है कि भाजपा संगठन के साथ ही कैसे वसुंधरा राजे समर्थन में अलग से संगठन काम कर रहे हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

शाह ने पूनिया और राजे की प्रशंसा की

अमित शाह ने बैठक में राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कार्यों और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू की गईं योजनाओं की जमकर तारीफ की थी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि शाह की दोनों नेताओं की तारीफ करने से स्पष्ट संदेश जाता है कि वे राज्य के पार्टी नेताओं के बीच मतभेदों को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। उनका सीधा संदेश है कि सभी नेता एकजुट होकर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं। शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि पूनिया संगठन को चलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वसुंधरा का जनता के बीच अपना एक मजबूत जनाधार है और राज्य में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी का एक साथ होना आवश्यक है।

काठ की हांडी चढ़ाने में जुटे नीतीश कुमार

ऐसा लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा का समर्पण कर दिया है और भाजपा की मदद से बिहार का मुख्यमंत्री बन कर संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन तीन-चार साल की चुप्पी और सबकुछ बरदाश्त करने के बाद एक बार फिर उनकी महत्वाकांक्षा जोर मार रही है और वे फिर काठ की हांडी चढ़ाने में लग गए हैं। एक समय था, जब उन्होंने राजद और कांग्रेस के साथ मिल कर बिहार में भाजपा को निर्णायक रूप से हराया था। उस समय वे पूरे देश में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देखे जा रहे थे। विपक्ष की ओर से मोदी से मुकाबले का स्वाभाविक चेहरा नीतीश का माना जा रहा था।

वे पिछड़ी जाति से आते हैं, डिग्री का भी संकट नहीं है, पढ़-लिख कर इंजीनियर बने थे और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हैं और सामाजिक न्याय यानी मंडल की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा हैं। पर एक दिन अचानक उन्होंने विपक्ष का साथ छोड़कर भाजपा के साथ सुरक्षित खोल में पहुंच गए। जब जुलाई 2017 में वे फिर से भाजपा के खेमे में लौटे तब मान लिया गया कि अखिल भारतीय नेता बनने की इच्छा उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन जाति जनगणना और बिहार के विशेष दर्जे की मांग फिर शुरू करके उन्होंने अपनी पुरानी राजनीति को रिवाइव किया है।

नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वे बिहार में जातीय जनगणना होगी और बिहार सरकार उसका खर्च उठाएगी। यह बहुत बड़ी बात है और भाजपा को मुश्किल में डालने वाली है। ध्यान रहे भाजपा जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे उसका हिंदुत्ववादी राजनीति का ढांचा बिखर सकता है। नीतीश बिहार की सभी पार्टियों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिले और जाति जनगणना कराने की अपील की। उसके बाद उन्होंने छह महीने तक इंतजार किया और जब केंद्र की ओर से इस पर फैसला नहीं किया गया तो उन्होंने जाति जनगणना का एकतरफा ऐलान कर दिया। इसी तरह कई बरस तक बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने के बाद नीतीश पिछले चार साल से इस पर चुप्पी साधे हुए थे। ध्यान रहे उन्होंने 2015 का विधानसभा चुनाव विशेष राज्य के दर्जे पर लड़ा था लेकिन 2017 से इस पर चुप थे। अब उनकी सरकार ने नीति आयोग को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के जो पैमाने तय किए गए हैं बिहार उन सब पर फिट बैठता है। देखना दिलचस्प है कि नीतीश कुमार इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाते हैं।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वह इसे लेकर शांत थे। अब एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और कहा कि यह बिहार की जरूरत है। राज्य की उपमुख्यमंत्री और बिहार की नेता रेनू देवी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मांगने का कोई अर्थ नहीं है और इस दावे को लेकर कोई विस्तृत जानकारी भी नहीं है। उनके इस बयान पर नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए ही निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि यदि राज्य में कोई स्पेशल स्टेटस की डिमांड का विरोध करता है तो संभव है कि उसे मुद्दे की जानकारी ही न हो। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग 2007 से ही उठाते रहे हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले यह मांग और तेज हो जाती है।

फिलहाल पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के अलावा उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ही यह दर्जा प्राप्त है। ये सभी राज्य सीमांत इलाके हैं और पहाड़ी हैं। 1969 में योजना आयोग की सिफारिश पर इन राज्यों को यह दर्जा मिला था। अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य पिछड़ेपन के आधार पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के दौरान कांग्रेस सरकार ने उसे विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। इसके चलते वह भी अक्सर ऐसी मांग करता रहा है, लेकिन मोदी सरकार में इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार को मानव विकास सूचकांक और ग्रोथ रेट के मामले में निचले पायदान पर रखा गया है। इस पर नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा दी है। प्रतिव्यक्ति आय में भी बिहार काफी पीछे है। देशभर में यह 1,34,432 है, जबकि बिहार में 50,735 ही है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की आधी से ज्यादा आबादी यानी 51.91 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। स्कूल ड्रॉपआउट, कुपोषण, मातृत्व पोषण जैसे मानकों में भी बिहार काफी पीछे है।

भाजपा को दबाव में रखने के लिए अक्सर नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते रहे हैं। भले ही भाजपा राज्य में सीनियर पार्टनर है, लेकिन अब तक वह नीतीश के ही पीछे चलती रही है। भाजपा की ओर से तारकिशोर प्रसाद और रेनू देवी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन वह अब तक कोई मांग करते नहीं दिखे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि भले ही भाजपा राज्य में मजबूत होकर उभरी है, लेकिन अब भी वह चुनावी समर में अकेले उतरने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वह गठबंधन में अपनी बढ़त को खोना नहीं चाहते।

● **विनोद बक्सरी**

दर्जा मिला तो केंद्र से मिलेगी 90 फीसदी फंडिंग

यदि बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देती है तो फिर केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग में उसकी हिस्सेदारी 90 फीसदी की होगी, जबकि राज्य सरकार को 10 प्रतिशत खर्च ही उठाना होगा। पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है, लेकिन अन्य किसी मैदानी राज्य को ऐसा कोई स्टेटस नहीं मिला है। गैर विशेष राज्यों में चलने वाली केंद्रीय स्कीमों की फंडिंग में केंद्र और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात 60:40 या फिर 80:20 रहता है। संविधान में किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन दुर्गम पहाड़ी राज्यों, ऐतिहासिक कारणों, अधिक आदिवासी आबादी अथवा कम जनसंख्या, रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन जैसे कारणों के आधार पर यह स्टेटस दिया जाता रहा है।

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress- and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

5 साल की सुस्ती पड़ेगी भारी

सड़क पर जूझने के लिए मशहूर रहा समाजवादी पार्टी का काडर अभी तक इस रहस्य को सुलझाने में लगा है कि आखिर अखिलेश यादव पांच साल तक हाथ पर हाथ धरे घर में ही क्यों बैठे रहें? सपा काडर के मन में ऐसे बहुतेरे सवाल हैं। करीब दर्जनभर छोटे दलों के साथ गठबंधन हो सकने की स्थिति में भी किंतु-परंतु है। सपा का जो सांगठनिक किला दिख रहा है- कम से कम उप्र विधानसभा चुनाव के लिहाज से दरका हुआ माना जा सकता है। ये दूसरी बात है कि अब पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री का एकछत्र नियंत्रण है। पार्टी में दूर-दूर तक उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं। ना घर के अंदर और ना बाहर से। मगर सवाल तो यही है कि क्या इससे अखिलेश का उप्र संकल्प पूरा हो पाएगा?

सपा के पुराने काडर से बात करिए तो वह दबे मन स्वीकार कर लेता है कि अखिलेश ने सक्रियता बढ़ाने में देर की। विपक्ष में पांच साल का लंबा वक्त बिताने के बावजूद उन्होंने पराजयों से कुछ नहीं सीखा और भविष्य की बेहतर तैयारियां नहीं कीं। उन्होंने सबसे ज्यादा ऊर्जा पार्टी पर नियंत्रण में ही लगाई। अन्य चीजों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया। ठीकठाक काम करने के बावजूद जिन वजहों से सत्ता से बाहर हुए उसे दुरुस्त नहीं कर पाए। दुरुस्त करने निकले भी तो चुनाव सिर पर आने के बाद। जो प्रभावित करने की बजाय चुनावी स्टंट नजर आता है। आज की तारीख में सपा पूरी तरह से अखिलेश की पार्टी है, मगर इस हालत में नहीं कि उप्र में मोदी-योगी-मौर्या की मजबूत तिकड़ी को पीट सके।

बराबर की जंग के लिए अखिलेश को सहयोगियों की जरूरत है। हालांकि उनकी दुर्भाग्यगाथा का निकट अंत नहीं दिखता। राहुल गांधी की तरह वे भी गलतियां करते दिख रहे हैं, जबकि उनकी राजनीति बिल्कुल अलग थी। छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन, छोटी सभाओं की जगह टीमटाम वाले रोड शो, मंदिरों में जाकर माथे टेकना, धर्माचार्यों से मुलाकात और ध्रुवीकरण को हवा देने की कोशिश। अखिलेश भी ब्राह्मणों को पुचकार रहे हैं, गोया उप्र के सियासत की चाभी सिर्फ जनेऊधारियों के पास हो। ऐसी तमाम कोशिशें फायदा पहुंचाने की बजाय अखिलेश की राजनीतिक सेहत के लिए हानिकारक नजर आ रही है।

मदिरों में सिर नवाने और धर्माचार्यों से मुलाकात में अखिलेश को सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का कोपभाजन बनने से ज्यादा कुछ नहीं हासिल हुआ। भाजपा की नकल में छोटे दलों का साथ लेने की कोशिश में वे अपनी हार की सही वजहों को भूल रहे। उन्हें शायद अपनी उन यात्राओं के बारे में भी ठीक से याद नहीं जिसकी वजह से उन्होंने अकेले उप्र के चुनाव की पूरी फिजा ही बदल दी थी और बाद में मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल जो अखिलेश नजर आ रहे हैं वो चुनाव पूर्व सरेंडर मुद्रा में दिख रहे हैं। सपा के राजनीतिक दांत अब धारदार नहीं दिखते। समझ ही नहीं आता कि आखिर अखिलेश ने पांच साल तक किया क्या? उन्होंने अपनी पराजयों पर मंथन किया भी या नहीं। यह ठीक है कि भाजपा ने छोटे-छोटे दलों का सहयोग लेकर उन्हें सत्ता से बेदखल किया। मगर वे रणनीतियां तो अखिलेश के खिलाफ भाजपा के अपने मंथन से निकली थीं। रणनीति के लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भांप ही नहीं पाए। रणनीति थी- अन्य पिछड़ी जातियों में राजनीतिक वर्चस्व की इच्छा को जगा देना। सपा के खिलाफ भाजपा यह संदेश पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब रही कि अखिलेश और सपा ओबीसी नहीं सिर्फ यादवों की पार्टी और नेता हैं इसके साथ ही एंटी हिंदू हैं। जो अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पॉपुलर धारा में कहें तो देश विरोधी भी।

सपा के टिकट वितरण, मुस्लिम नुमाइंदगी से लेकर सांगठनिक ढांचे में गैर यादव जातियों की हिस्सेदारी जैसे उदाहरणों को निकालकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। अब यह सही है या गलत मगर सपा सरकार में यादव और मुस्लिम गठजोड़ की ताकत को खारिज नहीं किया जा सकता। सांगठनिक प्रोत्साहन से जमीन कब्जाने और उत्पीड़न की बहुत सारी शिकायतें सामने आईं। स्वाभाविक है कि उत्पीड़न झेलने वाली ज्यादातर पीड़ित दबंग जातियों से नहीं रहे होंगे। वे ओबीसी और दलित जातियों से ही होंगे। उधर, ओबीसी की जो गैर यादव जातियां पिछले कुछ सालों में राजनीतिक रूप से ताकतवर बनीं उन्होंने यादवों को ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में लिया। एंटी यादव नैरेटिव ने इसे और मजबूती प्रदान की। इस तर्क को प्रसारित करना ज्यादा आसान है कि जब 10 से 12 प्रतिशत यादवों का वोट लेकर अखिलेश समूचे ओबीसी समुदाय को पीछे चलने पर मजबूर कर सकते हैं तो फिर ओबीसी में शामिल दूसरी मजबूत जातियां भी यही क्यों ना करें? ऐसा नहीं है कि सपा चीफ इन चीजों पर सक्रिय नहीं हुए। बेशक हुए, मगर समय हाथ से निकल चुका है। अखिलेश ने सांगठनिक स्तर पर स्थानीय इकाइयों में फेरबदल किया। बड़े पैमाने पर स्थानीय इकाइयों की कमान गैरयादव नेताओं को दी गई है। अभी हाल ही में प्रदेश और केंद्रीय स्तर पर भी फेरबदल कर गैरयादव नेतृत्व को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। चुनावी सीजन में हुए फेरबदल पिछले एक दशक से जारी एंटी यादव नैरेटिव को कितना कमजोर करेंगे यह समझना मुश्किल नहीं है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

मुसलमान की मजबूरी है सपा

उधर अयोध्या पर फैसला, नागरिकता कानून, धारा 370, तीन तलाक जैसे मुद्दे हमेशा से मुसलामनों को भावुक करने वाले रहे हैं। सपा की सियासत को मजबूत बनाने में मुसलमानों का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। लेकिन तमाम मुद्दों पर अखिलेश चुप रहे, भाजपा की मदद की या पीछे हट गए। नागरिकता कानून के खिलाफ उप्र में प्रियंका की सक्रियता के बाद तो सवाल भी उठे कि सपा आखिर है कहां। यहां तक कि जिस आजम खान के चेहरे को पार्टी पोस्टर पर लगाकर मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है उनके लिए भी कांग्रेस मुद्दे उठाती नजर आ रही थी। यह साफ है कि मुसलमान पूरी तरह से सपा के साथ हैं, मगर सिर्फ इसलिए हैं कि भाजपा के खिलाफ उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं है। जबकि सपा के साथ जाने में मुस्लिम बड़ी कीमत चुका रहे हैं जिसकी भरपाई उन्हें अगले कई सालों तक करनी होगी यह तय है। मगर राजनीति तो यही है। कई बार हासिल करने से ज्यादा खुशी गंवाने में होती है। इस बार मुसलमान सपा का साथ गंवा कर खुश होना चाहते हैं। अखिलेश भले ही कितने ट्वीट कर लें- सपा ना तो किसान आंदोलन क्लेम करने की स्थिति में है और ना ही महंगाई को लेकर भाजपा को घेरने की अवस्था में। इन मुद्दों पर रालोद और कांग्रेस की अपील ज्यादा प्रभावी है।

दोस्ती का नया अध्याय

भारत-रूस के रिश्ते करीब-करीब एक जैसे

भारत-रूस पुराने सहयोगी रहे हैं। राष्ट्रीय हितों की एकरूपता उन्हें फिर से संबंधों को गहराने के लिए प्रेरित कर रही है। तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत-रूस संबंध काफी मधुर रहे हैं। पिछले कुछ दशक में दुनिया कई बुनियादी बदलावों और विभिन्न तरह के भू-राजनीतिक समीकरणों का गवाह बनी है, लेकिन भारत-रूस के रिश्ते करीब-करीब एक जैसे बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हो रही है।

हाल में संपन्न भारत-रूस शिखर बैठक ने दोनों देशों की दोस्ती का नायाब उदाहरण पेश किया। इसमें भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खासतौर से दिल्ली आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में उनकी अगुवाई की। दिनभर चली बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भारत-रूस दोस्ती को अनूठी और एक-दूसरे की संवेदनाओं का ध्यान रखने वाली बताया, वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बड़ी शक्ति और विश्वसनीय दोस्त करार दिया।

बैठकों में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों, अफगानिस्तान, आतंकवाद, एशिया प्रशांत और कोरोना महामारी की चुनौतियों से लेकर अंतरिक्ष एवं विज्ञान के क्षेत्र में नए सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इससे पहले दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अलग-अलग बैठकें हुईं। उसके बाद इन चारों की टू-प्लस-टू व्यवस्था के तहत पहली संयुक्त बैठक हुई। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और चीन के साथ रूस के लगातार मजबूत होते सामंजस्य के बावजूद मोदी और पुतिन ने इस शिखर बैठक के जरिए वैश्विक स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक संकेत दिया।

शीत युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। पुराने दोस्त सामान्य दोस्त रह गए हैं और पुराने प्रतिद्वंद्वी भी कई मामलों में अच्छे मित्र बन गए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति तक रूस भारत का सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहा। शीत युद्धोत्तर काल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कोरोना कालखंड के पिछले दो वर्षों में राष्ट्रपति पुतिन की यह दूसरी विदेश यात्रा थी। जून 2021 में वह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के साथ शिखर बैठक करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। उनका भारत आना इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्होंने चीन का भी अपना दौरा कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया था। साफ है कि भारत आकर उन्होंने चीन को भी संदेश दिया। हाल के दशकों में अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध काफी तेजी से गहरे हुए हैं। क्वाड सहित अनेक बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से इसमें काफी गहराई आई है। क्वाड का सदस्य होने के बाद भी भारत ने रूस से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाकर यही साबित किया कि उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है।

वर्तमान में अमेरिका-रूस के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। यूक्रेन के सवाल पर वे और भी खराब हो सकते हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत-रूस संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत-अमेरिका के गहराते संबंधों में अंतर्निहित कारकों को रूस भी समझ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का वर्तमान दौरा इस सच्चाई को रेखांकित कर रहा है। अमेरिका-रूस के बीच जटिल होते संबंधों के बावजूद भारत-रूस के संबंधों की गहराई मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलताओं में मील का पत्थर है।

2018 में भारत-रूस ने एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर समझौता किया था। इसी प्रणाली को रूस से लेने के कारण अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर तमाम प्रतिबंध लगाए, पर भारत के मामले में वह नरमी बरतता दिख रहा है। रूस अब इस प्रणाली को भारत को सौंपने वाला है। चीन एस-400 मिसाइल प्रणाली को भारत को देने से खफा है। उसे लगता है कि भारत इसे चीन की सीमा के पास तैनात करेगा। इस प्रणाली को हासिल करने बाद भारत की सैन्य ताकत बढ़ जाएगी। भारत 400 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जबाव देने में और अधिक ताकत प्राप्त कर लेगा। यह स्पष्ट है कि इस मामले में रूस ने चीन की चिंता की परवाह नहीं की।

अफगानिस्तान के मामले में पहले रूस-भारत के बीच थोड़े मतभेद थे, लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद की हरकतों ने रूस को सशंकित किया है। पिछले महीने नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की शिखर बैठक में भाग लेकर रूस ने इस मामले पर भारत के साथ अपने हितों की एकरूपता को रेखांकित किया। तालिबान के शासन में आने के कारण अफगानिस्तान में अव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। रूस और भारत के लिए यह सामूहिक चिंता है। वैसे तो रूस-चीन के बीच पिछले कई वर्षों से दोस्ती रही है, लेकिन सुदूर पूर्व साइबेरिया के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता बनी रहेगी। हालांकि चीन ने रूस के साथ इस क्षेत्र में सीमा समझौता कर लिया है, पर रूस इससे चिंतित है कि विशाल भू-भाग होते हुए भी यहां रूसी जनसंख्या एक करोड़ से भी कम है। रूस के ऊर्जा समृद्ध इस पूर्वी इलाकों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ब्लादिवोस्तक में भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति की घोषणा करते हुए इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं के लिए एक अरब डालर की लाइन आफ क्रेडिट की घोषणा की थी। इन परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। पुतिन के वर्तमान दौरे में भी इस पर अनेक सहमतियां बनी हैं।

● **कुमार विनोद**

ANU SALES CORPORATION

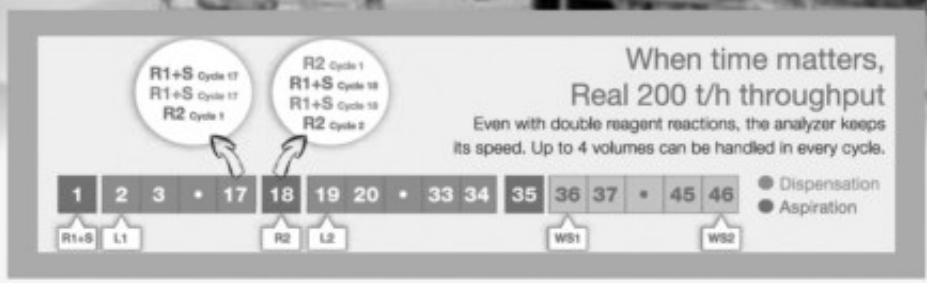

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

बेबस

राजमार्ग पर सड़क किनारे लगे एक मील के पत्थर के करीब बैठी शून्य में ताकती वृद्धा के हवाले उसकी पोती की और कहा, 'ये ले काकी, तेरी पोती! काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार उठाईगीर पकड़ में आ ही गए। अच्छा किया कि मोबाइल से तुरंत सौ नंबर पर फोन करके सही से सूचना दे दी। क्षेत्रीय गश्ती दल तुरंत पीछे लगा, तभी पकड़े गए। एक बार नजरों से ओझल हो जाते तो हम लकीर पीटते रह जाते।'

'यह बुढ़िया आपको दिल से आशीर्वाद देती है, दारोगा बाबू! राम जी गरीबों की गुहार सुनने वाले आप जैसे इंसान को सुखी रखें।'

'पर काकी! शौचालय बनवाने के लिए सबको सरकारी अनुदान मिला था तो शौचालय बनवाना था। इस तरह सड़क के किनारे गड्ढों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर सरकारी अनुदान खा पीकर हजम कर लिया?'

'हम अनपढ़-गवार, न जान-पहचान, न घर में मरद-मानुष, हमें कहां पैसे मिले शौचालय बनवाने के। ऊ तो बड़कन लोग...'

'सार्वजनिक शौचालय भी तो बने हैं। उसमें जा सकती हो ना।'

'अरे बाबू! ऊ बड़ा गंदा रहत है।'

'हद है काकी! अब हम क्या पुलिस की नौकरी छोड़ कर भंगी की नौकरी पकड़ लें? सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाना सरकार का काम है, पर उसके बाद गंदा रहे तो इसमें भी सरकार की गलती है? शौचालय इस्तेमाल करने के बाद ढंग से पानी-वानी डालो, चंदा-वंदा करके उनकी साफ-सफाई करवाओ। सबकी सुरक्षा तो बनी रहेगी।

आज लड़की नहीं मिलती तो बस्ती के लोग सड़क रोक आंदोलन पर बैठ जाते। टायर जलाते, और पूरा राजमार्ग जाम कर देते, पुलिस-प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते, मुफ्त का बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता', पुलिस वाले झल्लाते हुए गाड़ी से निकल गए।

- नीना सिन्हा

फूलों का शहर

वीरान हुआ ख्वाबों का चमन,
मायूस जिंदगी का सफर।
उदासियों से दूर ले चल मुझे,
हो जहां फूलों का शहर।
नयन मूंद बैठे हैं मुझ से,
कल तक थे जो मेरे अपने।
साथ छोड़ गए जो हम से,
याद आकर रुलाते सपने।
प्यार आंधियों का सुनामी,
ढाह के गया हम पे कहर।
उदासियों से दूर ले चल
मुझे हो जहां फूलों का शहर।
फूलों का शहर हसीन है,
जहां प्यार के दो दिल मिलते।
महकती खुशबू के दामन में,
मुहब्बत के फूल हैं खिलते।
दिल लुटा देते है अपनों पे,
जिंदादिल होते हैं हमसफर।
उदासियों से दूर ले चल मुझे
हो जहां फूलों का शहर।
बदन होता है जहां शबाब,
निखरा सा शबनम की तरह।
नयनों से प्रेम मधु बन के,
महक जाता सरगम की तरह।
भौंरों की गुंजन हो मधुर,
फूलों से घिरा मेरा हो घर।
उदासियों से दूर ले चल मुझे
हो जहां फूलों का शहर।
शिकवा नहीं कोई शिकायत,
हैं करते भरोसा खुदपर।
खुश मजाज रहते दिल से,
उजला है जिन का अंबर।
ऐसे जहां में ले चल
हो न इंसान वहां कोई काफिर।
उदासियों से दूर ले चल मुझे
हो जहां फूलों का शहर।

- शिव सन्याल

नीम तले

कैसे हैं तुम्हारे बाबूजी? मां की उद्विग्नता साफ झलक रही थी आवाज में।

मां! डॉक्टर ने संभाल लिया है। अब धीरे-धीरे सांस ले रहे हैं। कई तरह की जांच के बाद डॉक्टर ने दवाई लिखी है।

गाँव में तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक थे!

मम्मी! मुझे मालूम नहीं था कि इस बार भी दिवाली में इतना अधिक वायु प्रदूषण होगा। लोगों ने न्यायालय और सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा दिया।

वे दिल्ली में स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बेटा। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हम वापस गांव जाएंगे।'

जी मम्मी, देखता हूं। दीपक बाबू ने मोबाइल ऑफ किया।

दीपक के कानों में पिताजी की अस्पष्ट आवाज गूंज रही थी, मुझे नीम तले ले चलो। सीने में बहुत दर्द हो रहा है।

बाबूजी गांव के घर के सामने खड़े नीम के पेड़ की बात कर रहे थे।

- निर्मल कुमार डे

विराट से कप्तानी छिनने के मायने

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप तक वनडे फॉर्मेट के पूर्णकालिक कप्तान बने रहेंगे। टी-20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को पहले ही टी-20 टीम का नया कप्तान बनाया जा चुका है। दरअसल, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने यूएई में खेले जा रहे आईपीएल के दूसरे चरण के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि वह टी-20 वर्ल्ड कप के बाद टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि जल्द ही विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से भी भारमुक्त किया जा सकता है। क्योंकि, टी-20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के समय विराट कोहली ने वर्कलोड को लेकर एक बड़ा पत्र सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था।

कहा जा रहा था कि बीसीसीआई की ओर से विराट कोहली पर कप्तानी छोड़ने को लेकर काफी दबाव बनाया गया था। हालांकि, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के आधिकारिक बयान के अनुसार, विराट कोहली खुद ही टी-20 टीम की कप्तानी नहीं करना चाहते थे। उनसे टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ने को नहीं कहा गया था। वैसे, विराट कोहली से वनडे की कप्तानी वापस लिए जाने के बाद अब वे केवल टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के लिए कप्तानी करेंगे। लेकिन, यहां भी संभावना बनी हुई है कि अगर विराट कोहली थोड़ा सा भी अड़ियल रवैया दिखाते हैं, तो टेस्ट की कप्तानी से भी हाथ धो बैठेंगे। खैर, ऐसा होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन, इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि विराट कोहली जैसों से कप्तानी क्यों छीनी जाती है?

विराट कोहली लंबे समय तक टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम नहीं किया। लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान विराट कोहली ने कोई रिकॉर्ड्स अपने नाम नहीं किए। लेकिन, ये रिकॉर्ड एक टीम के तौर पर टीम इंडिया के किसी काम के नहीं थे। आसान शब्दों में कहा जाए, तो विराट कोहली अपनी कप्तानी के कार्यकाल में एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के तौर पर काफी मजबूत हुए। लेकिन, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठी। एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी परफॉर्मेंस के साथ ही साथी खिलाड़ियों पर भी काम करे, लेकिन विराट कोहली इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ऐसा होता है कि कई बार टीम नतीजे देती रहती है, तो कप्तान की गलतियां छिप जाती हैं। लेकिन, बीते कुछ समय में कोई भी चीज विराट कोहली के पक्ष में नहीं थी। इस दौरान विराट कोहली और टीम के बीच तालमेल में कमी भी कई बार सामने आई। जिसकी वजह से कई टूर्नामेंट्स में पूरी टीम बुरी तरह से फ्लॉप रही। हालिया हुआ टी-20 वर्ल्ड कप इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है।

एक कप्तान के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको हर खिलाड़ी को साथ लेकर चलना है। टीम के कप्तान के रूप में कोई शख्स अपना ईगो दूसरों पर नहीं थोप सकता है। विराट कोहली भी टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हो गए हैं। हालांकि, टीम इंडिया में अभी भी उनसे सीनियर खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों की अपनी विशेषताएं हैं। कई मौकों पर विराट कोहली की ओर से रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा समेत अन्य साथी खिलाड़ियों के लिए गलत अप्रोच रखी गई। जो कहीं न कहीं पूरी तरह से उनके खिलाफ गई। एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली का व्यवहार हर खिलाड़ी के साथ एक जैसा होना चाहिए था। लेकिन, वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते थे। जिसकी वजह से वो पूरी टीम इंडिया के विश्वास पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। इसी साल हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का ठीकरा दो सीनियर खिलाड़ियों पर थोप दिया गया।

बीते दो सालों से विराट कोहली एक भी शतक लगाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। जिसकी वजह से उनके और टीम के परफॉर्मेंस में एक बड़ा गैप बन गया था। सबसे अहम बात ये भी रही कि ये गैप कम होने की बजाय हर सीरीज के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इस परफॉर्मेंस गैप का असर कहीं न कहीं टीम पर भी पड़ता है। जिसकी वजह से विराट कोहली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे थे। उदाहरण के तौर पर जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस भी इसी तरह कमजोर होने लगी, तो बीसीसीआई की ओर से उन्हें इशारा दे दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने पहले अपनी परफॉर्मेंस सुधारने पर ध्यान दिया। लेकिन, सफलता न मिलने पर धीरे-धीरे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी। हालांकि, इस दौरान वह विकेटकीपर और फिनिशर के तौर पर टीम के साथ जुड़े रहे। ऐसे कई बड़े मुकाबले हुए जिनमें महेंद्र सिंह धोनी से एक कप्तानी पारी खेलनी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन, वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। जबकि, उनकी टीम का परफॉर्मेंस उनसे अच्छा रहा। कप्तान और टीम के परफॉर्मेंस में आने वाला ये गैप विराट कोहली पर भी लागू होता है।

● आशीष नेमा

खेमे का हिस्सा बन जाना

विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर बुरी तरह से खेमेबाजी का शिकार हो गए थे। विराट कोहली की टीम इंडिया में कुछ खास खिलाड़ियों पर निर्भरता बढ़ गई थी। कोई या कैसी भी परिस्थिति हो, इन खिलाड़ियों को आसानी से प्लेइंग इलेवन में जगह मिल जाती थी। लेकिन, अपनी परफॉर्मेंस को टीम इंडिया में शामिल होने के लिए इंप्रूव कर रहे और नतीजे देने वाले खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन या टीम स्क्वाड से ही बाहर रख दिया जाता था। विराट कोहली को अपने करीबी साथी खिलाड़ियों और पूर्व कोच रवि शास्त्री की पसंद के खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में लेने के लिए जाना जाने लगा। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया में रविचंद्रन अश्विन को चारों मैच में बाहर रखा गया। कुलदीप यादव सरीखे युवा चाइना मैन बॉलर को बेंच पर बैठाए रखा गया। 2019 के वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने गए मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इस्तीफा देने के साथ ही बीसीसीआई चयन समिति पर थ्रीडी चश्मे वाला तंज कसा था। आसान शब्दों में कहा जाए, तो आईपीएल का असर टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन और स्क्वाड चयन में भी नजर आने लगा था।

हरनाज बनीं मिस यूनिवर्स

21 साल बाद भारत के नाम यह खिताब

मिस यूनिवर्स 2021 का ताज भारत की हरनाज संधू ने अपने नाम कर लिया है। इजराइल में हुई इस प्रतियोगिता के प्रीलिमिनरी राउंड में 75 से ज्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली युवतियों ने हिस्सा लिया था। टॉप 3 में साउथ अफ्रीका और पराग्वे की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए हरनाज संधू ने ब्रह्माण्ड सुंदरी के ताज पर अपना नाम लिख डाला। खास बात ये है कि हरनाज से पहले केवल दो भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स बनी हैं। भारत ने इससे 21 साल पहले इस खिताब पर कब्जा किया था। 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था।

फाइनल राउंड में पॉजिटिव आंसर ने दिलाई जीत

जब हरनाज से पूछा गया- आज के दबावों से निपटने के लिए युवा महिलाओं को आप क्या सलाह देंगी? तो इस सवाल पर हरनाज ने जवाब दिया, आज का युवा जिस सबसे बड़े दबाव का सामना कर रहा है, वह है खुद पर विश्वास करने का। यह जानना कि आप यूनीक हैं, आपको सुंदर बनाता है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद करें और दुनियाभर में हो रही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करें। बाहर निकलें, अपने लिए बोलें, क्योंकि आप अपनी लाइफ की लीडर हैं। आप खुद अपनी आवाज हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और इसलिए मैं आज यहां खड़ी हूं। मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन जीतने के बाद हरनाज काफी खुश नजर आईं। हंसते हुए हरनाज चक दे फट्टे इंडिया... चक दे फट्टे कहती दिखीं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद होस्ट स्टीव हार्वे ने संधू से उनके पसंदीदा जानवर के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्लियां बहुत पसंद है। भारत की हरनाज संधू ने तीन घंटे चली लाइव प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने से पहले कई राउंड पार किए।

तनिषा मुखर्जी ने पहली बार एक मुस्लिम लड़की का रोल निभाया

हालिया रिलीज फिल्म कोड नेम अब्दुल में तनिषा मुखर्जी ने लीड रोल निभाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में तनिषा ने अपने कैरेक्टर की खासियत सहित, एग्स फ्रीजिंग आदि के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए पहली बार एक मुस्लिम लड़की का रोल निभाया है। तनिषा कहती हैं- फिल्म में मैं सलमा का किरदार निभा रही हूं। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत इनोसेंट है। मेरे लिए इस रोल को प्ले करना काफी इंटरेस्टिंग रहा। यह एक स्ट्रांग डिक्टेटिव की तरह का रोल है। इस फिल्म के जरिए मैंने पहली बार एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया है। सलमा मेन कैरेक्टर तारिक की सिस्टर इन लॉ है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि सलमा को लोग कैसे किडनैप करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कैसे टॉर्चर करते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लंबे समय तक पर्दे से दूर रहने के सवाल पर तनिषा ने कहा- मैं पर्दे से दूर नहीं रही हूं। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म की रिलीज डेट में वक्त लगता है, जबकि हम तो काम करते रहते हैं। अभी दो साल से कोविड-19 आ गया। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया है। लेकिन यह जो गैप आया है, वो रिलीज डेट टलने की वजह से आया है। मैंने आखिरी फिल्म अन्ना की थी, जो स्क्रीन पर रिलीज हुई थी।

22 साल के करियर में सिर्फ 1 हिट फिल्म दे पाए डिनो मोरिया

बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया को फिल्म राज से बेहद कामयाबी मिली थी। डिनो ने साल 1999 में आई फिल्म प्यार में कभी-कभी से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्मों में आने से पहले डिनो साइंस फिक्शन सीरियल कैप्टन व्योम में काम कर चुके हैं। डिनो ने पैसों और शौक के लिए मॉडलिंग करनी शुरू की थी। जब वो एक फैशन कंपनी के लिए मॉडलिंग किया करते थे, तब उन्हें नोटिस किया गया था।

मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। डिनो ने फिल्मों और विज्ञापन के जरिए अच्छी खासी कमाई की है। बता दें बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के बाद डिनो ने अपनी रेस्टोरेंट की चेन खोल ली है। इनका क्रेप स्टेशन रेस्टोरेंट पूरे भारत में काफी फेमस है। डिनो की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म कंदुकौंदैन में काम किया था। साल 2002 में डिनो को विक्रम भट्ट की फिल्म राज मिली और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद उनकी झोली में ढेर सारी फिल्में आईं, लेकिन वो सफल नहीं हो सकीं। फिल्मों में कामयाबी ना मिलने पर हाल ही में डिनो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 15 फिल्मों में एक्टिंग करने के बावजूद, मैं कभी भी एक एक्टिंग स्कूल नहीं गया था।

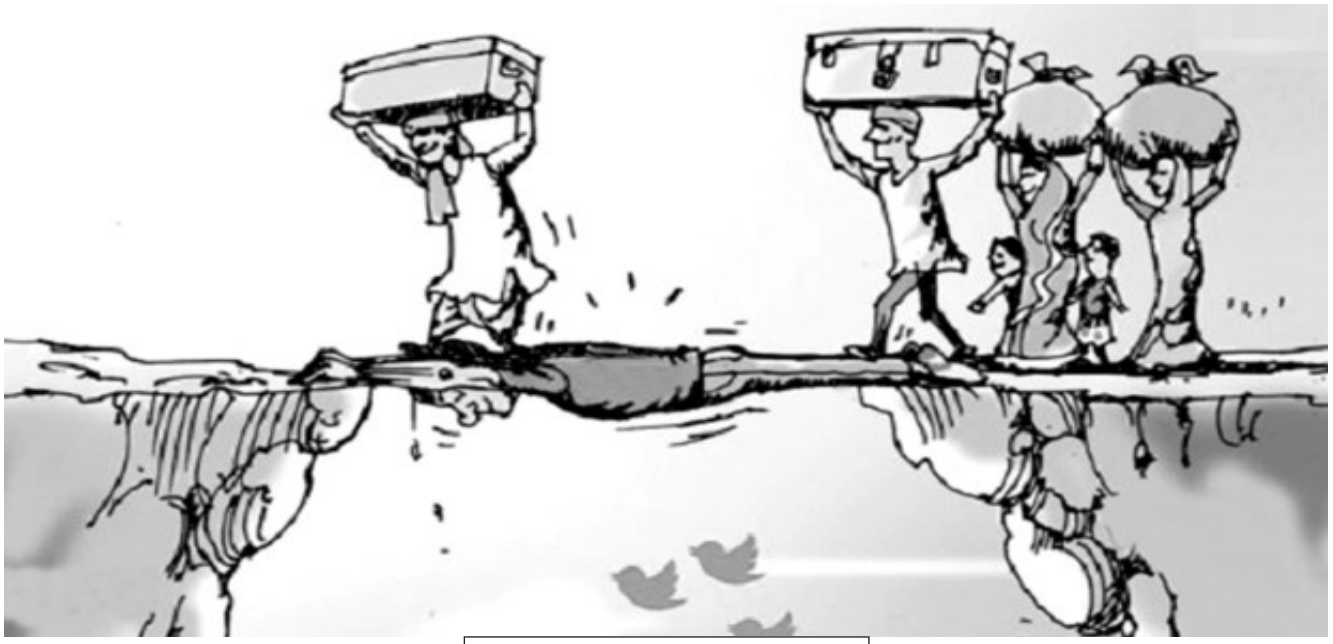

सावन के अंधे

सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। यह कहावत आज-कल से नहीं प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस कहावत के पद-चिन्हों पर एक-दो नहीं, हमारे जैसे लाखों-करोड़ों लोग चल रहे हैं। हम सभी ने अपनी आंखों पर मजबूत पट्‌टी बांध रखी है। इसलिए हमें अपनी ओर से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हमें आप उनका पिछलग्गू कहकर अपमानित मत कीजिए, हम तो सच्चे अनुगामी हैं, सद्‌भक्त हैं।

सद्‌भक्त वह होता है, जो अपनी सोच का समर्पण अपने आराध्य को कर देता है। हमारे कुछ विरोधी तत्व यह भी कह सकते हैं, कि हमारी बुद्धि दिवालिया हो गई है। अब आप कुछ भी कहें- चमचा कहें, अंध भक्त कहें अथवा दीवाना कहें। जो भी कहें, कह सकते हैं। पर हम तो अपने विवेक और चमड़े की दोनों प्रकार की आंखें उनके कारण बंद कर चुके हैं। यदि आंखों के कोई और भी प्रकार होते हों, तो भी वे सब उनके लिए समर्पित हैं। जैसे प्रेम दीवानी मीराबाई कृष्ण भक्ति में दीवानी हो गई थी, हमारा दीवानापन किसी भी अर्थ में उससे कम नहीं है। 'मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।'

यदि हमारे आराध्य अपने मुख कमल से कुछ भी बाहर निकालकर वमन कर देते हैं, और कुछ अंतराल के बाद किसी स्वार्थवश उसे पुन: अपने मुख कमल से उदरस्थ भी कर लेते हैं, तो भी हम उनके इस प्रशंसनीय कार्य की सराहना ही करते थे, करते हैं और करते भी रहेंगे। हिंदी सहित्य वाले भले मुहावरे की भाषा में इसे थूककर चाटना कहें, तो कहते रहें, हमारी बला से। हम तो अपनी आंखों पर पट्‌टी बांधे हुए अपनी जुबां से इसे विवेक का सही इस्तेमाल करना ही कहेंगे।

यदि हमारे आराध्य अपने मुख कमल से कुछ भी बाहर निकालकर वमन कर देते हैं, और कुछ अंतराल के बाद किसी स्वार्थवश उसे पुनः अपने मुख कमल से उदरस्थ भी कर लेते हैं, तो भी हम उनके इस प्रशंसनीय कार्य की सराहना ही करते थे, करते हैं और करते भी रहेंगे।

भला अपने आराध्य में हमें कोई दोष, दुर्गुण, धोखा और धुंध क्यों दिखाई दे? हम सभी यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 'जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं, उसके अवगुण हमें दिखाई नहीं देते।'

हमारा आराध्य भले ही कितना बड़ा चोर, ढोंगी, धोखेबाज, शोषक, अत्याचारी, जुमलेबाज, वचन का मिथ्याचारी, ड्रामेबाज, बहुरूपिया जैसे अनेक विशेषणों का धारक और वाहक हो, हमें आंखें बंद करके अनुगमन उसी का करना है। यदि धोखे से हमारी आंखों की पट्‌टी हट भी जाए, तो भी हमें आंखें बंद कर लेनी हैं। क्योंकि सद्‌भक्त के गुणों के अनुसार हमें अपने 'सतपथ' से क्षण मात्र के लिए भी विच्युत नहीं होना है।

आप और हम यह भी अच्छी तरह से जानते समझते हैं कि इस धरा धाम पर जिसने भी अपने चरण रखे हैं, वह 'जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व कीन्ह करतार' उक्ति के अनुसार शत-प्रतिशत श्रेष्ठ गुणवान नहीं है। और फिर इस कलयुग में जिसमें धर्म में भी पाप भरा हुआ हो, 100 में से 90 प्रतिशत पाप ही पाप बरस रहे हों, वहां सतयुग (100 में से 99 पुण्य) भला कैसे हो सकते हैं। 'काजर की कोठरी में कैसे हू सयानों जाय एक लीक काजर की लागि है पै लागि है।'

ऐसी हालत में भला आप ही बताइए कि जब हम सभी भक्तों ने अपनी बुद्धि को भी गिरवी रख दिया है, उसके साथ ही दिल भी दे दिया है। हम तो बस उनके ही प्राणों से चलते-फिरते हैं। हमारी समग्र जीवनी-शक्ति कर एकमात्र स्वामी, संवाहक, संचालक, परिचालक, परिपालक, पालक, मालिक सब वही हमारे आराध्य देव हैं। वे चाहें थूक कर चाटें, चाहे चाटकर पुनः थूकें। हम तो उनके थूके हुए को भी सहस्रों बार चाटने में सहयोग करने को अहर्निश तैयार हैं। भक्त-धर्म के साचे पालनकर्त्ता यदि कोई है, तो वर्तमान कलयुग में हम ही हैं।

हमें अपने इस महान समर्पण पर प्रचंड घमंड भी है। यदि सौ झूठों के सामने दस सत्यवादी भी आकर चुनौती दें, तो वह सत्य भी झूठ सिद्ध हो जाता है। आज हम उसी युग में जी रहे हैं। कलयुग में सत्य को, सांचे इंसान को और आराध्य-आराधक को ढूंढना, ठीक वैसे ही है, जैसे चील के घोंसले में मांस ढूंढना। मालूम है कि यह बहुमत का जमाना है। यहां बहुमत की जीत होती है, भले ही वह मूर्खों का हो, झूठों का हो, चोरों का हो, चरित्रहीनों का हो, जुमलेबाजों का हो। बहुमत के आगे अच्छे-अच्छे सांचाधारी भी पानी भरते हैं। हम ऐसे ही 'भगवानों' के सच्चे भक्त हैं। बोलो कलयुगी 'भगवान' की...।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट भारत के निर्माण की ओर... एक कदम

मप्र के 7 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन बन रहे स्मार्ट...